हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

16 फरवरी, 2009

खण्ड-1, अंक-6

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
★ Chandigarh ★

विषय सूची

सोमवार, 16 फरवरी, 2009

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6) 1
राजकीय महाविद्यालय सैक्टर-2, पंचकूला के विद्यार्थियों का अभिनंदन	(6) 27
अनुपस्थिति संबंधी सूचना	(6) 27
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(6) 27
विधान सभा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(6) 27
नई आबकारी नीति के संबंध में मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य	(6) 28
वर्ष 2009-2010 के लिए बजट	(6) 28
मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा	(6) 57
वर्ष 2009-2010 के लिए बजट अनुदानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारंभ)	(6) 57
बैठक का समय बढ़ाना	(6) 77
वर्ष 2009-2010 के लिए बजट अनुदानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारंभ)	(6) 78

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 16 फरवरी, 2009

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान सभा, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में अपराह्न 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the question hour.

New HUDA Sector at Pundri

*** 1187. Sh. Dinesh Kaushik :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to establish a new HUDA Sector at Pundri in near future?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : No Sir.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि पुण्डरी कस्बे का अभी कंट्रोल्ड एरिया प्लान नहीं हो पाया है परन्तु माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में सर्वे करने के लिए निर्देश दिए हैं। हम फिर भी फिजीब्लिटी देखने के लिए हुडा को बोल देंगे कि इसका डिमाण्ड सर्वे करवा लें ताकि वहां पर हुडा का सैक्टर काटने का कोई प्रावधान बन सके।

प्रो० दिनेश कौशिक : अध्यक्ष महोदय, वहां पर छोटी सी मण्डी टाऊनशिप के अलावा और कोई भी प्लाट खाली नहीं हैं सभी भरे हुए हैं। वहां के लोगों की बड़ी भारी डिमाण्ड है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र इसके बारे में कोई फैसला लिया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कन्सीड कर लिया है कि इसके लिए डिमाण्ड सर्वे करवायेंगे और उसके लिए माननीय सदस्य भी हमारी मदद करें। उस सर्वे में यह देखेंगे कि अगर वहां की जनता यह चाहती है कि हुडा का सैक्टर कटना चाहिए तो उसके बाद हुडा का सैक्टर काटने की उचित कार्यवाही भी की जायेगी।

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महम में भी जो हुडा का सैक्टर कटना विचाराधीन है उसकी क्या पोजीशन है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक पृथक प्रश्न है इसलिए इस प्रश्न की मेरे पास अभी हैंडी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य इस बारे में लिखकर भिजवा दें तो उसके बारे में सही जानकारी सूचित कर देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1167

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान सदन में मौजूद नहीं थे)

तारांकित प्रश्न संख्या 1216

(इस समय माननीय सदस्य श्री रामकिशन फौजी सदन में मौजूद नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया)

Construction of Building of Post Graduate Regional Centre

*** 1219. Smt. Anita Yadav :** Will the Education Minister be pleased to state:—

(a) whether the building of Post Graduate Regional Centre, Meerpur is under construction in District Rewari; if so, the amount spent till date on the construction work; and

(b) the time by which the construction work is likely to be completed?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes Sir, an amount of Rs. 653.30 Lacs has been spent upto 31.12.2008 on the construction work.

(b) The first phase of the construction work is likely to be completed by July, 2009.

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जब रेवाड़ी आये थे तो उस समय यह घोषणा की गई थी। मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद भी करती हूं कि उसका कार्य शुरू हो गया है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि अगले साल के लिए कितने पैसे का प्रावधान किया गया है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि यह सैंटर के.एल.पी. कालेज की रैंटिड प्रिमीसिस में तीन अक्तूबर से चल रहा है। हरियाणा सरकार ने दस करोड़ रुपये की ग्रान्ट-इन-ऐड महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी को इस कार्य के लिए दी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने दस करोड़ 55 लाख रुपये पी०डब्ल्यू० डी० (बी० एण्ड आर०) की रेवाड़ी ब्रान्च जिस महकमें के मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, को दिया गया है। जैसे ही पहले फेज की स्टेबिलाईजेशन हो जायेगी तो हम दूसरे फेज को उसके बाद बनायेंगे और जितने पैसे की आवश्यकता होगी हम उतना पैसा देने के लिए कटिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वायदा है उसको हम अवश्य पूरा करेंगे।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि इस रीजनल सैंटर का काम पिछले दस सालों से बन्द पड़ा था। पिछली सरकार की मेहरबानी रही कि इन्होंने इस कार्य को बन्द रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर लोगों की मांग को देखते हुए उस सैंटर के कार्य को शुरू करवाया है। जैसा कि माननीय मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बताया कि फेज 2 का कार्य पूरा करवाने के लिए सरकार ने अगले साल के लिए पैसे का प्रावधान कर दिया है। इस बारे में मेरी शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है इन्होंने मुझे बताया कि इस कार्य के लिए अगले साल के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस सैंटर का कार्य अवश्य पूरा किया जायेगा।

Declaration of Sirsa-Ellenabad Road as State Highway

*** 1091 Dr. Sushil Indora :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether the Sirsa-Ellenabad road has been declared state highway; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to widen or to reconstruct the said road?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sirsa-Ellanabad road is already part of State Highway No. 23. Improvement of this stretch is likely to be taken up during 2009-10.

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रोड्स को बनाने के बाद उसकी रिपेयर करने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के क्या कायदे हैं कि कितने साल के बाद उस सड़क की रिपेयर जरूरी है। क्या उन कायदे कानूनों के मुताबिक इस सड़क की रिपेयर हो रही है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो नार्मली यह होता है कि 3 साल के बाद हम सड़कों की मेन स्ट्रैंग्थनिंग का काम करते हैं। इनकी जो सड़क है उस पर स्कीम के हिसाब से करीब 25 करोड़ रुपया खर्च होना था। सी०आर०एफ० स्कीम के तहत केस भेजा गया था लेकिन किसी वजह से वहां मंजूर नहीं हो पाया। इस रोड पर कोई पोटहोल्स नहीं हैं। यह रोड सर्विसेबल है और इस रोड की हालत ज्यादा खराब नहीं है। फिर भी हम सी०आर०एफ० या किसी और स्कीम के तहत इस सड़क की स्ट्रैंग्थनिंग और वाइडनिंग का केस बना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इनका यह काम पूरा हो सके। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार इन्होंने सिरसा मिनी बाई पास के बारे में जिक्र किया था इसके बारे में आप काफी वाजिब थे कि इसका जवाब दें तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसका 4 लेन का कार्य धर्मपाल ठेकेदार को अलाट किया जा चुका है। मई, 2009 तक यह काम कर देंगे। उस दिन मेरे पास डिटेल नहीं थी। चूंकि इस बारे में काफी जिज्ञासा थी इसलिए मैं इनको बताना चाहूंगा कि मई 2009 तक इस काम को पूरा कर देंगे। इसमें एक साइड में कुछ लोगों ने इन्क्रोचमैंट कर रखी है जिसकी वजह से प्रोब्लम आ रही है। हमने डी०सी० को कह रखा है कि इस मामले को सुलझाएं।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि उस रोड की हालत ठीक ठीक है और ज्यादा खराब नहीं है। लेकिन मंत्री जी खुद जाकर देखें। मैं एक गांव को प्वांयट आउट कर रहा हूं कि मनाला गांव के आस पास वहां खड्डे ही खड्डे हैं। मंत्री जी ने जो मिनी बाई पास के बारे में बताया है, इसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे यहां एक आर.ओ.बी.भी बन रहा है वह भी इनके विभाग से रिलेटिड है उसके लिए भी मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि इससे लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि सड़कों पर 3 साल के बाद रिपेयर हो जाती है लेकिन इस सड़क की रिपेयर नहीं हुई। चूंकि इस सड़क की हालत काफी खस्ता है इसलिए क्या मंत्री जी सरकार से स्पैशल परमिशन लेकर इसको ठीक करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, आपके प्रश्न का जवाब आ गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनके क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगा कि हमने इनके क्षेत्र में 104 किलोमीटर सड़कों की इम्प्रूवमैंट की हैं। इनके हल्के में 22 करोड़ रुपये सड़कों के रख रखाव पर खर्च किए हैं। अगर ये डिटेल लेना चाहेंगे तो इनको डिटेल दे देंगे। करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से इनके हल्के में 53 किलोमीटर सड़कों पर काम चल रहा है। जो वर्क्स इन पाइप लाइन हैं वे करीब 18 किलोमीटर के हैं जिन पर 6 करोड़ रुपये लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, चाहे सड़कों की स्ट्रैंगथनिंग के काम हों, चाहे रिपेयर के काम हों हम टोटल 175 किलोमीटर सड़कों पर कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके हल्के में ज्यादा प्रोब्लम नहीं है करीब 200 किलोमीटर सड़के इनके हल्के में हैं जिन पर काम होना है जिसमें से 175 किलोमीटर सड़कों पर काम कर रहे हैं और बाकी 25 किलोमीटर सड़कों का काम अगले साल में कर देंगे।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कप्तान साहब अपने विधान सभा क्षेत्र के बाद अपने परम मित्र और सीनियर साथी डा० साहब के हल्के में पैसा दे रहे हैं। इनकी दोस्ती का प्रमाण आज सदन के सामने इस प्रश्न के जवाब के माध्यम से आया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इनके हल्के में दो नई सड़के बना रहे हैं। जिन पर 175 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनकी और कप्तान साहब की अभिन्न मित्रता है जिसका प्रमाण आज पता चला है। इन्दौरा जी, कप्तान साहब ने आपके विधान सभा हल्के के लिए विशेष पैसा दिया है।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं लेकिन ये काम दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इनके राज में कोई नई सड़क नहीं बनी। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष तौर पर इनके हल्के में दो नई सड़कें मंजूर की हैं जिन पर काम चल रहा है।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह केवल भ्रामक है, ये हमारे यहां चलें तो इनको पता चल जाएगा कि वहां क्या हालात हैं ?

श्री बलबंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय डेढ़-दो साल पहले बिलासपुर मण्डी गये थे। वहां पर लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बहुत सी मांगे रखी थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनकी सारी मांगे मंजूर कर ली गई। उनमें सोम नदी पर पुल बनाने की मांग को भी मुख्यमंत्री जी ने माना था ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सोम नदी पर कब तक पुल बनवा दिया जायेगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यदि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई अनाउंसमैंट या कोई आश्वासन दिया है तो उस पर हम अवश्य कार्य करवायेंगे। हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे और यदि मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा की है तो इस पर अवश्य कार्य करवाया जायेगा।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि सड़कें बनने के बाद बार-बार पानी जमा होने के कारण या बरसात के पानी के कारण टूट जाती हैं। क्या मंत्री जी भविष्य में वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान देंगे ताकि बार-बार सड़कें न टूटें और पैसों की भी बचत हो ?

श्री अध्यक्ष : सुमिता जी, यह प्रश्न तो पहले ही डाक्टर शिव शंकर भारद्वाज जी पूछ चुके हैं और जबाव भी आ गया है। It is simply repition.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि जहां पर पानी के कारण सड़कें टूटती हैं वहां पर हम सी०सी० की रोड बनाते हैं और जहां पर ड्रेनेज की जरूरत होती है तो ड्रेनेज सिस्टम भी बनाते हैं। यदि कहीं पर ब्लोक्स बनाने की जरूरत होती हैं तो हम वहां ब्लोक्स भी बनवायेंगे। बहन जी के एरिया में भी कहीं पर यदि इस तरह की समस्या है तो वे हमें बता दें हम उसका भी समाधान करवा देंगे। वैसे हमने इन्डीपैंडैंट सुपरविजन कंसलटैंट भी लगा रखे हैं जो स्टेट क्वालिटी मोनिटर और नैशनल क्वालिटी मोनिटर के तहत काम करते हैं हमारे क्वालिटी कंट्रोल के एक्सियन हैं वे भी समय-समय पर गुणवत्ता की चैकिंग करते हैं और यदि कोई कमी मिलती है तो हम शीघ्र ही कार्यवाही भी करते हैं। अभी हमारे विभाग में दोषी पाये जाने पर 120 राजपत्रित अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है जिन्होंने गलती की थी।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने हमारी बहुत पुरानी मांग मान ली और काम भी पूरा करवा दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कोसली से कनीना का मार्ग बनवाने के लिए कोसली विकास रैली में अनाउंस किया था और अब उस रोड़ को पूरी तरह से चौड़ा करके बनवा दिया है। जबकि पहले वाली सरकार के समय में हमें 3-3 फिट के गड्ढों में चलना पड़ता था और पूरे पांच साल निकल गये थे उन्होंने उस रोड़ को नहीं बनवाया। अब मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि अधिकारियों की कमी की वजह से उस रोड़ में थोड़ा सा पैच नहाड़ से लूखी का रह गया है उस पैच को भी जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी बनवाने का कष्ट करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो पैच नहाड़ से लूखी के बीच का रह गया है उसको हम वर्ष 2009-10 के वर्क प्रोग्राम में शामिल करके ठीक करवा देंगे।

डा० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैं हर सैशन में डबवाली से संगारिया तक की सड़क का जिक्र करता हूं लेकिन इस सड़क की रि-कारपेटिंग का कार्य अभी तक नहीं किया गया है। इस सड़क पर थोड़ी बहुत रिपेयर का कार्य तो हुआ है लेकिन इस पर ट्रैफिक बहुत हैवी होने के कारण यह सड़क जल्दी ही टूट जाती है। इस रोड पर आगे राजस्थान की सड़क लगती है और राजस्थान सरकार ने उस सड़क को नैशनल हाई वे डिक्लेयर कर रखा है। डबवाली से संगारिया की सड़क की सरकार रिपेयर करवाती है और वह दस दिन भी नहीं चलती। अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी ने इस सड़क के बारे में आश्वासन भी दिया था कि वे इस सड़क को नये नार्म्ज के मुताबिक बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन हर बार आश्वासन तो मिलता है परन्तु कार्य नहीं होता इसलिए मेरी उनसे दोबारा से प्रार्थना है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी इस बारे में सैप्रेट नोटिस देते तो मैं इनको पूरी डिटेल दे देता। लेकिन फिर भी मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस सड़क को हम सी०आर०एफ० या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या नाबार्ड की किसी योजना में शामिल करके बनाने की कोशिश करेंगे।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले सैशन में भी मेरा एक सवाल लगा था नगीना से तिजारा तक की सड़क बनाने के बारे में, यह एरिया राजस्थान में पड़ता है, यह सड़क पहाड़ काटकर बननी थी। स्पीकर सर, अगर हम फिरोजपुर-नूंह साईड से घूमकर तावडु आते हैं तो हमें लगभग 50-60 किलोमीटर ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता है। स्पीकर सर, वहां पर नगीना से तिजारा तक अगर यह 6-7 किलोमीटर का टुकड़ा बना दिया जाये तो हमें 50-60 किलोमीटर का सफर ज्यादा तय नहीं करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस 6-7 किलोमीटर की सड़क को बनाने का कोई प्रावधान सरकार के विचाराधीन है ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, यह एक सैपरेट क्वैश्चन है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इसके लिए मुझे सैपरेट नोटिस दें तो मैं पूरी स्थिति को एग्जामिन करवाकर कम्पलीट जवाब इनको भिजवा दूंगा।

श्री भूपेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में रूरल इलाकों में कुछेक सड़कें ऐसी हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनमें से कुछ तो एन०सी०आर० में और कुछ नाबार्ड के अधीन आती हैं। इस बार इस मद के लिए गुड़गांव जिला में कोई फण्ड्ज नहीं दिये गये हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, प्रॉपर गुड़गांव शहर में कुछ रोड्ज़ हुडा की हैं और कुछ पी०डब्ल्यू०डी० की हैं। पी०डब्ल्यू०डी० विभाग और हुडा ने अपने-अपने अधीन आने वाली सड़कों को ठीक किया है।

श्री अध्यक्ष : भूपेन्द्र जी, आप रूरल एरिया की बात कर रहे हैं या अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र चौधरी : स्पीकर सर, मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम वर्ष 2009-10 के वर्क प्रोग्राम के तहत इनकी सभी रूरल रोडज़ को ले लेंगे और उनको ठीक करवायेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह बतायें कि कौन सी रोड़ज मार्केटिंग बोर्ड की हैं और कौन सी सड़कें पी०डब्ल्यू०डी० की हैं। अगर कोई सड़क मार्केटिंग बोर्ड की है तो माननीय सदस्य को उसके बारे में माननीय कृषि मंत्री श्री एच.एस. चड्ढा लिखकर जवाब दे देंगे और अगर कोई सड़क पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) की हैं तो माननीय पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) मिनिस्टर माननीय सदस्य को लिखकर जवाब दे देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि स्टेट के अन्दर से जो हाईवेज़ गुजरते हैं क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार करेंगे कि उस सड़क के साथ लगते हुए गांवों में या खेतों में अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो उसका पलिंथ लैवल सड़क से कितना ऊंचा होना चाहिए ? क्या मंत्री जी डिपार्टमैंट की तरफ से कोई कानून बनाने का विचार करेंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इसके लिए फिक्स नॉर्म्ज हैं। नॉर्मली जो पलिंथ लैवल है वह हाईवे से ऊपर होना चाहिए यह तो जो ऑनर है उसको देखना है कि उसे अपनी साईट को कितना ऊंचा रखना है। यह सरकार का काम नहीं है। नॉर्मली पलिंथ लैवल को हाईवे से ऊपर रखा जाता है और अगर कोई नीचा रखेगा तो इससे वहां पर पानी घुस जाने से ओनर का ही नुकसान होगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, यह एक जनहित का सवाल है क्योंकि डिपार्टमैंट की तरफ से अगर अपना कोई कानून हो कि सड़क के किनारे बनने वाले मकान और दुकान का पलिंथ लैवल कितना होगा तो उससे सड़कें टूटने से बच जायेंगी। क्या माननीय मंत्री जी डिपार्टमैंट की तरफ से कोई कानून बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर, लाडवा से मुस्तफाबाद जो सड़क है वह बहुत ज्यादा खस्ताहाल है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस सड़क की रिपेयर करवायेंगे। अगर करवायेंगे तो कब तक ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि स्टेट में इस प्रकार की कुछेक सड़कें हैं जो कि क्वैरी की रोडज़ हैं ये ओवरलोडिड ट्रैफिक की वजह से टूट जाती हैं। जहां तक लाडवा से मुस्ताफाबाद सड़क का सवाल है इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम एग्जामिन करवाकर इस सड़क की जल्दी रिपेयर करवा देंगे।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि रेवाड़ी से अटेली तक की सड़क 2005 में रिपेयर हुई थी लेकिन वह सड़क अब दोबारा टूट चुकी है। क्या मंत्री जी ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही करवा रहे हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, रेवाड़ी से अटेली की सड़क के दोबारा से टेंडर कर दिये हैं और बहुत जल्द ही उसके ऊपर काम शुरु हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, नरेश यादव जी चाहते हैं कि इनकी सभी सड़कों को राजस्थान बॉर्डर के साथ जोड़ दिया जाये लेकिन प्रॉब्लम हमारी यह है कि जितनी भी स्टैरीज हैं वे सब राजस्थान में हैं। राजस्थान से बहुत सारे हैवी व्हीकल्स आते हैं। हमने अभी नारनौल से अटेली का रोड बनवाया है लेकिन अगर उन पर 7-7 टन के भारी व्हीकल्स चलेंगे तो वे टूटेंगे ही। हमने आर.टी.एज. को भी आदेश दे रखे हैं कि जो भारी व्हीकल्स आते हैं उनके चालान काटे जायें। अब हम इस ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि ओवरलोडिड गाड़ियाँ कम से कम चलें।

श्री फूलचन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जिन सड़कों पर हैवी लोडिड गाड़ियाँ नहीं चलती और वे भी बनने के एक साल के अन्दर टूट जाती हैं क्या मंत्री जी उसकी जाँच करवायेंगे और देहातों की सारी सड़कें कब तक रिपेयर कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मुलाना साहब, वह तो पहले ही बता दिया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर ये कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछें तो मैं बता सकता हूँ। वैसे सदन की जानकारी के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पूरे राज्य में तकरीबन कुल 22450 किलोमीटर सड़कें हैं जिसमें से 12000 किलोमीटर सड़कें तो बिल्कुल सही है। 6500 किलोमीटर पर हम पहले ही काम कर रहे हैं वर्क प्रोग्रैस पर है। बाकी बची तकरीबन 5 हजार किलोमीटर सड़कों में से 1500 किलोमीटर बहुत ज्यादा खराब हैं, उनको हम ठीक करवायेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे राज्यों से चाहे आप राजस्थान चले जाओ या किसी और राज्य में चले जाओ वहाँ से हमारी सड़कें बहुत अच्छी हैं।

श्री हबीब-उर-रहमान : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेवात के लिए साढ़े 5 सौ करोड़ रुपये सड़कों के लिए सैंग्शन किये हैं। साथ ही मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि गुड़गाँव से नूंह तक का रोड फोरलेनिंग मंजूर हो गया है। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि नूंह से फिरोजपुर बोर्डर तक की सड़कें का वाइडनिंग का काम हो जायेगा, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसको फोरलेनिंग के लिए एडॉप्ट कर लिया है या नहीं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क हमने एम०सी०आर० स्कीम के तहत ले रखी है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अगर घोषणा की होगी तो हम उसको जरूर बनायेंगे।

Delay in construction of B.Ed. College Bulding Bhiwani

***1069. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that construction of building of B.Ed. College in Bhiwani is delayed; if so, the reason thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : श्रीमान् जी, निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क), हरियाणा द्वारा किया जा रहा है। निर्माण स्थल की परिस्थितियों के कारण निर्माण कार्य में कुछ देरी हुई है। भवन का निर्माण कार्य नवम्बर 2009 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

डा० शिव शंकर भारद्वाज : सर, साईट कंडीशन की वजह से बी०एड० कालेज की बिल्डिंग के निर्माण में डिले हुआ है।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, मंत्री जी ने डिले का रीजन दे दिया और इन्होंने यह भी बता दिया कि वह इस समय तक कम्पलीट हो जायेगा।

आई० जी० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री ने जुलाना में सरकारी कॉलेज की घोषणा वर्ष 2006 में की थी। वर्ष 2007 में बिल्डिंग बननी भी शुरू हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, दो साल हो गये लेकिन जिस तेजी से काम चलना चाहिए उस तेजी से काम नहीं चल रहा है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह बिल्डिंग कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ताकि जो क्लासिज शुरू हो चुकी हैं उनको हम इस बिल्डिंग में शिफ्ट कर सकें और हमारे बच्चों को परेशानी न हो।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए ये सैपरेट सवाल दें फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जल्दी इसको बनाने का प्रयास करेंगे।

श्री एस० एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले माननीय मुख्य मन्त्री साहब कैथल गए थे। उन्होंने बड़ी कृपा की क्योंकि कैथल जिला में कोई कॉलेज नहीं था, वहां पर उन्होंने कालेज मन्जूर किया। लोगों की रिक्वैस्ट पर उस कॉलेज को तुरन्त चालू करने के आदेश दिये थे। पिछले दो साल से वहां पर एक स्कूल की बिल्डिंग में कालेज की क्लासिज़ तो चल रही हैं लेकिन वहां पर कमरे इनऐडिक्वेट हैं, लैबोरेट्री नहीं है, खेल का मैदान भी नहीं है। इस कॉलेज के लिए साढ़े बारह एकड़ जमीन हमने फ्री ले कर डिपार्टमैंट को दी थी लेकिन दो साल से इस पर कोई काम नहीं हुआ है। इस बारे में डिपार्टमैंट को लिख कर भी दिया है। इसके लिए टैंडर तो कॉल किये गये हैं लेकिन इसके लिए पैसा नहीं मिला है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कॉलेज के लिए पैसा देकर वहां पर काम शुरू करवाएंगे ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी में शायद यह बात नहीं है कि इस कॉलेज के लिए 12 करोड़ रुपये अलॉट किये गये हैं। इसके टैंडर मांगे हुए हैं और जल्दी ही इस पर बिल्डिंग का काम चालू कर रहे हैं।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, माननीय मुख्य मन्त्री जी ऐजुकेशन का विस्तार बहुत ही जोर से कर रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि गांवों की पंचायतों ने 15-15 कमरे जोहड़ भर कर अपने खर्चे पर बना कर दिये थे लेकिन वहां पर स्कूल शुरू नहीं हुए हैं। गांव ढाणी पीरवाली और गढ़ी में डी०ई०ओ० इसका इन्सपैक्शन करके गए हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन स्कूलों को कब तक अपग्रेड कर देंगे ताकि बच्चों की ऐजुकेशन के लिए जो पैसा खर्च किया गया है वह ऐजुकेशन उनको मिल सके।

श्री अध्यक्ष : मक्कड़ साहब, यह सवाल तो हायर ऐजुकेशन से सम्बन्धित है (विघ्न) यह सवाल कॉलेज और बी०ऐड० कॉलेजों के बारे में है। आप स्कूलों के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। आप इस बारे में लिख कर मन्त्री जी को भिजवा दें। वे यदि नॉर्म्ज पूरे करते होंगे तो मन्त्री जी इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अरजन सिंह : स्पीकर सर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए अपनी अच्छी सोच दिखाई और वर्ष 2006 में हमारे यहां छछरौली में कॉलेज मन्जूर करके आए थे। हमारे वहां पर कोई भी कॉलेज नहीं था। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कृपा की और वहां पर कॉलेज शुरू हो गया है लेकिन वहां पर कॉलेज की बिल्डिंग नहीं है। यह बिल्डिंग मन्जूर हो गई है लेकिन इसका काम शुरू नहीं हुआ है। क्या शिक्षा मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बिल्डिंग का काम कब तक शुरू करवा देंगे ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि छछरौली कॉलेज की बिल्डिंग मन्जूर हो गई है और जल्दी ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा।

श्री अरजन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनका धन्यवाद करता हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि बी०एड० कॉलेज चलाने के लिए प्रदेश के अन्दर क्या पॉलिसी बनाई है, कितने गवर्नमैंट बी०एड० कॉलेजिज हो सकते हैं और प्राईवेट सैक्टर में जो कॉलेजिज खुलते हैं उसके लिए माप-दण्ड क्या हैं जिनके आधार पर बी०एड० कॉलेज चलाने की इजाजत देते हैं ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में गवर्नमैंट बी०एड० कॉलेज केवल दो ही हैं लेकिन ज्यों-ज्यों स्टूडैंट्स तथा लोगों की और टीचर्ज की डिमांड आई, प्रदेश में बी०एड० कॉलेजिज की बाढ़ सी आ गयी और सरकार उनको रोकने के बावजूद भी रोक नहीं पा रही है। हमारे यहां पर 480 कॉलेजिज हैं जो सैल्फ फाईनैंस में चल रहे हैं। हमने उन कॉलेजिज को रोकने की कोशिश भी की है क्योंकि एकदम इतने ज्यादा कॉलेजिज हो जाने से हमें यह खदशा है कि जब हमारे इतने ज्यादा लड़के ट्रेंड हो जाएंगे तो सरकार के लिए उनके लिए सर्विसिज देना एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी लेकिन इन कॉलेजिज को रोकना हमारे हाथ में नहीं। सैंटर गवर्नमैंट ने अपना एक अदायरा बना रखा है, बी०एड० कॉलेजिज के लिए वहां से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर हम ऐसे कॉलेजिज को रोकने की कोशिश भी करते हैं तो वे कोर्ट से सैंग्शन ले कर कॉलेज खोल लेते हैं। इस समय हरियाणा में बी०एड० कॉलेजिज की कोई कमी नहीं है।

डा० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा में बी०एड० कालेजिज़ की कोई कमी नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज कई बी०एड० कालेजिज़ ऐसे हैं जोकि नार्मर्ज पूरे नहीं करते हैं और बी०एड० की डिग्रियां बांटते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हरियाणा में आने वाले समय में शिक्षा का स्तर बहुत गिर जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं ऐसे कालेजिज़ के नाम भी बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, बी०एड० कालेजिज़ खोलने का एक क्राईटेरिया होता है, स्पैसिफिकेशंज होती हैं। अगर ये सभी पूरी होती हैं तभी बी०एड० कालेज खोलने की परमिशन दी जाती है। अगर आपके पास किसी कालेज का नाम है कि वह ऐसे ही डिग्रियां बांट रहा है तो उसका नाम बताएं।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि बी०एड० कालेज स्टेट गवर्नमैंट नहीं खोलती है। बी०एड० कालेज खोलने की सैन्टर की एन०सी०ई०आर०टी० परमिशन देती है। स्पीकर सर, जैसा डर माननीय साथी को महसूस हो रहा है तो मैं इनको बताना

चाहूंगा कि इससे पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी को और हमें भी यही डर महसूस हुआ था कि अगर इसी तरह से बी०एड० कालेज खुलते रहे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को नौकरी देने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसी सोच के चलते हुए हमने सैन्टर गवर्नमैंट को लिखा भी था और उन्होंने हमारी बात मान भी ली है। अब उन्होंने यह कहा है कि आगे से जो भी बी०एड० कालेज खुलेगा तो उसको खोलने से पहले स्टेट गवर्नमैंट की राय ली जाएगी। इसके अलावा जहां तक इन्होंने डिग्रीयां देने वाली बात कही है तो अगर इनके पास ऐसी कोई शिकायत है तो ये हमें लिख कर दें हम उस पर जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज की सरकार शिक्षा की ओर बहुत ध्यान दे रही है। माननीय मंत्री जी कलायत में एक कपिल मुनि कालेज हैं, उसकी बिल्डिंग साढ़े नौ एकड़ में तैयार है। हमारा कलायत हल्का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या मंत्री जी उस कालेज को सरकार द्वारा टेक ओवर करने के बारे में विचार करेंगे। इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को दरख्वास्त भी भेजी हुई है।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपना एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा कि माननीय सदस्या ने जो बात कही है वह जायज है। उस कालेज में से बहुत से बच्चे पढ़ कर निकलते हैं और अगर पोसिबल है तो क्या सरकार इस कालेज को टेक ओवर करेगी।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम कलायत के कालेज को टेक ओवर करेंगे। अगर विधायिका जी ने मुख्यमंत्री जी को कोई दरख्वास्त दी हुई है और मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकार कर लेते हैं तो हम इस बारे में एग्जामिन कर लेंगे।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कालांवाली एक नया हल्का बना है। क्या वहां पर भी सरकार नया कालेज खोलने के बारे में विचार करेगी ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से कहना चाहूंगा कि अभी तो यह नया हल्का बना है। इसको प्रयोग करो और देखो कि वहां पर क्या क्या प्रोब्लम है ? हम समय आने पर इसको भी देखेंगे।

Separate Panchayat or status of Municipal Committee to Pillukhera Mandi

***1086. Sh. Bachan Singh Arya :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to grant the status of Municipal Committee or to constitute a separate Panchayat for Pillukhera Mandi in Safidon Constitutency which comes under the Panchayats of village Pillukhera and Bhuran Mandi keeping in view its wide spread area and huge population ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री० एसी० चौधरी) : प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री बचन सिंह आर्य : अध्यक्ष महोदय, पिल्लूखेड़ा मंडी जोकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में है और जहां पर बहुत बड़ी मंडी है वहां पर सात हजार के करीब आबादी भी है। जब 28 जून, 2008 को मुख्यमंत्री जी ने वहां पर एक बहुत बड़ी जनसभा की थी तो उस वक्त उनके सामने भी हमने यह बात रखी थी कि पिल्लूखेड़ा मंडी तीन गांवों यानी बुरहेड, अमरावली और पिल्लूखेड़ा गांवों की पंचायतों में आती है। पुरानी मंडी और पुराना शहर होते हुए भी आज तक वहां पर पंचायत नहीं है और न ही नगरपालिका है। वहां पर रेलवे स्टेशन भी है।

श्री अध्यक्ष : बचन सिंह जी, उन्होंने जबाव दे दिया है कि matter is under consideration. आपने जब लिखकर दिया होगा तभी इन्होंने सर्वे करवाया होगा और तभी तो इन्होंने यह कहा है कि matter is under consideration.

श्री बचन सिंह आर्य : स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि विचाराधीन तो बहुत लम्बे समय से है। हम शुरू से ही इस बात की मांग कर रहे हैं। चूंकि वहां पर बहुत समस्या है तो क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि जल्दी ही ये वहां पर नगरपालिका बनाने की मंजूरी देंगे ? अगर किसी वजह से वहां पर नगरपालिका नहीं बन सकती तो क्या पिल्लूखेड़ा मंडी में अलग से पंचायत बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 अगस्त को अपने दौरे में इनके हल्के की मांग को देखते हुए यह आश्वासन दिया था कि अगर ये तीन गांव की पंचायतें नगरपालिका बनाने के लिए क्वालीफाई करती हैं तो जरूर वहां नगरपालिका बना दी जाएगी। अब इस मांग को प्रोसैस में ला दिया गया है लेकिन इसके लिए कई क्राईटेरिया फिक्स हैं जैसे आबादी का, वहां के इन्कम के सोर्सिस का और उसके साथ ही यह कि क्या वह एरिया अर्बन इन करैक्टर है जिसमें कम से कम 60 परसैंट तो शहरीकरण होना ही चाहिए। उसके अलावा क्या वे लोकल पंचायतें हैं अगर हैं तो उनके पास क्या प्रस्ताव उपलब्ध हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : बचन सिंह जी, आप लोकल पंचायतों से भी और मंत्री जी से भी पर्सनली मिल लेना और इस मामले को परस्यू कर लेना।

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर साहब, अगर ये सी०एम० साहब के सामने पेश हुए थे तो उसके आधार पर हम डी०सी० की अध्यक्षता में इस बारे में एक कमेटी गठित कर देते हैं। डी०सी० के पास ये इस बारे में लिखकर भेज दें और उसके बाद अगर वह क्वालिफाई करते हैं तो हम इस बारे में एग्जामिन कर लेंगे।

Shri Dharambir : Speaker Sir, I would like to know from the Hon'ble Minister that there is any proposal under consideration of the Government to Constitute the Municipal Committee to the important towns of the Haryana *i.e.* Hasanpur? Population of the Hasanpur town is nearly 15 thousand.

Shri A.C.Chaudhary : Speaker Sir, basically as on date we do not have any such suggestion but still Hasanpur has already been cleared.

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे हल्के हैं जो म्यूनिसिपल कमेटी से बाहर पड़ते हैं। नये इलाके जो अभी तक एप्रुव नहीं हुए हैं। उनके अंदर प्रौब्लम यह है कि न तो म्यूनिसिपल

कमेटी वहां पर रोड बनाती है न पैसा खर्च करती है। वह एरिया पंचायत में भी नहीं आता है इसलिए वहां पर एच०आर०डी०एफ० का पैसा भी खर्च नहीं होता है। इस तरह से ऐसे इलाके न इधर के रहते हैं और न उधर के रहते हैं वे दोनों तरफ से वंचित रह जाते हैं। क्या मंत्री महोदय का ऐसे इलाको की तरफ भी ध्यान हैं ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपका स्पैसिफिक सवाल यह है कि जो एरिया म्यूनिसिपल कमेटी से बाहर है उनको म्युनिसिपल कमेटी में मिलाओगे या नहीं मिलाओगे ?

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : हाँ जी।

श्री ए०सी० चौधरी : स्पीकर साहब, आलरेडी अनऐप्रूव्ड कालोनीज का केस कोर्ट से स्टे है। जब इस बारे में फैसला होगा तो हम देख लेंगे। मैं हाउस की जानकारी के लिए इतना बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात की सीरियसनैस को महसूस किया है इसलिए आज ही या कल इन दोनों विभागों के अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। मैं इतना जरूर बता दूं कि जो एरिया म्युनिसिपल कमेटी से बाहर हैं उनके लिए कहीं भी म्युनिसिपिल कमेटी की लायबिलिटी नहीं बनती लेकिन अगर वह रिजर्व एरिया में है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर ऐसे मशरूम ग्रोथ न हो। इसके मुताबिक किया जाएगा और जो बाकी अनऐप्रूव्ड एरियाज के लिए अगर प्रोविजन होगा तो हम उसके मुताबिक काम करेंगे।

श्री राधे श्याम : स्पीकर साहब, एक तरफ नारनौल शहर की नगरपालिका है और उसके साथ सुभाष नगर स्पैसिफिक मौहल्ला है लेकिन उसको कोई भी सुविधा नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप इस बारे में स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछ लेना क्योंकि जनरल पोलिसी इन्होंने बता दी है।

श्री भूपिन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि फरुखनगर म्युनिसिपल कमेटी के अन्तर्गत चांदनगर गांव हैं जिसे सदन में आश्वासन के बाद भी म्युनिसिपल कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। यह कह दिया गया था कि अब की बार जब म्युनिसिपल कमेटी के इलैक्शन होंगे उसमें यह गांव म्युनिसिपिल कमेटी में शामिल कर लिया जाएगा। उसके इलैक्शन हुए और मैंने मन्त्री जी को लिखकर भी दिया कि वहां टोटल हरिजन पॉपुलेशन है और आज के दिन भी वह गांव न तो म्युनिसिपल कमेटी में है न ही पंचायत में है। यह भी जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है कि आश्वासन के बाद भी यह काम नहीं हुआ है ?

श्री ए० सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में ऐसी कोई ऐश्योरैंस सरकार की तरफ से नहीं दी गई फिर भी आज इन्होंने इशू रेज किया है। यह क्वैशचन बिल्कुल सेपरेट है फिर भी मैं इसको देखकर ऑनरेबल मैंबर को पत्र द्वारा यह जानकारी दे दूंगा।

श्री धर्मबीर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि म्युनिसिपल कमेटी के साथ लगते-लगते जो एरिया हैं उनको म्युनिसिपल कमेटी में शामिल क्यों नहीं कर लिया जाता है। अनअथोराइज्ड कालोनीज का नाम देकर उनको इग्नोर क्यों किया जाता है। आखिरकार डिवैल्पमैंट तो उस इलाके की भी होनी है कि नहीं होनी है ?

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो एरियाज म्युनिसिपल लिमिट से बाहर हैं। (विघ्न)

श्री धर्मबीर : उनकी लिमिट कौन बढ़ाएगा ?

श्री ए०सी० चौधरी : इस बारे में मैं इतनी अर्ज जरूर करूंगा कि इनका पहला सवाल है उसका पहले जवाब ले लें। उसमें जो एरिया म्युनिसिपल लिमिट से बाहर है उनकी अर्बन लोकल बॉडीज की कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर कोई ऐसी जरूरत है और उस एरिया के लोगों की मांग आएगी और लोकल एम०एल०ए० की कोई मांग आएगी तो उस पर जरूर विचार करके जो सही निर्णय होगा, वह अवश्य सरकार ले लेगी।

श्री हबीब-उर-रहमान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि नूंह पहले सब डिवीजन था और इस सरकार के आने के बाद जिला बना दिया गया है। क्या जो म्युनिसिपल कमेटी की बाउंड्री है उसको बढ़ाने की सरकार की कोई मंशा है या नहीं ?

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जब बाउंड्री आलरेडी ईयरमार्क हो जाती है तभी म्यूनिसिपिल कमेटी बनाने की घोषणा की जाती है।

श्री हबीब-उर-रहमान : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐक्सटैंशन की बात कर रहा हूं।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ऐक्सटैंशन का केस अलग से अंडर कंसीड्रेशन है और जो भी केसिज आए हैं जिन-जिन का केस प्रौसेस में है उनमें से अगर हम कोई भी केस क्लीयर करते हैं तो उसके लिए तो ऑब्जैक्शंज/सजेशंज नोटिफाई करते हैं और वह प्रौसेस में है।

श्री धर्मबीर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमैंट्री और पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : गाबा साहब, आपका और चौधरी साहब का इंटरनल मामला है इसलिए आप अलग से उनसे क्वैश्चन कर लेना।

Functioning of Blood Component Separator

***1195. Smt. Sumita Singh :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the Blood Component Separator Instrument purchased in the year 2002 with the cost of Rs. 25 lac for Government Hospital, Karnal has not been made functional so far; if so, the reasons thereof ?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Yes, Sir. The Blood Component Separation Unit could not be made operational due to non-issue of license from Drug Controller General Govt. of India.

स्पीकर सर, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्या की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि सारी फ़ौर्मैलिटीज पूरी करके वह कागज ड्रग कंट्रोलर के पास भेज दिया गया है और अगले 24 घंटे तक वह लाइसैंस मिल जाएगा ?

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि जब भी कोई नयी मशीनरी लेते हैं उसके लाइसैंस के लिए पहले ऐप्लाई करते हैं, तभी मशीनरी लेते हैं। चलो यह तो हो गया सो हो गया लेकिन नौ साल का लम्बा अर्सा बीत जाने के बाद क्या

सरकार ने उन आफीसर्ज के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया है जिन्होंने लाइसैंस ऐप्लाई करने में इतनी देरी की ? 9 साल के अर्से में तो रोज रोज नयी-नयी तकनीक आती है अब तक तो ब्लड सैपरेशन यूनिट भी आउटडेटेड हो गया होगा। जब प्राइवेट हॉस्पीटल्ज को ऐसे यूनिट्स के लाइसैंस मिल जाते हैं फिर गवर्नमैंट हॉस्पीटल को लाइसैंस लेने में क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं लिया ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि उनकी चिंता इस बारे में बिल्कुल वाजिब है और मैं उससे सहमत हूं। एक तो जो लाइसैंस है वह तभी लिया जाएगा जब उस मशीन के पूरे कंपोनैंट्स, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मौके पर पूरी तरह से लगा दी जाएगी। यह सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ड्रग कंट्रोलर के पास लाईसैंस के लिए केस जाता है। ड्रग कंट्रोलर कभी भी इन ऐंटीसिपेशन लाइसैंस नहीं देता। इस काम में वाकई ही बहुत देरी हुई है। इस देरी के लिए जिम्मेदार हमारे माननीय सदस्य यहां बैठे भी है। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत देर तक तो ब्लड कंपोनैंट सैपरेशन यूनिट के इक्विपमैंट नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात नाको से नहीं आए। पांच साल तक तो यह संस्था वह इक्विपमैंट्स ही पूरी नहीं करवा पाई। पांच साल की अवधि तक तो इक्विपमैंट्स और पार्ट्स ही नैको से आते रहे। इस बारे में यह रिपोर्ट दुर्भाग्यपूर्ण है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, पांच साल की बात तो ठीक है लेकिन अब इन 4 साल की अवधि में सरकार ने क्या किया है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उसके बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर और दूसरे पार्टस मौजूदा सरकार आने के बाद पूरे करवाये गये हैं। (विघ्न) इसमें देरी हुई है वह बात तो मैंने पहले ही मान ली है। उसके बाद हमने यह केस ड्रग कन्ट्रोलर के पास भेजा है। वर्षों से पैथोलोजिस्ट ही नहीं थे। वर्तमान सरकार ने 35 नये पैथोलोजिस्ट लगाये हैं जिनमें से दो करनाल में भी लगाये हैं। पैथोलोजिस्ट के बगैर तो यह मशीन चल ही नहीं सकती है। हमें उम्मीद है कि अगले 24 घण्टे में उसके लिए यह लाईसैंस भी आ जायेगा तो इस इंसट्रूमैंट को चालू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि केवल एक ही नहीं इसी प्रकार का Blood Component Unit पी०जी०आई० रोहतक में भी लगा दिया है। वर्ष 2009-2010 तक Model Blood Bank for training in Blood Banking वहां पर भी शुरू करेंगे। इसी प्रकार से दो यूनिट्स हिसार और फरीदाबाद में भी लगायेंगे। हमने नैको को इस बारे में केस भेज दिया है। जो कमियां पहले केस में रह गई थी उन सबको केस भेजने से पहले से ही दूर कर लिया जायेगा। Infrastructure Pathologist की जितनी भी जरूरत थी वह सब मापदण्ड पूरे कर लिये हैं वहां पर जल्दी ही मशीनें आ जायेंगी। इसी प्रकार से मार्डन ब्लैड बैंक की मशीन भी लगाई जायेगी। ये तीनों मशीने साथ-साथ लगाई जायेंगी।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननयी मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इस Instrument को पिछली सरकार ने खरीदा और माननीय मंत्री जी इसको अधूरा बताते हैं तो जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये अधूरा रह गया था उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की। क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की इच्छा रखती है। विघ्न

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह इक्विपमैंट हमने नहीं खरीदा।

Election of Municipal Corporation, Gurgaon

* **113. Sh. Dharambir :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the time and date on which the election of Municipal Corporation, Gurgaon will be held?

Ubran Development Minister (Sh. A.C. Chaudhry) : Sir, as per Section 4(4) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, the election of Municipal Corporation, Gurgaon is to be conducted within a period of one year as extended from the date of its constitution. However, State Election Commission has not fixed any date as yet.

Shri Dharambir : Sir, will the Government consider to request the State Election Commission that the election of Municipal Corporation, Gurgaon should be held after the election of the Lok Sabha?

Shri A.C. Chaudhary : Gaubaji, I could not get you. Speaker Sir, this is a new Municipal Corporation and after that we have to see so many formalities to be completed at the end of the Government. First of all, census is to be conducted and for that we have given contract to a very big company who has deputed almost 200 people on the job to conduct the census. Thereafter, of course, wardbandhi is to be done. After completion of all these formalities, we can request the State Election Commission to conduct their business themselves.

Shri Dharambir : Speaker Sir, he said, the process is not going on but the process is already going on. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रोसैस चालू नहीं हुआ है जबकि प्रोसैस आलरेडी चल रहा है। वार्ड बन्दी के बारे में आज गुड़गांव में मीटिंग हो रही है लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। इनकी इन बातों को कैसे माना जाए ? इन बातों को मंत्री जी बतायें।

Shri A.C. Chaudhary : Sir, little knowledge is dangerous thing. सिस्टम में तीन लाख के करीब डिवैलिंग हाउसिज हैं जिनमें से दो लाख का तो सर्वे इस साल सरकार करवा चुकी है। जिस कम्पनी को हमने ठेका दिया हुआ है वह एक्टीवैली ऑन जॉब पर है। जब तक हम इस बारे में पूरा सर्वे नहीं कर पायेंगे तब तक वार्ड बन्दी होने का कोई चान्स नहीं है। सर, हमारा जो शिड्यूल्ड है वह 28 फरवरी तक हमने टाईम बाउंड किया हुआ है। वह कम्पनी यह सारा सैन्सस कम्पलीट कर लें, उसके बाद ही वहाँ की वार्डबंदी करेंगें और वार्डबंदी का एक ड्राफ्ट नोटीफाई करेंगें। ओब्जैक्शन और सजैशन आने के बाद फाईनल वार्ड बंदी के बाद हम स्टेट इलैक्शन कमीशन को भेज देंगें कि ये वार्डबन्दियां हो गई है then they can go ahead. लेकिन इससे पहले स्टेट इलैक्शन कमीशन ने पार्शियल इन्फोर्मेशन पर कोई प्रोसैस शुरू किया है तो Hon'ble Members should appreciate it that Government is quiet serious about it.

Water Allowance in the State

* **1220. Shri S.S. Surjewala :** Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) whether the water allowance in the State of Haryana is 2.4 Cs and the only exception is district Kaithal where water allowance is 1.9 Cs; if so, the

grounds for this discrimination togetherwith steps taken to remove this discrimination; and

(b) whether it is a fact that the Saraswati distributary system existing in the Kaithal area was being fed from Saraswati Lake since inception and now the Saraswati Lake is not being allowed to be filled for the last about 10 years making Kaithal as one of the dry districts; if so, the steps taken by the Government for providing alternate source to feed the Saraswati distributary System ?

Public Works Minister (Capt Ajay Singh Yadav) :—

(a) No Sir. Water allowance is not a uniform figure for the whole State. It varies depending upon the agro-climatic conditions and ground water availability. Water allowance on Saraswati Distributary System and Markanda Distributary System in Kaithal District is kept as 1.95 Cusecs per thousand acres CCA because it is a sweet water zone having large number of tubewells. There is no proposal under consideration of the Government to increase the water allowance from 1.95 cusecs to 2.40 cusecs per thousand acres CCA.

(b) Yes Sir. It is fact that the Saraswati Distributary System existing in Kaithal area was being fed from Bibipur Lake (not from Saraswati Lake) upto the year 2000, but it also has its source from Narwana Branch through Saraswati Feeder. Land owners of the Lake area did not allow to fill the lake from the year 2000. However, normal water is being supplied to the Saraswati Distributary from the Narwana Branch.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि वाटर अलाउंसिज को फिक्स हुए लगभग 40 से 50 साल हो गए हैं। जब भाखड़ा नहर निकली थी उस समय वाटर अलाउंसिज फिक्स हुए थे। उस समय इस इलाके में बेशुमार जंगल थे। घग्घर नदी के पास भी 10-10 या 20-20 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल था। लोकल भाषा में इसे बण कहते हैं। लैंड रिक्लेम बाद में किए हैं। यही कारण था कि वहां वाटर अलाउंसिज पूरे फिक्स नहीं किए गए।

श्री अध्यक्ष : ये वाटर अलाउंसिज कब फिक्स हुए थे ?

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, वाटर अलाउंसिज 1960 में फिक्स हुए थे। उसके बाद तो बहुत चेंजिज आ गए हैं। अब वहां कोई जंगल नहीं है और पूरी जमीन पर काश्त होती है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात माननीय मंत्री महोदय की नोलेज में यह भी नहीं है कि कैथल अब ज्योग्राफिकली दृष्टि से रिओर्गेनाइज हो चुका है। कलायत कांस्टीच्युंसी जो पहले जींद जिले में थी वह अब कैथल जिले में आ गई है। कलायत में 40 से 45 गांव हैं। कलायत में एक भी ट्यूबवैल नहीं है वहां सारे खेत सूखे हैं और वहां पानी भी खारा है। पाई कांस्टीच्युंसी जिसको श्री तेजेन्द्रपाल जी रिप्रैजेंट कर रहे हैं, वहां के एक गांव में भी ट्यूबवैल नहीं है। पूरे इलाके का पानी खारा है। कैथल में 40 के करीब गांव हैं जिनमें से 22 के करीब गावों में कोई ट्यूबवैल नहीं है। नीचे का पानी खारा है। सिर्फ गुहला चीका एक ऐसा हल्का है जहां ट्यूबवैल भी है और वहां से घग्घर नदी भी बीच से निकलती है। नम्बर एक तो ज्योग्राफिकली सिचुएशन सारी चेंज हो गई हैं और दूसरा 1960 में और आज के समय में कितने सालों का फर्क है ? Total soil and every condition has been changed.

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि in view of the changed situation क्या मंत्री जी पुनर्विचार करेंगें और उनको वही वाटर अलाउंसिज देंगें जो भाखड़ा के बाकी एरियाज में दिए जा रहे हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार में बताया है कि वाटर अलाउंसिज क्लाइमेटीज पर डिपैंड करता है कि वहां पर स्वीट वाटर जोन है या सैंडी एरिया है। सैंडी जो एरिया है जहां लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है वहां पर वाटर अलाउंसिज पहले 2.4 क्यूसिक्स था लेकिन अब 3 क्यूसिक्स है। हिसार के कुछ एरियाज हैं जहां पर 4 क्यूसिक्स था।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सिरसा और हिसार में वाटर अलाउंसिज 4 क्यूसिक्स बताया है। मुख्यमंत्री का एरिया था इसलिए 4 क्यूसिक्स कर दिया होगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, 1960 में तो हरियाणा ही नहीं बना था तो मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। हमें एवेलेबिलिटी आफ वाटर देखना पड़ता है।

स्वीट जोन वाटर के एरिया में अलग पोलिसी होती है और ट्यूबवैलज हैं या नहीं है उनके लिए भी अलग पोलिसी होती है। लेकिन फिर भी हमें काफी चिंता है इसलिए इसको हमने एग्जामिन करने के लिए कह दिया है और उसके लिए तीन महीने का समय दिया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम की रिमोडलिंग करते समय सारे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा उस समय उनको खरीफ के लए 2.4 क्यूसिक्स पानी दिया जा सके।

मुख्यमंत्री (श्री भपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, इनके एरिया में अब भी खरीफ के लिए 3 क्यूसिक्स पानी दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, खरीफ के लिए तो अब भी 1.9 क्यूसिक्स की जगह 3 क्यूसिक्स पानी दिया जा रहा है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी हम खरीफ के लिए नहीं दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि अभी पानी की कमी है।

श्री बलवंत सिंह सढ़ौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बरसात के फालतू पानी से वाटर रिचार्जिंग करने के लिए यमुना नगर से नारायणगढ़ तक एक नहर बनानी सरकार के विचाराधीन थी। पिछले बजट सैशन में मंत्री जी ने कहा था कि इस नहर के लिए पैसे का भी प्रावधान किया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस नहर पर अब क्या कार्यवाही चल रही है और कब तक इसको बनवा दिया जायेगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह स्कीम एप्रूवल के लिए सैंट्रल वाटर कमीशन को भेजी हुई है जैसे ही वहां एप्रूवल आ जायेगी हम इस पर कार्यवाही शुरू कर देंगे। (विघ्न) नहीं तो ये बाद में कह देंगे कि सरकार ने पहले एप्रूवल नहीं ली।

Construction for roads connecting with Rajasthan Border

*** 1207: Shri Naresh Yadav :** Will the Agriculture Minister be pleased to state the time by which the construction work will be started on the 23 roads of Rewari and Mahendergarh districts connecting Rajasthan Border, announcement for which was made by the Hon'ble Chief Minister on 17th February, 2008 in Ateli Constituency, togetherwith the reasons due to which the construction work has not been started so far alongwith the full details thereof?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) : Sir, a statement is placed on the table of the house.

Statement

As per policy of the Board, only those paths are made pucca where minimum 5 Karam path is available. As per Revenue record, the path available for all these 23 proposals is less than 5 Karam. However, the Government *vide* order dated 15.01.2009 has given approval for the construction of 4 roads subject to the condition that the deficiency in available path is made available by the adjoining land owners so that the available path becomes 5 Karam. These roads are :—

Sr. No.	Name of road	Length in KM	Path in Karam	Estimated cost (Rs. in lac)
1	Ratta Khurd to Kalwari	7.30	4	145.00
2	Behali to Gokalpur via Ateli Begpur	4.90	4	98.00
3	Mohalra to Ramchand Pura via Ratta Kalan	2.30	4	46.00
4	Mohanpur to Girdharpur Garhi Ruthal	7.75	4	155.00

The construction work of these roads will be started as and when the additional required land width is transferred in the name of Market Committee concerned by the land owners.

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने महेन्द्रगढ़ जिले में भी सड़कें बनाने का पहली बार खाता खोला है। माननीय मंत्री जी ने अब हमारे वहां भी 4-5 सड़कें बनाने का आदेश दिया है। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे हल्के में 4-5 ऐसी सड़कें हैं जो राजस्थान के साथ लगती हैं और उनकी हालत बहुत खराब है वे सड़कें 400-400, 500-500 मीटर की हैं यदि उनको बना दिया जायेगा तो राजस्थान और हमें दोनों प्रदेशों के लोगों को फायदा होगा। थे सड़कें बिहाली सा कायसा, बूसन से डूमडोली और कांटी से तलवाना तक की है। यदि इन सड़कों को बना दिया जायेगा तो थोड़ा सा जो लिंक है वह पूरा हो जायेगा और हम राजस्थान से जुड़ जायेंगे इसलिए इन सड़कों को चाहे पी०डब्ल्यू०डी० बनवाये, चाहे मार्केटिंग बोर्ड बनवाये लेकिन जल्दी से जल्दी बनवाया जाये।

सरदार एच०एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, जिन सड़कों का माननीय यादव जी ने जिक्र किया है ये सड़कें नार्म्ज पूरा नहीं करती। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है कि जो भी सड़क नार्म्ज पूरा करती हों उन्हें बनवा दिया जाये। मेरे साथी इन सड़कों का नार्म पूरा करके इन्हें पांच कर्म की करवा दें हम इन्हें बनवा देंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी नरेश यादव जी के एरिया में आठ सड़कें बन रही हैं जिनमें दो सड़कें पी०डब्ल्यू०डी० बना रहा है और 6 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड बनवा रहा है। इसके लिए इन्हें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए और ये कह रहे हैं कि इनके यहां सड़कें बनाने का खाता सरकार ने खोला है।

Repair of CHC at Hodal

*** 1125. Sh. Udai Bhan :** Will the Health Minister be pleased to state whether any steps are being taken by the Government to repair/renovate the dilapidated building of the Community Health Centre at Hodal; if so, the time by which the said work is likely to be completed?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes Sir, the repair work is likely to be completed by March 2009.

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि होडल की सी०एच०सी० कहने को ही सी०एच०सी० है लेकिन उसकी बिल्डिंग की हालत बहुत ही जर्जर है। अब उसकी रिपेयर की जा रही है लेकिन उसकी हालत बहुत खस्ता है।

श्री अध्यक्ष : उदयभान जी, आपके सवाल का जवाब मंत्री जी ने दे दिया है और आपको समय भी बता दिया है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, वहां के लिए 26 लाख रुपये सरकार ने दिए हैं।

Construction of an Escape Reservoir

*** 1104 Maj. Nirpender Singh Sangwan :** Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that escape at Pump House No. 2 on the Loharu Canal causes floods on the vast chunks of fertile land in villages Birhi Kalan and Mehra;

(b) whether it is also a fact that no compensation has been paid to the affected farmers by the Government; if so, whether there is any proposal to compensate these farmers; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an escape reservoir at RD 41300 on the left of Loharu Canal?

Public works Minister (Capt. Ajay Singh Yadav):—

(a) Yes Sir.

These escape at Pump House No. 2 on Loharu Canal submerges the land of villages Birhi Kalan and Mehra when the escape is run.

(b) Yes Sir.

No compensation has been paid to the affected farmers by the Government as it was not required because the escape water was being used for the crops during keen demand. At present there is no proposal to compensate these farmers.

(c) Yes Sir.

There is proposal under consideraton of the Government to construct an escape reservoir at R.D. 41300 on the left of Loharu Canal.

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैंबर्ज, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Bus Service from Nangal Paju to Badhra

***1176. Shri Somvir Singh :** Will the Transport Minister be pleased to state:—

(a) whether the route permit has been issued to private bus from Nangal Paju to Badhra in Loharu Sub-Division; if so, whether the said bus is plying only in day time and not in morning and evening; and

(b) whether there is any proposal to get ply the said bus in the morning and evening and to issue a route permit of the second bus to any other person?

परिवहन मंत्री (श्री मांगेराम गुप्ता) :

(क) हां श्रीमान् जी। जिला भिवानी के मार्ग संख्या 7 बाढड़ा से गारनपुरा वाया नांगल पाजू मार्ग पर वर्ष 1993 की निजीकरण स्कीम के अन्तर्गत दो रूट परमिट जारी किए गए थे परन्तु इस समय इस मार्ग पर कोई बस नहीं चल रही है।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

Development of Sarswati River Project

*** 1129. Smt. Geeta Bhukal :** Will the Irrigation Minister be pleased to state the details of steps taken by the Government for the development of Saraswati River Project especially in Kalayat?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : हां श्रीमान जी, एक विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणी

पुरातत्व अनुसंधान के माध्यम से इस मत को सहायता नहीं मिलती है कि बहुत से लोगों को विश्वास है कि पुरानी सरस्वती नदी शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में यमुनानगर जिले के आदी बद्री के आसपास से निकलती है। आगे यह भी ज्ञात हुआ है कि पवित्र सरस्वती नदी का मार्ग बिलासपुर शहर के कपालमोचन क्षेत्र के आसपास में मौजूद है और आगे चलकर चौतांग नाले में मिल जाता है। यद्यपि चौतांग नाले को पश्चिमी यमुना नहर तक पहले ही चैनल बनाया जा चुका है। सरस्वती नदी का चौतांग नाले तक का भाग निरर्थक बन गया है। यह जाना जा रहा है कि यमुनानगर जिले के गांव थाना छप्पर से आगे लगभग 95 किलोमीटर की लम्बाई में नदी का बहने का रास्ता पाया गया है जोकि यमुनानगर एवं कुरुक्षेत्र जिलों के गांव ऊँचा चंदाना - झिवरेहड़ी - जुआंधौला - बीर पिपली - नरकटारी के पास से गुजरती पाई गई है और अन्त में इसका रास्ता सतलुज यमुना सम्पर्क तथा नरवाना ब्रांच नहरों पर बनी साईफन के माध्यम से जिला कुरुक्षेत्र में बीबीपुर झील तक का पाया गया है। बीबीपुर झील से आगे पुराना नदी का जो भाग मिला है उसे सरस्वती ड्रेन में बदला जा चुका है जोकि अन्त में पाडा नदी में गिरती है और उसके बाद आगे चलकर घग्गर नदी में गिरती है। समय गुजरने के साथ-साथ सरस्वती नदी के रास्ते को एक ड्रेन में बदला जा चुका है। हम लोगों की भावनाओं को मध्यनजर रखते हुए इसका नाम सरस्वती ड्रेन से बदलकर सरस्वती नदी रजबाह रख दिया है और इस रजबाह में गन्दा पानी डालने को रोकने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पुरानी सरस्वती नदी के मौजूद बहने वाले स्थान को जिला यमुनानगर के गांव ऊँचा चंदाना से कुरुक्षेत्र जिले के गांव नरकटारी में सतलुज यमुना सम्पर्क नहर तक 200 क्यूसिक क्षमता की 83 किलोमीटर लम्बाई में सरस्वती नदी रजबाह के रूप में पुनर्जीवित किया जायेगा। इसमें पानी शाहबाद फीडर के 31.89 किलोमीटर से छोड़ा जायेगा। (शाहबाद फीडर एक खरीफ चैनल है जिसका निर्माण दादूपुर नलवी योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है और इस योजना पर 90 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है)। सरस्वती नदी रजबाह को पुनर्जीवित करने का कार्य 63 किलोमीटर की लम्बाई में राष्ट्रीय राजमार्ग नं० - 1 (पिपली के नजदीक) तक किया जा रहा है जोकि प्रगति पर है और अब तक 50 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। बहुत से भागों में नदी का पुराना प्रवाह पथ मौके पर मौजूद नहीं है क्योंकि इसकी नीची भूमि का आलेख राजस्व अभिलेख में भी उपलब्ध नहीं है। अतः इस उद्देश्य के लिए नदी के पुराने प्रवाह पथ के लापता स्थानों और जहां प्रवाह पथ तंग मिला है उन पर 17.92 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

शेष भाग 20 किलोमीटर लम्बाई में जोकि कुरुक्षेत्र जिले में पिपली से सतलुज यमुना सम्पर्क नहर तक है, कार्य आरम्भ करना शेष है। इस परियोजना की कुल लागत 10.00 करोड़ रुपये है और अब तक इस पर 1.25 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

आगे यह भी विश्वास है कि पवित्र सरस्वती नदी का रास्ता आगे पेहवा से कलायत क्षेत्र में है। सरस्वती नदी शोध संस्थान हरियाणा नामक एक गैर सरकारी संगठन पुरानी सरस्वती नदी के अपने बहने के पूरे रास्ते को पुनर्जिवित करने बारे भी रूचिपूर्वक सक्रिय है। इस विषय पर 22-10-2008 को कुरुक्षेत्र में एक संगोष्ठी (सेमिनार) का भी आयोजन किया गया था जिसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस

आयोग (ओ०एन०जी०सी०) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, भारत के भौगोलिक सर्वेक्षण तथा अन्य भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। इसके पश्चात यह निर्णय लिया गया कि अन्वेषण के उद्देश्य से कलायत के निकट कपिल मुनि मंदिर के क्षेत्र में दो कुओं की खुदाई की जायेगी ताकि पवित्र सरस्वती नदी के रास्ते की खोज की जा सके। कुओं की खुदाई हेतु तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ०एन०जी०सी०) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहयोग से भू-भौतिकी एवं भू-विद्युत सम्बन्धी सर्वेक्षण का कार्य कर रहा है।

Recarpeting of Road

*** 1134. Shri Sher Singh :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state the time by which the recarpeting of Jind and Jind-Bhiwani roads is likely to be done?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान् जी, इन सड़कों पर रिकार्पेटिंग 30.6.2009 तक पूर्ण होने की संभावना है।

Constituency Development Fund for M.LA's

***1140. Dr. Sita Ram :** Will the Finance Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide constituency development fund to the MLA's on the pattern of Central Government Scheme for MP's?

वित्त मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह) : नहीं श्रीमान् जी।

Creation of posts for Palwal District

***1051. Sh. Karan Singh Dalal :—**Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) whether the Chief Secretary held any meeting for the purpose of creating department wise posts for newly created Palwal District in Haryana together with the date of meeting and the name of officers who attended the meeting along with details thereof?

(b) the action taken so far in the matter as stated in part (a) above;

(c) whether any officer is responsible for not taking action for the creation of posts as mentioned in part (a) above; and

(d) if so, whether any disciplinary action is required to be taken or has been taken against the officers who have not performed his/her part together with the details thereof?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हाँ श्रीमान जी, दिनांक 25.9.2008 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जिला पलवल के लिये पद सृजन करने बारे बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें निम्न अधिकारियों ने भाग लिया;

1. श्री के०एस० भौरिया, आई०ए०एस०, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, हरियाणा।
2. श्री जी० प्रसन्ना कुमार, आई०ए०एस०, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, हरियाणा।
3. श्री एल०एस०एम० सालिन्स, आई०ए०एस०, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा।
4. श्री कृष्ण मोहन, आई०ए०एस०, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, कृषि विभाग, हरियाणा।
5. श्री मानिक सोनावाणे, आई०ए०एस०, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, हरियाणा।
6. श्री अजीत एम० शरण, आई०ए०एस०, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग, हरियाणा।
7. श्री आर० जाखू, आई०ए०एस०, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा।
8. श्री समीर माथुर, आई०ए०एस०, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, हरियाणा।
9. श्री डी०एस० ढेसी, आई०ए०एस०, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, नगर एवं शहरी आयोजना विभाग, हरियाणा।
10. श्री एन०के० जैन, आई०ए०एस०, वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, मत्स्य विभाग, हरियाणा।
11. श्रीमती नवराज सन्धु, आई०ए०एस०, एस०जे०ई० विभाग, हरियाणा।
12. श्री वाई०एस० मलिक, आई०ए०एस०, आयुक्त एवं सचिव, ई०आई०टी० एवं औद्योगिक विभाग, हरियाणा।
13. श्री एस०एस० प्रसाद, आई०ए०एस०, आयुक्त एवं सचिव, तालमेल विभाग, हरियाणा।
14. श्री अरुण कुमार, आई०ए०एस०, निदेशक, औद्योगिक विभाग, हरियाणा।
15. श्री अनुराग रस्तौगी, आई०ए०एस०, शिक्षा आयुक्त, हरियाणा।
16. श्री श्रीकान्त वाल्गड, आई०ए०एस०, निदेशक ग्रामीण विभाग, हरियाणा।
17. श्री आलोक राय, आई०पी०एस०, डी०आई०जी०, ट्रेनिंग, हरियाणा।

18. श्री सी०आर० राणा, आई०ए०एस०, उपायुक्त, पलवल।
19. श्री ओ०पी० सिंह, आई०पी०एस०, निदेशक, खेल, हरियाणा।
20. श्री एस०के० धर, अतिरिक्त पी०सी०सी०एफ०, वन विभाग, हरियाणा।
21. श्री ओ०पी० गोयल, उप सचिव, गृह विभाग, हरियाणा।
22. श्री एम०आर० शर्मा, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा।
23. डा० सत्यवीर सिंह, निदेशक बागवानी विभाग, हरियाणा।
24. डा० ओ०पी० यादव, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, हरियाणा।
25. श्री आर०के० धवन, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरियाणा।
26. श्री एस0पी0 अरोड़ा, अतिरिक्त श्रम आयुक्त, हरियाणा।

(ख) विभिन्न विभागों में 179 नये पद स्वीकृत किये गये हैं। कुछ विभागों द्वारा 44 पद आन्तरिक समायोजन से जिला पलवल में अन्य जिलों से भरे जाने हैं। इसके अतिरिक्त 159 पद सृजन करने के लिये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) नहीं, श्रीमान जी।

(घ) नहीं, श्रीमान जी।

Construction of Stadium

*** 1044. Sh. Radhey Shyam Sharma :-** Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state:—

(a) the time by which the construction work of Netaji Subhash Chander Bose Stadium at Narnaul City will be completed; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Mini Stadium at Village Nangal Dargu of Narnaul Assembly Constituency?

वन राज्य मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) :

(क) श्रीमान जी, वर्ष 1999 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम सम्पूर्ण हो गया था। दिनांक 27/03/1999 को तत्कालीन मुख्य मन्त्री चौ0 बन्सी लाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चार-दिवारी, पैविलियन, 300 मीटर, ऐथैलैटिक्स ट्रेक, बास्केटबाल कोर्ट, वालीबाल कोर्ट, क्रिकेट पिच, अभ्यास क्रिकेट पिच, बैडमिन्टन कोर्ट, कबड्डी खेल मैदान, बाक्सिंग रिंग व स्टेज विकसित की गई है। सिन्थेटिक लान-टैनिस कोर्ट का कार्य प्रगति पर है और यह 31/03/2009 तक पूरा हो जायेगा।

(ख) नहीं, श्रीमान।

Repair of Roads

***1153. Sh. Mahender Partap Singh :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the condition of following roads is very bad in Mewla Maharajpur Constituency:-

(i) from Kheri bridge Faridabad to Badshahpur Bhupani road;

(ii) from Kheri bridge to Mawai village;

(iii) from Badshapur Bhupani road to Wazirpur village;

(iv) from Tigaon road to Mirzapur;

(v) from Tigaon to Neemka;

(vi) from Sohana road to Alampur and Kot village;

(vii) from Agwanpur to Vasantpur;

(viii) Kanwara Rajpur road;

(ix) from Bharat Colony, Faridabad to Kheri Kalan; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the said roads in near future?

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : (क) तथा (ख) श्रीमान जी, इन सड़कों की स्थिति निम्न प्रकार से हैं:—

(i) से (iii) इन सड़कों की मरम्मत के लिए निविदाएं 13.2.2009 को खोली जाएंगी।

(iv) इस सड़क को सुदृढ़ करने का कार्य 19.12.2008 को पहले ही मैसर्ज पाहुजा स्टोन क्रैशर वर्क्स को आबंटित हो चुका है।

(v) यह सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से सम्बन्धित है तथा 200 मीटर लम्बाई को छोड़कर जो जमीनी झगड़े के कारण लम्बित है, की मरम्मत कर दी गई है।

(vi) यह क्वैरी सड़क है जिसमें बड़े सुधार की आवश्यकता है। इस सड़क की 2009-10 के दौरान मरम्मत करने की संभावना है।

(vii) 4.50 कि०मी० की कुल लम्बाई में से 1.2 कि०मी० लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क) से सम्बन्धित है तथा अच्छी हालत में है। बाकी हिस्सा हुडा के पास है, जिन्होंने बताया है कि इसकी मरम्मत के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(viii) मरम्मत का कार्य 25.01.08 को मैसर्ज गावर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को आबंटित हो चुका है तथा 31.3.09 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ix) यह सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से सम्बन्धित है तथा मरम्मत का कार्य ठेकेदार को आबंटित हो चुका है जिसके शीघ्र पूरा होने की संभावना है।

Mr. Speaker : Hon'ble Members now the question hour is over.

राजकीय महाविद्यालय सैक्टर-2 पंचकूला के विद्यार्थियों का अभिनंदन

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूंगा कि गवर्नमैंट कालेज, सैक्टर-2, पंचकूला के छात्र-छात्राएं दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं। अध्यक्ष महोदय, हर रोज किसी न किसी कालेज के विद्यार्थी इस सदन की कार्यवाही को देखने के लिए आते हैं। ये देश की अगली पीढ़ी हैं जैसा मैने पहले भी कहा था कि इन्हीं में से इस सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदेश और देश की प्रगति और उन्नति में विशेष रचनात्मक भूमिका निभानी है। मैं पक्ष और विपक्ष के साथियों से सादर आग्रह करूंगा कि आपका आचरण इन सब छात्र-छात्राओं के जीवन में एक आदर्श के रूप में है इसलिए इस बात का अवश्य ख्याल रखें।

अनुपस्थिति संबंधी सूचना

15.00 बजे **Mr. Speaker :** Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received a letter from Smt. Kartar Devi, Health Minister, dated 16th February, 2009, vide which she has informed that she will not be able to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha, as the P.G.I. doctors have advised her complete rest for a few days.

Hon'ble Members I am also to inform the House that I have received an intimation from Shri Anil Thakkar, Parliamentary Secretary, Revenue, dated 16th February, 2009 vide which he has informed that due to marriage of his relative he would not be able to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha on 16th February, 2009.

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Parliamentary Affairs Minister will lay papers on the Table of the House.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House-

The Haryana Private Universities (Amendment) Ordinance, 2008 (Haryana Ordinance No. 3 of 2009).

The Haryana Private Universities (Amendment) Ordinance, 2009 (Haryana Ordinance No. 4 of 2009).

विधान सभा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Smt. Geeta Bhukal, MLA, Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the Thirty Second Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2008-2009.

Smt. Geeta Bhukal : (Chairperson, Committee on the Welfare of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes): Sir, I beg to present the Thirty Second Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2008-2009.

नई आबकारी नीति के संबंध में मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will make a statement regarding Excise Policy of 2009-10.

Finance Minister (Shri Birender Singh) : Speaker Sir, keeping in view the Parliamentary tradition and practice, cabinet has taken a decision on the excise policy of 2009-10 and before the policy goes to the press, I think it is my duty to bring it on the floor of the House and to the notice of the august House. Speaker Sir, regarding the salient features of the new policy of excise, I want to narrate it like this that the Policy for this year is a step forward of the land-mark excise regime brought out in 2006-07. The guiding principles of the policy are:

- to give choice to the citizens i.e. people who drink responsibly should be able to excise their preference.
- revenue maximization to garner resources for the State's development.
- to encourage responsible drinking habits and create an environment of regulation of consumption of alcohol.
- to provide legal, decent and dignified premises for sale and consumption of alcohol and alcoholic beverages.
- to wean people away from higher strength alcohol to low content alcohol such as wine, beer and ready to drink beverages.
- to stamp out sale of spurious liquor which endangers human life.

Speaker Sir, after 2006-07, we adopted the policy of decentralization of retail network, end of monopoly and providing legal employment avenues to the unemployed youth of the State has been the basis of the Excise Policy for the last few years. Resultantly, State has gained the maximum in terms of revenue which has increased by over Rs.500 crore since 2004-05. In 2004-05 the total revenue from excise was Rs. 1013 crore which has gone to Rs. 1500 crore in 2008-09.The new excise policy which we have brought today also ensures and also meets the twin objectives of control of the consumption and maximization of revenue without putting unreasonable restriction on an adult citizen's freedom of choice. The following are the salient features of the excise policy, 2009:-

- Allotment of vends by inviting sealed tenders.
- Sealed tenders for each vend will be invited from general public about 25 years of age in a transparent manner.

We have provided reservation for L-14 and L-2 vends. There is 15% reservation for the vends i.e. 10% reservation for the Scheduled Castes and 5% reservation for the Backward Classes-A category, which has been done for the first time in the history of Haryana. We have provided reservation for those sections of the Society, who were not very much involved in this commercial activity. This would give lot of opportunities to these sections of the society. Sir, the number of vends have been reduced from 3800 to 3500. We have reduced the number of vends quite substantially. Sir, one more very glaring example of the intention of the Government is to see that no vend would be opened in the villages where Kanya Gurukuls are functioning.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, अगर ये वैंड नहीं खोलेंगे तो लोग सब वैंड खोल लेंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कन्या गुरुकुल जहाँ पर होंगे वहाँ किसी गाँव में वैंड खोलने की हम इजाजत नहीं देंगे तो सब वैंड खोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। Sir, for the first time we have levied VAT on the sale of liquor i.e. only on wholesale licenses. At one point VAT would be levied. The number of sale hours for shops or the vends have been reduced from April to October and we have reduced one hour for this period. In the winter we have reduced the number of hours for two hours i.e. from November to March. To encourage cultivation for barley, a cash crop, a fund has been created. About Rs. 10 crores shall be placed at the disposal of the Agriculture Department to introduce and encourage barley cultivation by the farmers of Haryana, especially by the farmers of south Haryana. (Interruptions). Bar license fee has also been rationalized i.e. Rs. 6 lakhs in Panchkula, Faridabad, Gurgaon and Yamunanagar. In the rest of the Districts, the license fee has been fixed at Rs. 4 lakhs. New pub license fee for beer and wine in the form of L-10E is Rs. 3 lakhs in Yamunanagar, Panchkula, Gurgaon, Sonepat, Faridabad, Hisar, Panipat and Karnal and in rest of the Districts, it would be Rs. 2 lakhs only. So, these are the some landmarks and some salient features of the new excise policy. Sir, with this we hope that from Rs.1500 crores revenue, which we collected through excise policy last year, in the next year i.e. 2009-2010, the revenue would be about Rs. 2000 crores. This would be another substantial increase. Sir, Haryana may be one of the first State where we have taken the steps and where social conditions and social requirements were taken into consideration जो हमारा अगले साल का फाईनैंशियल ईयर है उसमें हमें ऐक्साईज से 500 करोड़ रुपये अधिक मिलने की सम्भावना है और इस साल भी हमारे जो बजट ऐस्टिमेट्स थे उनसे ज्यादा 150 करोड़ रुपये सरकार के खजाने में दिये हैं। इस पोलिसी को भी हमने रैशनैलाईज़ किया है। हमने सबसे पहले फैसला लिया था कि हम शराब की मोनोपली नहीं बनने देंगे जो कि पहले सालों में रही है। हम ने उसको तोड़ा है और इफैक्टिवली तोड़ा है। हमने उसको और आगे नहीं बढ़ाया है। पहले शराब की दुकानों की ऑक्शन होती थी। इस ऑक्शन के बारे में हमने यह सोचा कि because auction may not be a full-proof method. हमने उसको लॉटरी सिस्टम से इन्ट्रोड्यूस किया। इस बार हम नये सिरे से हर दुकान के टैंडर ईशु करेंगे और जिसका टैंडर सबसे ऊपर होगा उसको वह दुकान मिलेगी। आन्ध्र प्रदेश में इस पॉलिसी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं उसको देखते हुए हमने यह बेहतर समझा कि हम शॉप्स की अलॉटमैंट टैंडर के जरिये करें। धन्यवाद।

वर्ष 2009-2010 के लिए बजट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the general discussion on the budget estimates for the year 2009-2010 will take place. (विघ्न) अब श्री के०एल० शर्मा बजट पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, आपसे यह रिक्वैस्ट है कि बोलने के लिए सबसे पहले हमारी पार्टी के लोगों को समय मिलना चाहिए। सर, यदि आप चाहें तो इस बारे में आप माननीय बीरेन्द्र सिंह जी से पूछ लें।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो इनसे यह पूछें कि इनके लीडर कहां हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आपके लीडर ही यहां पर नहीं है तो हम क्या करें। (विघ्न) क्या उनको सदन में आते हुए शर्म आती है?

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, अभी तक यह परम्परा रही है कि विपक्ष के किसी सदस्य को बजट पर सबसे पहले बोलने देना चाहिए। (विघ्न)

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं है आप इनको पहले बोलने का मौका दे दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हम विपक्ष को बोलने का मौका देना चाहते हैं लेकिन ये लोग सही ढंग से नहीं सोचते हैं। (शोर एवं व्यवधान) क्या आप लोग वाकआउट के लिए भूमिका बना रहे हैं? (विघ्न) डॉ० सीता राम आपके नेता सदन में क्यों नहीं आते हैं लोगों ने उनको चुन कर भेजा है। जब माननीय मुख्य मन्त्री जी घोषणा कर रहे थे तो आप लोगों ने सुझाव भी दिया था।

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, मेरी यह रिक्वैस्ट है कि परम्पराओं का पालन किया जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, एक बात तो यह है कि अगर आपको बजट पर पहले बुलवाएंगे तो आप कितना टाईम लेंगे। लेकिन आप लोग बोलने के बाद फौरन सदन से बाहर चले जाते हैं। अगर आपने बाहर जाना है तो उसका भी कोई तरीका होना चाहिए या तो आप लोग वाकआउट करेंगे या आप कोई प्रोटैस्ट करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर सर, XXX XXX XXX

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। जो ये बोल रहे हैं वह रिकार्ड न करें। (शोर एवं व्यवधान) डॉक्टर साहब, ऐसा है कि अगर कोई मैम्बर हाउस में नहीं आता है तो उसकी तरफ से रिक्वैस्ट आती है कि इस कारण से वह हाउस में नहीं आ सकता या वह बीमार है। आपके नेता को लोगों ने चुनकर भेजा है लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए चुन कर भेजा है जिस तरह की उनकी एबसैंस है that is condemnable.

डॉ० सीता राम : यह कोई जरूरी भी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जरूरी क्यों नहीं है, लोगों ने उनको चुन कर भेजा है। जनता ने जनहित के मुद्दे उठाने के लिए उनको चुन कर भेजा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सर, हम लोग मुद्दे उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दो भूतपूर्व मुख्य मन्त्री हैं, और 12-12, 13-13 साल मुख्य मन्त्री रहे हैं उनको चाहिए कि वे लोग सरकार और सदन को चलाने में कुछ सुझाव दें लेकिन they are not serious. How can you strengthen the peoples' democracy? पीपल डैमोक्रेसी को कैसे मजबूत करेंगे। (विघ्न) आप सभी बैठ जाएं मैं सभी को बुलवाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

XXX चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Dr. Sita Ram : Sir may, I Continue? सर, सी०एम० साहब भी कह रहे हैं कि बोलने दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष महोदय, इनसे पहले तो हमारा इंडिपैंडेंट्स सदस्यों का हक बनता है। पहले हमें बोलने का समय दें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : आप पहले अपना सिम्बल तो लेकर आएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश यादव : सिम्बल क्या होता है। (शोर एवं व्यवधान) सिम्बल की क्या बात कर रहे हो। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पहले इन्डीपैंडेंट्स को बोलने का समय दें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Shri Balwant Singh Sadhaura will open the Budget Speech.

Dr. Sita Ram : Sir, I will speak. मैंने नाम दिया हुआ है।

Dr. Sushil Indora : Sir, we have authorized Dr. Sita Ram. अध्यक्ष महोदय, मैंने और सीता राम जी ने अपना नाम लिखकर भेजा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, आपने कहां अथोराईज किया है? आपने लिखकर नहीं भेजा। इन्होंने लिखकर भेजा है। एज ए डिप्टी लीडर आपने नहीं भेजा है।

डॉ० सीता राम : सर, आपने मेरी कंसैंट ली थी और आपने कहा था कि आप मुझे बुलवाओगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सीता राम जी, मैंने बजट पर बोलने के लिए कहा था पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपसे ओपन करवाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सर, मेरे से ओपन करवाने में दिक्कत क्या है। हम भी अच्छे विचार प्रकट करेंगे, अच्छे सुझाव सरकार को देंगे।

श्री अध्यक्ष : आपने यह नहीं कहा था कि मैं ओपन करूंगा। आपने यह कहा था कि मैं बजट पर बोलूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सर, सबसे पहले मैंने अपने नाम की पर्ची भिजवाई है। (शोर एवं व्यवधान) सर, सदन के नेता जी ने भी कह दिया है कि मुझे बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके नेता कहां हैं। क्या सदन की जिम्मेवारी के अलावा कोई और जिम्मेवारी भी है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सर, हम प्रदेश की बात करेंगे। अपनी बातें करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चलो ठीक है। बलवन्त सिंह सढौरा जी बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सर, हम जिम्मेवारी से बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान) हम अच्छे सुझाव सदन में देना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मैं सभी को पूरा समय दूंगा और हर सदस्य को बोलने का समय दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) ऐसा न हो कि अपनी बात बोलने के बाद आप कागज उठा कर भाग जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : सर, आप जानबूझ कर ऐसी बात न करें। (शोर एवं व्यवधान) आप हमें बोलने का समय तो दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चलो ठीक है, सीता राम जी आप बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम (डबवाली अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने हरियाणा सरकार का 13 फरवरी, 2009 को वर्ष 2009-10 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किया है। मैं यहां पर बैठा देख रहा था कि जब उन्होंने बजट अनुमान प्रस्तुत किया था तो उनके चेहरे से बहुत ही मायूसी झलक रही थी। (शोर एवं व्यवधान) सर, वित्तमंत्री जी के बोलने का एक ही दिन होता है और उस दिन जो घोषणाएं वित्तमंत्री जी ने बजट में करनी होती हैं, वित्तमंत्री जी ने जो बातें कहनी होती हैं। मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं * * *

Mr. Speaker: Nothing to be recorded.

डॉ० सीता राम : सर, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बिल्कुल चुनावों को नजदीक देखकर चुनावी घोषणाएं की गयी। अगर ये चुनावी घोषणाएं नहीं थीं तो इनके लिए बजट में रुपयों का प्रबन्ध किया जाता लेकिन ऐसा कोई प्रबन्ध बजट के अंदर नहीं किया गया और न ही मेरे ख्याल से चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को पता था। अगर पता होता तो वे इन योजनाओं के लिए रुपयों का बजट में प्रबन्ध जरूर करते।

श्री फूलचन्द मुलाना : स्पीकर साहब, क्या ये उन घोषणाओं पर ऐतराज करते हैं कि ये क्यों की गयीं ?

डॉ० सीता राम : स्पीकर साहब, मैं ऐतराज नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि इस साल लोक सभा चुनाव नजदीक आने के बाद चूंकि यह आखिरी बजट है इसलिए घोषणाएं की गयी नहीं तो ये चार साल पहले भी ऐसी घोषणाएं कर सकते थे।(विघ्न) सर, अब मैं जो वित्तीय प्रबन्धन है,राजस्व प्राप्तियाँ हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। वर्ष 2006-07 से लेकर 2009-10 तक परसैंटेजवाइज रैवेन्यू रिसीट गिर रही है। वर्ष 2006-07 में जो रैवेन्यू रिसीट का इंक्रीज था वह 29 परसैंट था इसके बाद वर्ष 2007-08 में रैवेन्यू रिसीट घटकर 29 परसैंट से 17 परसैंट हो गई। इसी तरीके से वर्ष 2008-09 के अंदर परसैंटेजवाइज रैवेन्यू रिसीट घटकर दस परसैंट हो गई। वर्ष 2009-10 में जो प्रपोज किया गया है, अनुमान लगाया गया है उसके अंदर रैवेन्यू रिसीट तीन परसैंट हो जाती है। इसको देखकर लगता है कि सरकार का जो वित्तीय प्रबन्धन है वह ठीक नहीं है क्योंकि रैवेन्यू रिसीट घट रही है। इसी तरह से जो प्लान एक्सपैंडीचर है, वर्ष 2009-10 में राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्षों के मुकाबले में बढ़ोत्तरी केवल 3 परसैंट हुई जो टोटल 666.40 करोड़ रुपये बनती है। जो योजनागत प्लान खर्च है वह वर्ष 2008-09 के मुकाबले में केवल 35 परसैंट अधिक है जबकि सरकार कहती है कि हमने दुगणा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यह ऐक्चुअल में रिवाइज्ड के अनुसार केवल 35 परसैंट अधिक है क्योंकि केवल 2905 करोड़ रुपये ही अधिक खर्च होंगे। राजस्व प्राप्तियाँ केवल 666.40 करोड़ रुपये हैं। इसको देखकर लगता है कि यह खर्च कहां से होगा। यह तो आने वाले साल में पता चलेगा कि कहाँ से यह प्रबन्ध किया जाएगा ? राजस्व घाटा साल शुरू होने पर 55.41 करोड़ रुपये रैवेन्यू सरप्लस के साथ शुरू हुआ। जो रैवेन्यू डैफिसिट है वह 3384.06 करोड़ रुपये है। अगर इसके अंदर यह 55.41 करोड़ रुपये भी जोड़ दें तो प्रदेश का घाटा बढ़कर 4139.47 करोड़ रुपये हो जाता है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

अगर इसके अंदर 6th पे कमीशन की रिकमंडेशंज मूल रूप में टोटल लागू की जाएं तो यह घाटा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रदेश का घाटा बढ़ रहा है इसलिए इस बजट को सरकार का एक अच्छा मैनेजमैंट नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से वर्ष 2007-08 का जो फिस्कल डैफिसिट है राजकोषीय घाटा है यह 1213.85 करोड़ रुपये था जोकि वर्ष 2008-09 में बढ़कर 3708.15 करोड़ रुपये हो गया और वर्ष 2009-10 के अंदर यह बढ़कर 8557.40 करोड़ रुपये हो गया **(इस समय सभापतियों की सूची में से माननीय सदस्य श्री शादी लाल बतरा पदासीन हुए)** सभापति महोदय, कहने का यह भाव है कि राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। हमारी सरकार के समय में वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा था और उस समय के फाइनैंस मिनिस्टर चौ.संपत सिंह जी थे उस समय केन्द्र के जो फाइनैंस मिनिस्टर थे उन्होंने यह कहा था कि हरियाणा प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है। लेकिन इस बजट में इन कारणों को देखते हैं और इन घाटों को देखते हैं तो यह लगता है कि हरियाणा प्रदेश कंगाली की तरफ जा रहा है और यहां पर जिस तरह से घाटा बढ़ रहा है, उससे विकास कार्य नहीं हो सकते। किसी भी स्टेट का गैर योजनागत खर्च और नॉन प्लान ऐक्सपैंडीचर जब बढ़ रहा होता है और प्लान ऐक्सपैंडीचर घट रहा होता है तो उसके वित्तीय प्रबंधन को अच्छा नहीं कहा जा सकता। जब मैं इस सरकार के वित्तीय प्रबंधन को देखता हूं तो जो गैर योजनागत खर्च था, उसमें 4 परसैंट की बढ़ौत्तरी है और वर्ष 2009-10 में देखता हूं तो गैर योजनागत खर्च में 14 परसैंट की बढ़ौत्तरी है जो कि लगभग 2500 करोड़ रुपये बनती है। इसका परिणाम यह होगा कि इसका सीधा असर प्रदेश की योजनाओं पर पड़ेगा और जो विकास के काम चल रहे हैं वे पूरे नहीं हो पाएंगे। इससे प्रदेश में विकास की गति थम जाएगी। इसी प्रकार से जो कंसोलिडेटेड राजस्व प्राप्तियां हैं उनमें टैक्स रिवेन्यू का योगदान वर्ष 2007-08 के मुकाबले में वर्ष 2009-10 में 22.4 परसैंट उसमें इंक्रीज है और वर्ष 2009-10 में वर्ष 2008-09 के मुकाबले में यह 2 परसैंट रह जाएगी। इसी प्रकार से जो कुल प्राप्तियां है उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वह पब्लिक डैट का है। वर्ष 2008-09 के अंदर वह 2420 करोड़ रुपये है जो कि वर्ष 2008 के मुकाबले में 2009-10 में 71 परसैंट अधिक हो जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश सिर्फ जो पब्लिक डैट है उसके बल पर विकास कार्य करने में सक्षम है। इसी तरीके से जो सेल्ज टैक्स की बिक्री है उसमें वर्ष 2008-09 में वर्ष 2007-08 के मुकाबले में 20 परसैंट बढ़ौत्तरी है और वर्ष 2009-10 में यह घटकर 9 परसैंट रह गई। स्टेट ऐक्साइज की घोषणा आज की गई और नतीजा पहले दे दिया कि इसके अंदर 1700 करोड़ रुपये की इन्क्रीज होगी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : 1700 करोड़ रुपये की इन्क्रीज नहीं है बल्कि 2000 करोड़ रुपये की इन्क्रीज का अनुमान है।

डॉ० सीता राम : नये के हिसाब से यह इन्क्रीज 2000 करोड़ रुपये बताई है। यह मेरी समझ में नहीं आया है।

श्री मांगे राम गुप्ता : यह अनुमान लगाया जाता है।

डॉ० सीता राम : इसी प्रकार से पैसिंजर पर गुड्स टैक्स वर्ष 2007-08 में 924 करोड़ था और वर्ष 2008-09 में घटकर 485 करोड़ रुपये रह गया और वर्ष 2009-10 में घटकर यह 425 करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार से समाज सेवाओं से जो प्राप्तियां हैं वह वर्ष 2007-08 में 1222 करोड़ रुपये थी, वर्ष 2008-09 में बढ़कर 2000.03 करोड़ रुपये हो गई और वर्ष 2009-10 में वह घटकर 1495.05 करोड़ रुपये रह गई हैं। पब्लिक टैक्स का जो योगदान है वह वर्ष 2008-09 में 3971 करोड़

[डॉ० सीता राम]

है और जो विकास के कार्यों में योगदान है। वर्ष 2008-2009 में 3971 करोड़ रूपये और वर्ष 2009-10 में यह बढ़कर 9508.51 करोड़ रुपये हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है जो लगभग अढ़ाई गुणा इन्क्रीज है। पढ़ोगे तो यह पता चलता है। इसी प्रकार से स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के लिए वर्ष 2008-09 में 991 करोड़ रुपये से 336 करोड़ रुपये हो गया है और वर्ष 2009-10 में स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का योगदान सिर्फ 100 करोड़ रुपये हो गया है। क्योंकि स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत केन्द्र की सरकार से 100 प्रतिशत तक सस्ती ब्याज पर आप लोन ले सकते हैं। जोकि प्रदेश के विकास में सहायक हो सकता है यह भी आपका घट रहा है। आज जो other loans हैं जिसमें वर्ष 2007-2008 के अन्दर 2003.02 करोड़ रुपये और वर्ष 2008-2009 में 2004.03 करोड़ रुपये और वर्ष 2009-10 के अन्दर जो इन्क्रीज हुआ है वह 5212.85 करोड़ रुपये हो गये हैं जो तकरीबन अढ़ाई गुणा ज्यादा है। कुल कन्सोलिडेटिड फण्ड में जो प्राप्तियां हुई हैं और ऋणों का जो योगदान है वह 14720.51 करोड़ रुपये है जो टोटल लोन जमा पब्लिक डैट के 45.67 प्रतिशत बनता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि मैं प्रजैन्ट की चिन्ता करता हूं मैं फयूचर की चिन्ता नहीं करता। इस बजट को देखकर लगता है कि इस बजट में सिर्फ प्रजैन्ट की चिन्ता की गई है फ्यूचर की चिन्ता नहीं है क्योंकि सरकार को यह लगता है कि सरकार का जनाधार खिसक रहा है इसलिए जाते-जाते प्रदेश के खजाने को लुटाने पर लगे हुए हैं। काम जो अधूरे हैं यह रिकार्ड की बात है कि वे काम पूरे नहीं होंगे। हमारी सरकार ने तो सरपल्स खजाना छोड़ा था।

श्री के० एल० शर्मा : चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। वर्ष 2004-05 में जब पिछली सरकार ने बजट छोड़ा था वह सिर्फ 2933 करोड़ रुपये का रेवेन्यू लौस था जबकि डाक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार सरपल्स बजट छोड़कर गई थी। माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ी घटिया बात हो नहीं सकती।

डॉ० सीताराम : चेयरमैन साहब, जो कन्सोलिडेटिड फण्ड से जो खर्च हुआ है उसमें सिंचाई योजनाओं पर वर्ष 2007-2008 में 1062.35 करोड़ रुपये , वर्ष 2008-09 में 865.76 करोड़ रुपये और वर्ष 2009-10 के अन्दर 871.32 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इससे सिंचाई योजनाओं के लिए पैसा लगातार घट रहा है। इसको देखकर लगता है कि जो भी सिंचाई की योजनाएं हैं वे इस सरकार के कार्यकाल के लिए पूरी नहीं होंगी। दूसरा, मुझे यह भी पता चला है क्योंकि मैंने क्वैश्चन के माध्यम से सरकार से पूछा है कि भाखड़ा मेन कैनाल से क्या हरियाणा स्टेट अपने हिस्से का पूरा पानी ले पा रहा है। मंत्री जी ने प्रश्न काल के दौरान अपने जवाब में यह कहा है कि हम भाखड़ा नहर से पूरा पानी नहीं ले पा रहे हैं। इस सरकार के चार साल के कार्यकाल में सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया कि वह 2000 क्यूसैक से ज्यादा पानी ले सके हम कम पानी ले पा रहे हैं। बल्कि नई नहरें खोदी जा रही हैं परन्तु उनके लिए पानी कहां से आयेगा। सरकार यह बताने में सक्षम नहीं है। इसी तरीके से मैंने सुना है कि मेवात में एक नई नहर खोदने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हांसी-बुटाना लिंक नहर खोदी गई लेकिन अगर उसकी पहले परमिशन ली जाती। तो यह दिक्कत और कठिनाई नहीं होती और आज प्रदेश के लोगों को सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी मिलना शुरू हो जाता लेकिन सरकार ने सिर्फ जल्दबाजी और राजनीति करने के लिए इस प्रकार के कार्य किए। सभापति महोदय, एस० वाई० एल० का नाम ही भूल गए। नई नई नहरों का नाम जरूर लेते हैं।

श्री सभापति : सीताराम जी, आप बजट पर बोलें।

डॉ० सीताराम : सभापति महोदय, सिंचाई योजना बजट का ही हिस्सा है। सर, मैं डिपार्टमैंट वाइज बोल रहा हूं इसलिए मुझे बोलना तो पड़ेगा ही।(विघ्न) सभापति महोदय, इंडस्ट्रीज का वहां बड़ा शोर मचाया जाता है कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत पैसा दे रही है। जब आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि इंडस्ट्रीज के लिए वर्ष 2007-08 में 252.67 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। वर्ष 2008-09 में यह बजट घटकर 143.66 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2009-10 के बजट में यह 64.78 करोड़ रुपये हो गया है। वैसे तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन जब इस बजट को देखते हैं तो पाते हैं कि यह बजट लगातार घट रहा है। सभापति महोदय, इस प्रकार से इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वर्ष 2008-09 में ट्रांसपोर्ट का जो बजट था वह 150.21 करोड़ का था। आज प्रदेश में बसिज की हालत बहुत खस्ता है। बहुत सी बसिज बिना टायर और ट्यूब्स के हैं और मैंटीनैंस न होने की वजह से खड़ी हैं। सभापति महोदय, मेवात के अंदर आज भी मैंने पढ़ा है कि बसिज की स्थिति अच्छी नहीं है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थिति अच्छी नहीं है। वर्ष 2009-10 में इसका बजट 109.25 करोड़ रखा गया है यानि बजट और घटा दिया गया है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से कैसे परिवहन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। एग्रीकल्चर एण्ड एलायंस सर्विसिज के अंदर जो कहा जाता है कि आज एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत कार्य कर रही है जबकि बजट के अंदर हम देखते हैं तो वर्ष 2008-09 में इसका बजट 412 करोड़ था और वर्ष 2009-10 में इसके बजट में सिर्फ 15 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई। लेकिन ये अखबारों में दिखावे के लिए अनेक तरह की बातें करते हैं। लेकिन इस बजट को देखकर नहीं लगता कि सरकार की मंशा ठीक है। रूरल डिवैल्पमैंट फण्ड के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने रूरल एरियाज को इग्नोर किया है। बजट में जो प्रावधान किया है उसके अनुसार देखें तो वर्ष 2008-09 में रूरल डिवैल्पमैंट के लिए 623.50 करोड़ रुपये रखे गए थे जबकि अर्बन एरियाज के लिए 385 करोड़ रुपये रखे गए थे। वर्ष 2009-10 में रूरल फण्ड 625 करोड़ रुपये रखा गया हैं यानि सिर्फ 2 करोड़ रुपये बढ़ाए गए हैं जबकि अर्बन डिवैल्पमैंट फण्डस जो बढ़ाए गए हैं वे 385 करोड़ से 1334 करोड़ रुपये किए गए हैं। इसको देखकर लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि रूरल एरियाज में डिवैल्पमैंट हो। क्योंकि अगर आज रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं करेंगें तो पूरी तरह से डिवैल्पमैंट नहीं हो सकेगा। शहरों के ऊपर तो पहले ही दबाव बहुत है। आज जो नौजवान पढ़े लिखे हैं वे सारे शहरों की तरफ भाग रहे हैं। हमें इस पलायन को रोकना है तो हमें ग्रामीण इलाके के अंदर ज्यादा पैसे खर्च करने होंगें और वहां ज्यादा सुविधाएं देनी होंगी। हमें छोटी इंडस्ट्रीज वहां लगानी चाहिएं लेकिन इस बजट को देखकर नहीं लगता कि यह सरकार इस तरफ कोई ध्यान दे रही है। ग्रामीण लोगों के प्रति फंड्स देने के मामले में सरकार का जो रवैया है इसको सरकार को सुधारना चाहिए। कंसोलिडेटिड फण्ड्ज में पैसा कहां-कहां से आ रहा है इस बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि सेल्ज टैक्स में वर्ष 2008-09 में एक रुपये में से 37.65 पैसा सेल्ज टैक्स से आता था और वर्ष 2009-10 में घटकर 33.32 पैसे ही सेल्ज टैक्स का योगदान रह गया। इस तरह से स्टेट एक्साईज की बात करें तो वर्ष 2007-08 के दौरान 6.02 पैसे एक रुपये में से योगदान था। वह भी वर्ष 2008-09 में घटकर 5.71 पैसे रह गया तथा वर्ष 2009-10 में और घटकर 5.28 पैसे रह गया है। चेयरमैन सर, इसी तरह से यदि स्टैम्प डयूटी की बात करें तो इसमें भी कमी आई है। वर्ष 2007-08 में 8.12 पैसे का योगदान

[डॉ० सीता राम]

स्टैम्प ड्यूटी का एक रुपये में से था। उसके बाद वर्ष 2008-09 में घटकर 8.08 पैसे रह गया और यदि 2009-10 के आंकड़े देखें तो यह बहुत ज्यादा घटकर 3.80 पैसे का योगदान एक रुपये में से रह गया है। इन सभी आंकड़ों से जाहिर होता है कि सरकार का जो टैक्स रैवेन्यू का योगदान है वह घट रहा है। इसी तरह से यदि पब्लिक डैट की स्थिति देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2008-09 में 15.28 पैसे था और वर्ष 2009-10 में बढ़कर 29.50 पैसे हो गया है जिससे लगता है कि सरकार केवल कर्ज के सहारे ही चल रही है। (विघ्न) चेयरमैन सर, यदि कैंसोलिडेटिड फण्ड जो पावर सैक्टर के लिए दिया गया उसकी बात करें तो वर्ष 2007-08 में एक रुपये में से 14.34 पैसे पावर सैक्टर के लिए दिए गए। इसी तरह से वर्ष 2008-09 में 13.36 पैसे दिए गए और वर्ष 2009-10 में घटकर 11.59 पैसे एक रुपये में से पावर सैक्टर के सुधार के लिए दिए जायेंगे। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि सरकार पावर सैक्टर में सुधार नहीं कर पायेगी क्योंकि हर साल पैसे कम होते जा रहे हैं। सरकार एक तरफ तो बड़े-बड़े वायदे कर रही है और ढिंढोरा पीट रही है कि हम पावर सैक्टर में यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं और आने वाले थोड़े दिनों में पावर की समस्या दूर हो जायेगी। लेकिन जिस हिसाब से पावर सैक्टर में कम पैसे दिए जा रहे हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार बिजली की समस्या दूर कर देगी। आज के दिन हमारे प्रदेश में बिजली की बहुत कमी है और मुझे नहीं पता कि सरकार पैसा कम करके पावर सैक्टर में किसी प्रकार से अपनी योजनाओं को पूरा करने में सक्षम होगी। मुझे इस बारे में बहुत चिंता है, डाउट है कि ये लोग पावर सैक्टर में पैसा कम करके किस प्रकार से लोगों की बिजली की समस्या दूर करेंगे।

चेयरमैन सर, यदि सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के बारे में भी मंत्री जी बड़ा प्रचार करते हैं कि हमने सिंचाई के लिए यह कर दिया वह कर दिया और हम नई नहर बनवा रहे हैं। यदि देखें कि एक रुपये में से कितना पैसा सिंचाई के लिए सरकार खर्च कर रही है तो सरकार की असलियत सामने आ जायेगी। वर्ष 2007-08 के दौरान 6.25 पैसे सिंचाई के लिए एक रुपये में से दिए गए थे। उसके बाद यह पैसा घटकर वर्ष 2008-09 में 5.50 पैसे ही रह गया। (विघ्न) उसके बाद वर्ष 2009-10 में यह घटकर केवल 5.00 पैसे ही रह गया है। चेयरमैन सर, एक तरफ तो मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सिंचाई की नई योजनाएं बनायेंगे और नई नहर भी बनवायेंगे और दूसरी तरफ सिंचाई योजनाओं के लिए पैसे हर साल कम कर रहे हैं। आज प्रदेश में पानी नहीं है, पैसे भी कम कर दिए गए और ग्राउंड वाटर भी प्रदेश में बहुत नीचे चला गया है जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मुझे नहीं मालूम कि सरकार किस प्रकार से प्रदेश के लोगों के लिए पीने के पानी और सिंचाई के पानी की व्यवस्था कर पायेगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रदेश को बहुत बड़ी समस्या पानी को लेकर होगी यदि सरकार इसी प्रकार से कार्य करेगी।

चेयरमैन सर, यदि वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन की बात करें तो इसमें भी वर्ष 2007-08 में 5.10 पैसे एक रुपये में से दिए गए। यह पैसा वर्ष 2008-09 में घटकर 4.68 पैसे रह गया और वर्ष 2009-10 में घटकर 4.31 पैसे रह गया है। इस प्रकार वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन में भी हर साल पैसा कम हो रहा है। सभापति महोदय, वाटर सप्लाई और सैनीटेशन विभाग के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आज हमें गांवों और शहरों में गन्दगी के ढेर लगे हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा पीने के पानी की भी कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और विशेषकर गर्मियों के मौसम में तो टूटियों में पानी आता ही नहीं। सभापति महोदय, यह बात तो आपको भी माननी होगी कि मलेरिया, चिकन गुनिया और

कैंसर जैसी बीमारियां भी गंदगी से फैलती हैं। खास तौर पर जब वर्षा का मौसम होता है तो ये गंदगी के ढेर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जिससे प्रदेश में बीमारियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है।

Mr. Chairperson : Mr. Sita Ram, please wind up.

डॉ० सीता राम : चेयरमैन सर, मैंने तो कोई टाईम वेस्ट नहीं किया।

Mr. Chairperson : Mr. Sita Ram, I agree, you are not wasting the time, but we have to divide the time among all the Members. Every Member has right to speak.

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य सीता राम जी जो यह कह रहे हैं कि इरीगेशन का बजट कम हुआ है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004-05 में इरीगेशन का वार्षिक बजट 252 करोड़ रुपये था जो कि इस बार 2009-10 में बढ़कर 862 करोड़ रुपये हो गया है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य गलत जानकारी देकर हाऊस को मिसलीड कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सभापति महोदय, सोशल वैल्फेयर विभाग के अन्दर एक रुपये में से जो खर्च होना था वह वर्ष 2007-08 में 5.12 पैसे था, जो वर्ष 2009-10 में घटकर 3.99 पैसे रह गया। सोशल वैल्फेयर डिपार्टमैंट एक ऐसा विभाग है जहां पर गरीब तबके के लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनती हैं इसको देखकर ऐसा लगता है कि उनके लिए बजट में कम पैसे का प्रावधान किया गया है। बी०पी०एल० फैमलीज़ में से कितने मेन स्ट्रीम में आये हैं ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। बी०पी०एल० फैमलीज़ तो बढ़ रही हैं किन कारणों से बढ़ रही हैं मैं इसकी चर्चा में नहीं जाऊंगा लेकिन उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनके लाईफ स्टाईल को ऊपर उठाने के लिए कितने लोगों को रोजगार मिला है। कुल मिलाकर इसके अन्दर हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जो राज्य की देनदारियां हैं उसमें वर्ष 2008-09 के अन्दर 32 हज़ार 203 करोड़ और अब वर्ष 2009-10 के अन्दर ये बढ़कर 39 हज़ार 654 करोड़ हो गई हैं। इन सबको देखकर लगता है कि सरकार पर हर साल कर्जा बढ़ रहा है। जहां तक सबसिडी का सवाल है सरकार द्वारा यह कहा गया है कि हमने प्रत्येक सैक्टर को बहुत ज्यादा मात्रा में सबसिडी दी है। जब हम वर्ष 2008-09 के दौरान दी गई सबसिडी को देखते हैं तो वह 3264.67 करोड़ और वर्ष 2009-10 के अन्दर वह सबसिडी घटकर 3055.61 करोड़ रह गई। वैसे हमारे वित्तमंत्री जी कहते हैं कि हम पावर सैक्टर के अन्दर बहुत ज्यादा सबसिडी दे रहे हैं। पावर सैक्टर को जो सबसिडी दी गई है वह 2778.43 करोड़ रुपये है जबकि पावर कम्पनीज़ ने जो सबसिडीज़ की डिमाण्ड की है वह 9200 करोड़ की है। अगर 2778.43 करोड़ रुपये को 9200 करोड़ में से घटा दें तो बैलेंस रह जाता है 6423 करोड़ रुपये। इस प्रकार से 6423 करोड़ रुपये या तो सरकार सबसिडी दे और अगर सरकार सबसिडी नहीं देगी तो बिजली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे जिससे आम उपभोक्ता प्रभावित होगा। इस बारे में भी सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं सिक्सथ पे कमीशन की बात करना चाहता हूं। देश के दूसरे प्रदेशों जैसे राजस्थान और यू०पी० के अन्दर वहां की सरकारों ने बिना कोई फेर-बदल किए जो भी सिक्सथ पे कमीशन की सिफारिशें थी उनको एज़ इट इज़ लागू कर दिया। जो सैंट्रल पे कमीशन ने रिकमण्डेशन दी थी उनमें किसी प्रकार की कोई अनोमली नहीं थी लेकिन यहां पर एक कमेटी बनाकर उसमें अनॉमलीज़ पैदा कर दी गईं। किसी कर्मचारी को डी-ग्रेड कर दिया गया और किसी को किसी बैंड में डाल दिया गया। अब मैं डाक्टर्ज़ की बात करता हूं जो डाक्टर्ज़ हैं उनको जो एन०पी०ए० मिल रहा था।

Mr. Chairperson : Dr. Sita Ram, is it a part of budget ?

Dr. Sita Ram : Yes Sir, it is a part of budget. Sir this is the part of the Finance Department अगर फाईनैंस डिपार्टमैंट ने उसको फाईनैन्स करना है तो पार्ट क्यों नहीं हुआ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : डॉ० सीता राम जी, मैं सही कह रहा हूँ समय कम है। आपका टाईम पूरा हो रहा है। आप वाइंड अप कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : ठीक है सर, मैं वाइंड अप कर लूंगा। यह बजट से संबंधित ही है। डॉक्टर्स का जो एन०पी०ए० था वह सिर्फ मैडिकल कॉलेज में दिया गया है। पहले वह 25 परसैंट मिलता था उसको सरकार ने घटा कर 15 परसैंट कर दिया है। डैंटल डॉक्टर्स का एन०पी०ए० भी घटाकर 25 परसैंट से 15 परसैंट कर दिया है। इसी प्रकार से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का एन०पी०ए० भी 25 परसैंट से घटाकर 15 परसैंट कर दिया गया है। इसी प्रकार से इंजीनियर्स, ड्राइंग टीचर्स, पी०टी०आई० इत्यादि बहुत सी पोस्टें हैं जिनके साथ छठे वेतन आयोग में भेदभाव हुआ है। सरकार को उस कमेटी को हटाकर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को एज इट इज ऑरिजनली लागू करना चाहिए। सभापति महोदय, अगर यह सरकार लागू नहीं करेगी तो मैं यह कहता हूँ कि हमारी सरकार आने पर हम छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को उसके कम्पलीट वे में लागू करेंगे यह मेरा कर्मचारी भाईयों को आश्वासन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : वह समय अभी नहीं आया है। आपका समय समाप्त हो रहा है। No, that is no way. (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : सभापति महोदय, यह बजट का ही हिस्सा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : डॉक्टर सीता राम जी, आपका 40 मिनट का समय बीत चुका है। Nothing to be recorded. (शोर एवं व्यवधान) सढौरा जी, आपका मैम्बर बोल रहा है, उसको बोलने दो। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सभापति महोदय, आम लोगों को जो दिक्कत है मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) (इस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य अपनी सीटों से उठकर बोलने लगे।)

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है। आपको बोलते हुए 40 मिनट हो गये हैं। (शोर एवं व्यवधान) हाँ जी, के.एल. शर्मा जी, आप बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री के०एल० शर्मा : सीता राम जी, आपका टाईम समाप्त हो गया है अब आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : सभापति महोदय, आप तो कह सकते हैं लेकिन शर्मा जी कैसे कह सकते हैं कि आपका टाईम समाप्त हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सभापति महोदय, अभी मुझे पता चला है खनन एवं भूसंरक्षण में ....

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, * * * *(शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

श्री सभापति : डॉ० इन्दौरा, आप अपने आपको रोकें तथा अपनी सीट पर बैठ जाईये। यह कोई तरीका नहीं है। This is not the way. (Noise & interruptions) Nothing to be recorded. (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, * * * * *

श्री सभापति : डॉ० इन्दौरा, प्लीज आप अपनी सीट पर बैठिये।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, * * * * *

Mr. Chairman : Dr. Indora, I warn you. This is not the way.

डॉ० सीता राम : सभापति महोदय, मैं बजट पर बोल रहा हूँ, फिर भी नहीं बोलने देते। प्रजातंत्र में भी आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते। जब आपकी मंशा ही यह है कि हमें बाहर भेज दिया जाये तो भेज दो। हम तो अच्छे सुझाव दे रहे हैं फिर भी नहीं सुनना चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : डॉक्टर सीता राम जी, आपके सजैशन का हम वैलकम करते हैं लेकिन आपके मैम्बर ही आपको नहीं सुनना चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : खनन एवं भू संरक्षण विभाग का मैं जिक्र करता हूं क्योंकि इसका प्रदेश के लोगों के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध है। उन्होंने एक सिंडिकेट बना लिया है जिससे प्रदेश के अन्दर रेते के भाव 40 परसैंट तक इन्क्रीज हो गये हैं और बजरी तथा क्रैशर के भाव भी बहुत ज्यादा इन्क्रीज हो गये हैं। सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए ताकि बजरी, रेत सीमैंट आदि आम आदमी को सस्ता और टाईम पर मिल सके। (विघ्न) मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इसी प्रकार से करप्शन फ्री ऐन्वायर्नमैंट की बात की जाती है। (विघ्न) सभापति महोदय, करप्शन के बारे में कहना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री सभापति : डा० सीता राम जी, आपको बोलते हुए 45 मिनट हो गये हैं इसलिए अब आप वाइंड अप कीजिए। (विघ्न)

डॉ० सीता राम : सभापति महोदय, 15-20 मिनट का समय तो वैसे ही टोका-टाकी में खराब कर देते हैं। मेरी यह रिक्वैस्ट है कि आप मुझे दस मिनट का समय और दे दें मैं इन दस मिनटों में अपनी बात समाप्त कर लूंगा। (विघ्न)

श्री सभापति : डा० साहब, अब आप वाइंड-अप करें।

डॉ० सीता राम : सभापति महोदय, लोकायुक्त की जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उसमें लिखा हुआ है कि लोकयुक्त जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ लिख कर भेजते हैं लेकिन कम्पिटैंट अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। चेयरमैन सर, नियम के अनुसार तीन महीने में उनके खिलाफ ऐक्शन टेकन रिपोर्ट आनी चाहिए लेकिन 3-3, 4-4 साल तक फाईलों के अन्दर ही मामले लटके रहते हैं। इस बारे में जो कानून है उसमें तीन महीने के अन्दर ऐक्शन टेकन रिपोर्ट लोकायुक्त को भेजी जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए इस मामले को सीरियसली देखना चाहिए

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

[डॉ० सीता राम]

क्योंकि इससे भ्रष्टचार को बढ़ावा मिलेगा। अगर सरकार इस बारे में सीरियस है तो उसे इस रिपोर्ट को सीरियसली लेना चाहिए। सभापति महोदय, इसी प्रकार से जो एच०सी०एस० नॉमिनेट किये गये हैं और आई०ए०एस० की जो रिकमेंडेशन सरकार ने भेजी है उसके अन्दर बड़ा भारी घपला हुआ है। (विघ्न)

श्री सभापति : सीता राम जी, यह बजट का पार्ट नहीं है किसके साथ क्या घपला हुआ यह बजट का पार्ट नहीं है आप बजट पर बोलें (विघ्न एवं शोर)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : चेयरमैन सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। आई०ए०एस० और एच०सी०एस० की सिलैक्शन के बारे में माननीय साथी बात न ही करें तो ही अच्छा है क्योंकि यह सारा मामला इनके नेता से जुड़ा हुआ है और मामला इनके नेता के खिलाफ सी०बी०आई० में गया है। जे०बी०टी० टीचर्ज से ले कर एच०सी०एस० अधिकारियों की नियुक्ति का मामला सी०बी०आई० में है। (विघ्न)

Mr. Chairman : Dr. Sita Ram Ji, you confined to budget only. (Interruptions)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सभापति महोदय, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में एच०सी०एस० के एग्जाम और नियुक्तियां कैसे की जाती थी यह सर्वविदित है। (विघ्न) Chairman Sir, I am on a point of order with your permission. (Interruptions) चेयरमैन सर, मैं अपने काबिल साथी को बताना चाहूंगा कि ये एच०सी०एस०, आई०ए०एस० का सिलैक्शन और टीचर्ज की सिलैक्शन की बात न ही करें तो ठीक रहेगा। हिन्दी की एक कहावत है कि छाज तो बोले ही बोले छलनी भी बोले जिसमें हजार छेद हैं। (विघ्न एवं शोर) चेयरमैन सर, किस प्रकार से इनमें घपला हुआ है, यह सबको पता है। (विघ्न एवं शोर)

श्री बलवन्त सिंह : चेयरमैन सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (विघ्न)

श्री सभापति : प्वायंट ऑफ आर्डर की कोई बात नहीं है। एक ही समय पर तीन-तीन आदमी खड़े हो गये हैं। पहले आप लोग यह बात तो डिसाईड कर लें कि कौन बोलेगा क्योंकि आप तीन-चार आदमी खड़े हैं। (विघ्न) Please take your seats.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : इनकी सरकार के समय में एच०सी०एस० की सिलेक्शन की गई तो यह प्रश्न पूछा गया कि देश का प्रधान मन्त्री कौन है तो कैंडीडेट ने उसका नाम ओम प्रकाश चौटाला बताया। उस कैंडीडेट को 20 नम्बर दिये गये। चेयरमैन सर, कोर्ट ने यह सारा रिकार्ड देखा है और इनकी पोल खुल चुकी है। (विघ्न) हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में किस प्रकार से मैम्बर के दामाद की नियुक्ति की गई, इनके पिछलग्गू कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां की गईं। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की रिकमैंडेशन पर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सस्पैंड किया गया। (विघ्न एवं शोर)

डॉ० सीताराम : चेयरमैन सर, क्या यह प्वायंट आफ आर्डर है?

श्री सभापति : डा० सीता राम जी, माननीय मन्त्री जी एक्सपलेन कर रहे हैं इसलिए आप अभी बैठिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : चेयरमैन सर, किस तरह से हजारों अध्यापकों की भर्ती की गई और किस तरह से चौटाला जी और उनके पुत्र ने रातों-रात लिस्ट बदलवा दी (विघ्न एवं शोर) 16.00 बजे चेयरमैन सर, जिस प्रकार से खुरापाती बातें इन्होंने कही हैं तो मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भर्तियां इनके समय में हुई है वह सबको पता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : * * * * । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : डाक्टर सीता राम जी, आप ऐसी बात नहीं करें। (शोर एवं व्यवधान) ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं करें। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आप क्या चाहते हैं ?

डॉ० सीता राम : * * * * । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : डाक्टर सीता राम, आपकी बजट पर स्पीच खत्म हो गई है। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं हो रहा है।

डॉ० सीता राम : * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : चेयरमैन सर, इन्होंने जो भी बातें कहीं है वह सब अनर्गल बातें कहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : ** * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : इन्दौरा जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप बिना इजाजत के कैसे बोल रहे हैं ? (शोर एवं व्यवधान) आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं इसलिए आपका कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : ** * * *।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : * * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : आप सभी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) Mr. Indora, is it the way to speak in the House ? (शोर एवं व्यवधान) Please take your seat. (शोर एवं व्यवधान) I warn you Mr. Indora. (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : ** * * *।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री सभापति : आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप बाहर जाना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : चेयरमैन सर, मैं प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान) Dr. Shaib, I am on point of order. आप मेरी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान) चेयरमैन सर, मैं आपकी अनुमति से अपने काबिल साथियों को बताना चाहता हूं कि ये जो बातें कह रहे हैं उनके माध्यम से ये सदन को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। इनको बजट पर बोलते हुए अपने अच्छे सुझाव देने चाहिए ताकि सरकार उस पर विचार करे। चेयरमैन सर, मैं सदन में कहना चाहता हूं कि पहले चाहे एक्सियन की सिलैक्शन हुई हो, जे०बी०टी० की सिलैक्शन हुई हो . . . . (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : चेयरमैन सर, यह क्या प्वायंट आफ आर्डर है ? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : चेयरमैन सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : चेयरमैन सर, क्या प्वायंट आफ आर्डर पर प्वायंट आफ आर्डर हो सकता है ? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : * * * *।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : * * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : * * * * *। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : चेयरमैन सर, क्या प्वायंट ऑफ आर्डर पर भी प्वायंट आर्डर होता है ?

श्री बलवन्त सिंह सढौरा : सभापति महोदय, * * *(शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : बलवन्त सिंह, आप बैठे।(शोर एवं व्यवधान) डॉ० सीता राम जी, आप भी बैठें। Please take your seat. Dr. Indora, I warn you. Why are you standing?

Shri Randeep Singh Surjewala : You have told them. Sir, he cannot take the time of the House. You have given time to Shri K.L. Sharma. Dr. Sita Ram cannot take the time of the House any longer.

डा० सीता राम : सभापति महोदय, * * *

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, he cannot be permitted to mislead the House. (interruptions)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Chairperson : Parliamentary Affairs Minister is on his legs. He is on a point of order. So, let him speak first. (interruptions) I warn you, Dr. Indora.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : चेयरमैन सर, आपने मुझे प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलने के लिए टाईम दिया है। ये घबरा क्यों रहे हैं ? मैं इनके बारे में कुछ कहने वाला नहीं हूं। (शोर एवं व्यवधान) मैं इनके लीडर का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं ओम प्रकाश चौटाला की कोई बात नहीं कहूंगा। (शोर एवं व्यवधान) I am asking your time on a point of order, Sir.

डॉ० सीता राम : सभापति महोदय, * * *(शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, you have given me time to speak on a point of order. So, he has to yield. (interruptions) Your direction has to be honoured.

श्री सभापति : डा.साहब, आपके सारे मैम्बर्ज एक साथ खड़े हुए हैं। आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सभापति महोदय, * * *

श्री सभापति : सीता राम जी, आप बैठिए। आपको बोलते हुए एक घंटा हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : चेयरमैन सर, आपने मुझे बोलने के लिए परमिट किया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : सर, आपने मुझे बोलने के लिए खड़ा किया हुआ है।(शोर एवं व्यवधान)

Mr. Chairperson : Parliamentary Affairs Minister is on a point of order and he wants to explain on point of order. Let him speak first. (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Sushil Indora : Sir, he has to explain but not to give the speech.

Shri Randeep Singh Surjewala : I have to explain only, not to give the explanation.

Mr. Chairperson : Dr. Indora, are you the only Member in this House? Why are you interrupting again and again? (interruptions)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : चेयरमैन सर, मैं केवल आपकी अनुमति से अपने काबिल सदस्य को इतना ही कहना चाहता था कि वे सदन को गुमराह न करें। चेयरमैन सर, जो नियुक्तियों का प्रश्न है नियुक्तियों के मामले में कौन गोलमाल कर रहा था, कौन अनियमितताएं कर रहा था ? (शोर एवं व्यवधान) अभी मैंने इनका नाम नहीं लिया है इसलिए ये ऐसे खड़े न हों। कौन उसमें हेराफेरी कर रहा था? (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ० सीताराम : चेयरमैन सर, क्या यह प्वायंट ऑफ आर्डर है ? आप हमें बोलने नहीं देते हैं, हमें समय भी दिया जाता है और बोलने भी नहीं दिया जाता है। हमारा स्पीकर भी बंद कर दिया जाता है और हमें बोलने भी नहीं दिया जाता है।(शोर एवं व्यवधान) हम केवल दो शब्द ही बोलते हैं और ये प्वायंट ऑफ आर्डर पर खड़े हो जाते हैं। हमें अपनी बात पूरी कहने नहीं दी जाती है क्योंकि ये उससे पहले ही खड़े हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि हमारा टाईम खत्म हो गया है।

श्री सभापति : डाक्टर सीता राम जी, आप बैठिए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : चेयरमैन सर, एक कहावत है कि चोर की दाड़ी में तिनका। इनको क्यों चिंता है कि मैं चौटाला साहब का नाम लेने जा रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह : स्पीकर साहब, क्या यह इनका प्वायंट ऑफ आर्डर है ?

Mr. Chairperson : The Minister is on the point of order. He is speaking. Let him speak.

डॉ० सीता राम : ये तो आधे घण्टे से खड़े हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : यह तो चोर की दाड़ी में तिनका वाली बात है। ये इतने सारे सदस्य यहां पर खड़े हैं इनको यह चिंता क्यों है कि मैं चौटाला जी का नाम लेने वाला हूं। ये क्यों डर रहे हैं ? हो सकता है कि मैं उधर इशारा कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं बी.जे.पी. के सदस्यों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी मंशा क्या है ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Mr. Chairman Sir, you have to protect my voice. He has to sit down. He can not keep running commentary. चेयरमैन सर, किसने अनियमितताएं की, किसने हरियाणा के नौजवानों के हकों के साथ कुठाराघात किया और एच.सी.एस.अधिकारियों व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति में किस प्रकार से भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार फैलाया गया। किस प्रकार से जे.बी.टी. अध्यापकों की पूरी की पूरी लिस्ट एक मुख्य मन्त्री और उनके पुत्र के कहने से बदली गई। यह बात पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : इस बारे में जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही हो जाएगी। उस बात का जिक्र ये पिछले चार साल से करते आ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Chairperson : The Minister is speaking. Let him speak. (interruptions)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, ये नियुक्तियों में घोटाले की बात कर रहे हैं। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मैंने उनका नाम नहीं लिया।

Mr. Chairperson : Dr. Sita Ram do not compel the Chair. (interruptions) The Minister is on his legs. (interruptions) इस सदन के कुछ नॉर्म्स हैं। उन नॉर्म्स और मर्यादाओं को कायम रखा जाए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : चेयरमैन सर, ये बैठते ही नहीं हैं। ये तो लैग्स पर ही रहते हैं। हमें तो यहां बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : चेयरमैन सर, किस तरह से अंग्रेजी के पेपर का जवाब हिन्दी में दिया गया और हिंदी के पेपर का जवाब अंग्रेजी में दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह सारा मामला देखा है और देख कर के देश के राष्ट्रपति ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Chairperson : Dr. Sita Ram, please do not loose the grace. You should have the grace. (interruptions) Let him give the reply. You will get the opportunity. (interruptions) **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)**

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, you have permitted me. Speaker Sir, I am on a point of order. अध्यक्ष महोदय, 35 मिनट से ये एक ही लाइन सुनते हैं और 8-9 सदस्य खड़े हो जाते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ये बात कर रहे थे भर्तियों में घोटाले की। (शोर एवं व्यावधान)

Mr. Speaker : Please maintain the decorum of the House. Please maintain the peace and decorum of the House. Now the Parliamentary Affairs Minister is on the point of order. Please listen him. (interruptions)

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, what is the meaning of this running commentary? How can he be permitted for this in the House ? (interruptions) This is only one point of order I am trying to make. अगर ये सुन लें तो मैं केवल एक बात कह रहा हूं। मेरे काबिल दोस्त डॉ० सीता राम आई०ए०एस० ओफिसर्ज की सिलेक्शन में अनियमितताओं की बात कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : ये आई०ए०एस० ओफिसर्ज की सिलैक्शन के बारे में बात कर रहे थे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आई०ए०एस० ओफिसर्ज की जो नॉमिनेशन एच०सी०एस० से होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी जब चेयरमैन सर चेयर पर थे उनकी अनुमति लेकर मैं इन्हें बताना चाहता था कि किस प्रकार से इस प्रान्त में हजारों-हजारों नौजवानों के साथ नियुक्तियों में उनके हकों के साथ कुठाराघात किया गया। जे०बी०टी० के सिलैक्शन में किस प्रकार से एक आई०ए०एस० आफिसर को प्रताड़ित किया गया और हजारों अध्यापकों के नाम की लिस्ट रातों-रात एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बनाने के लिए बदली गई। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल से ये यही बात कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : पब्लिक सर्विस कमीशन ने किस प्रकार से हेराफेरी की। यह सारा मामला आज सी.बी.आई. के पास गया हुआ है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Yes, I do agree. (Interruptions) It is a subjudice matter. (Interruptions). Please maintain the decency. You are a learned man.

डॉ० सीताराम : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मुझे बोलने का मौका ही कहां दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना जो पहले सिरसा और महेन्द्रगढ़ जिलों से शुरू की गई थी जिसको शायद अब सभी जिलों में आरम्भ कर दिया गया है। इस योजना के तहत भी बहुत सी

[डॉ० सीता राम]

बेकायदगियां हो रही हैं। मस्टर रौल के अन्दर उन नामों को शामिल कर दिया जाता है जो कि हकीकत में काम नहीं करते हैं। यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से ही होता है। जो काम व्यक्तिगत तौर पर करवाने चाहिये थे वे काम मशीनों से करवाये जाते हैं। तालाब और जोहड़ जो खोदे जाते हैं वे ऐसी जगहों पर खोदे जाते हैं जहां न तो नहर का पानी पहुंच सकता है और न ही बारिश का पानी पहुंच पाता है। इस प्रकार से इस योजना के तहत कोई स्पेसिफिक कार्य आईडैंटिफाई नहीं हैं कि कौन से काम होने चाहिएं और उनकी क्वालिटी क्या है और यह नहीं देखा जा रहा कि काम सही हो रहे हैं या नहीं। यह बड़ी भारी दिक्कत हो रही है जबकि इस स्कीम के तहत सभी जिलों में काम हो रहा है। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। इस प्रकार से घपलाबाजी हो रही है और प्रदेश का बड़ा भारी पैसा खर्च हो रहा है लेकिन सही मायने में जरूरत मंद लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को सीरियसली देखा जाए। अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। अभी जो मुझे पता चला है कि प्रदेश में 12-13 हजार जे०बी०टी० अध्यापकों की पोस्टें इस साल ही खाली हो रही हैं और पहले भी प्रदेश के अन्दर अध्यापकों की बड़ी भारी कमी है। गैस्ट टीचर्ज जो लगा रखे हैं उन पर भी कच्चा होने के कारण हमेशा तलवार लटकती रहती है। यह एक सीरियस मामला है। इस प्रकार से प्रदेश के अन्दर छात्र अपनी पढ़ाई नहीं कर पायेंगे। पहले से शिक्षा का स्तर प्रदेश में गिर रहा है। जो ड्राप-आउट रेट है वह भी कण्ट्रोल में नहीं हो पा रही है। मैंने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : आपके हिसाब से ड्राप आउट के लिए क्या स्टैप्स लेने चाहिएं, आप बतायें।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो टीचर्ज की कमी को पूरा किया जाना चाहिए और यह कोशिश की जानी चाहिए कि टीचर्ज रेगुलर स्कूलों में रहें। जो बच्चे ड्राप-आउट होते हैं उनके घरों में जाकर उनके परिवार के सदस्यों से बात करके और काउंसलिंग करके उन बच्चों को स्कूल में आने के लिए दोबारा से प्रेरित किया जाना चाहिए। जो दिक्कत और कोई कठिनाई है उसको भी दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो सर्वेक्षण मैंने पढ़ा है उसमें हरियाणा प्रदेश स्कूलों में बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे देश में 23वें नम्बर पर है। इसलिए सरकार का जो स्कूलों में बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार की बहुत गुंजायश है। इसी प्रकार से यह भी आया है कि जो नर्सिंग स्कूल या कालेजिज खोले गये हैं।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, आपने कौन सी सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ी है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगेराम गुप्ता) : स्पीकर सर, माननीय साथी according to the survey report जो ये कह रहे हैं इसका मुझे नहीं पता कि ये कौन सी रिपोर्ट ले रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें पहले हरियाणा 19वें नम्बर पर था लेकिन जो अब सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें हरियाणा 7वें नम्बर पर आया है। जो भारत सरकार की सर्वे रिपोर्ट है।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी एक सर्वे रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष : चलो , डाक्टर साहब, आप वह सर्वे रिपोर्ट दिखा देना।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जहां तक डाक्टर सीता राम जी ने स्कूलों में ड्राप-आउट बच्चों के बारे में जिक्र किया है। यह बात मैं हाउस में विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमने यह महसूस

किया है कि जो बच्चे स्कूलों से ड्राप-आउट होते हैं वे ड्राप-आउट नहीं होने चाहिए इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल ड्राप-आउट को रोकने के लिए इतनी ज्यादा फैसीलिटीज दे दी कि अब इन बच्चों का ड्राप-आउट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की तादाद पहले से ज्यादा बढ़ी है। माननीय सदस्य गलतफहमी में न रहें।

डा० सीता राम : ग्रेस मार्क्स देकर पास किए जाते हैं इस प्रकार से प्रदेश की शिक्षा की स्थिति ऊंची नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से सर्व शिक्षा अभियान के तहत खरीद में कई घपले सामने आए। अखबार में खबर आई थी कि 5 करोड़ के पैंसिल बॉक्स विदआउट टैण्डर्ज खरीद लिए गए। टैण्डर्ज आमंत्रित नहीं किए गए बल्कि एक ही कम्पनी को आर्डर्ज दे दिए गए। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मिड-डे मील स्कीम में कई तरह के घपले हो रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा है तो सरकार को ऐसे घपलों की जांच करवानी चाहिए। इस प्रकार की बातें मैं सरकार के नोटिस में ला रहा हूं। अगर ऐसा है तो सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो पैंसिल बॉक्स की खरीद के मुद्दे के बारे में बताया तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जैसे ही सरकार के नोटिस में यह मामला आया हमने तुरन्त एक्शन लिया और उस आर्डर को कैंसिल किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलबंत सिंह सढौरा : ऐसा घपला हुआ है इस बात को तो आप एडमिट करते हो।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हमने यह खरीद होने ही नहीं दी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीताराम : अध्यक्ष महोदय, सरकार की बेकायदगियां जो मेरे नोटिस में आई उसके बारे में मैं सरकार को बताऊंगा ताकि उनके बारे में कार्यवाही हो सके।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगेराम गुप्ता : सीता राम जी, सरकार ने आलरेडी एक्शन ले लिया है। आप इसको बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो ? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, अब मैं कानून और व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, ये नरेगा के बारे में भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। ये जो कह रहे हैं उसका कोई तथ्य तो बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, ये माननीय साथी मेरे साथ चल पड़ें मैं इनको दिखा दूंगा कि नरेगा में क्या-क्या बेकायदगियां हुई हैं। इनको तो प्रोपर्टी डीलिंग करने से ही फुर्सत नहीं है। इनको तो नरेगा के बारे में पता ही नहीं है कि नरेगा क्या है।(शोर एवं व्यवधान) जौनपुरिया जी, मेरे साथ चल पड़ना, मैं आपको दिखा दूंगा कि नरेगा में क्या-क्या बेकायदगियां हुई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, please maintain the decorum and decency of the House.

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं अब कानून और व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं। आज स्टेट में कानून और व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है।

श्री अध्यक्ष : सीता राम जी, आपने 5 मिनट के लिए कहा था लेकिन आपको बोलते हुए 8 मिनट हो गए हैं। आप जल्दी वाइंड अप करें।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ कानून और व्यवस्था पर अपनी बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह तथ्य है कि वर्ष 2004-05 में जब हमारी सरकार थी उस समय 404 हत्याएं हुई और वर्ष 2008-09 में यह संख्या बढ़कर 790 हो गई, यह रिकार्ड की बात है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 में रेप केसिज की संख्या 404 थी और आज यह संख्या बढ़कर 547 हो गई है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार डकैती की संख्या पहले 40 के करीब थी अब वह संख्या 95 हो गई है। आज प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करता। पंचकूला जैसा डिस्ट्रिक्ट जो चंडीगढ़ के नजदीक है जहां पुलिस का पूरा प्रबन्ध है उसके बाद भी ज्वैलर्स को सरेआम लूटा जाता है। अध्यक्ष महोदय, एक घटना नहीं बल्कि ऐसी घटनाएं रोज हो रही है। मुख्यमंत्री का गृह जिला जो सबसे ज्यादा प्रोन है वहां रोज हत्याएं हो रही हैं। आज भी मैंने पढ़ा है कि झज्जर में 13 हत्याएं हो गई। भिवानी के अंदर हत्याएं हो गई। सरकार का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। गुड़गांव के अंदर जो कि एन०सी०आर० रीजन है। जहां पर चार-चार एस०पी० हैं वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। गुड़गांव में हर रोज अपहरण हो रहे हैं और रैनसम की घटनाएं हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आज के अखबार में पढ़कर आ रहा हूं कि सरकार कहती है कि हम प्रदेश को नम्बर एक प्रदेश बनायेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि वह प्रदेश नम्बर एक प्रदेश नहीं बन सकता जिस प्रदेश में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही हो, कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही हों। इसके अतिरिक्त मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों पर कोई कंट्रोल न हो रहा हो वह प्रदेश नम्बर एक प्रदेश नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक न हो और न ही बिजली की कोई व्यवस्था हो वह प्रदेश नम्बर एक प्रदेश निकट भविष्य में नहीं बन सकता। मौजूदा सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हमारा प्रदेश नम्बर एक प्रदेश बनेगा लेकिन सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान कोई प्रयास नहीं किया जिससे हमारा प्रदेश नम्बर एक प्रदेश बन सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह बजट लोग हितैषी नहीं है, इस बजट से प्रदेश के विकास को गति नहीं मिल सकती। यह बजट प्रदेश के लोगों के साथ एक छलावा है इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं। (विघ्न)

श्री के० एल० शर्मा (शाहबाद) : स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब यह बजट पेश किया गया था, मैं समझता था कि इस बजट ने आज के हालात को देखते हुए, आज हमारी जो वैश्विक आर्थिक मंदी को देखते हुए यह बजट पेश किया गया है और ये रियायतें दी गई। मैं समझता था कि इससे हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम ऊँचा हुआ है और विपक्ष के साथी भी इसके लिए एप्रीशियट करेंगे परन्तु सर, बड़े दुख की बात है, एप्रीशियट तो क्या करना, इनको शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसी बात कहते हैं जिनको सुनने से दुख होता है। आज दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों की आंखें लगी हुई हैं। स्पीकर सर, वे देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश वाकई ही एक ऐसा प्रदेश है जो इस मंदी से बिलकुल अछूता बचा

है। स्पीकर सर, आज एक मैसेज की जरूरत थी जो डर लोगों के दिमाग में छाया हुआ था आज इतनी बड़ी-बड़ी इकोनोमिज़ हैं, चाहे अमेरिकन इकोनोमी की बात ले लीजिए, चाहे जापान की इकोनोमी की बात ले लीजिए, चाहे चाईना की इकोनोमी की बात ले लीजिए, चाहे साऊथ कोरिया की इकोनोमी की बात ले लीजिए हर जगह पर अफरा-तफरी मची हुई है और हर जगह पर जी०डी०पी० गिर रहा है। ऐसे समय में केवल एक चीज ही उसका सोर्स बताया गया कि जोब्स को क्रिएट कैसे किया जाये। जोब्स को क्रिएट करने के लिए खर्चे की कैसे पूर्ति की जाए। स्पीकर सर, कांफीडेंस जनता के अंदर किस प्रकार से पैदा किया जाये। ये मैसेज कैसे दिया जाए कि हमारे यहां कोई मंदी का असर नहीं है। स्पीकर सर, यह सबसे पहला कार्य है। मैं एप्रीशियट करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को जिन्होंने बजट के साथ-साथ एक बात यह कही कि जिनको विपक्ष के साथी बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। बात को तोड़ मरोड़कर कहना इनकी आदत हो गई है। ये शोर मचा करके चले जाते हैं। स्पीकर सर, आपने कहा था कि सीता राम जी आप सुनकर जाना लेकिन मेरे भाई अपनी बात कहकर चले गये। मुझे लगता है डाक्टर सीता राम जी को सदन की कुर्सी काटती है। वैसे तो ये बड़े अच्छे आदमी हैं और मेरे साथ पी०ए०सी० में मैंबर भी हैं। (विघ्न) बलवंत सिंह जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप भी अच्छे आदमी हो। स्पीकर सर, ये जो बात अभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणाएं कर दी। ये ऐसा इसलिए कह रहे थे इसका असर मैं बताना चाहूंगा कि इनको इसलिए तकलीफ हो गई है कि इन्हीं के नाम से तो लोगों को बरगलाकर इन्होंने वोट मांगनी थी वो इनका मुद्दा हाथ से छिन गया। स्पीकर सर, झूठ बोलकर वोट लेना इनकी आदत हो गई है। स्पीकर सर, आपको याद होगा जब पहले चुनाव हुए थे तब हम गांव-गांव वोट मांगने जाया करते थे तो लोग हमारे से यह सवाल करते थे कि शर्मा जी कुछ लोगों ने हमसे यह बात कही है कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो तुम्हारी पैंशन बन्द हो जायेगी। स्पीकर सर, उस समय लोगों की आंखों में वाकई एक क्वैश्चन मार्क होता था। वे जब हमसे यह पूछते थे तो हमारे ऊपर उनकी इस बात का असर भी होता था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने पहले ही दिन यहां पर घोषणा करके यह सुनिश्चित किया कि ये जो हमारी पैंशन्ज हैं इनको बढ़ाया तो जा सकता है लेकिन किसी भी सूरत में कभी भी घटाया नहीं जायेगा और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैंशन को बढ़ाकर अपने कहे को सत्य साबित कर दिया है। स्पीकर सर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब कल मैं अपने हल्के के ढंगाली गांव में गया तो वहां पर एक सहेला नाम का हरिजन मेरे पास आया उसकी धोती फटी हुई थी, पगड़ी मैली थी और टूटी हुई लकड़ी उसके हाथ में थी, उसने मेरे पास आकर मुझसे पूछा कि शर्मा जी, क्या यह बात सत्य है कि हमारी पैंशन 500 रुपये प्रति मास हो गई है। इस पर मैंने उसको बताया कि यह बात बिलकुल सत्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसकी घोषणा की है। स्पीकर सर, इस पर वह यह कहने लगा कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे लिए तो परमात्मा बन गये। स्पीकर सर, इस प्रकार की बातें तभी निकलती हैं जब हमारे दिल में किसी के प्रति आदर का भाव होता है। वह कहने लगा कि आज हमारे लिए जीने की एक आशा पैदा हो गई है। स्पीकर सर, जैसे कि कहते हैं कि मोहब्बत में ये इंतहा हो गई कि मोहब्बत में हम उनको खुदा कह गये। स्पीकर सर, यह बात उसके मन की थी। उन्होंने यह बात इसलिए कही क्योंकि उसे दवाइयों की जरूरत पड़ती थी, उसको कपड़ों की जरूरत पड़ती थी इसलिए जब माननीय मुख्यमंत्री ने उनकी पैंशन बढ़ाई तो उसको यह लगा कि उसे अपने जरूरी खर्चों के लिए जो धन कम पड़ने लगा था उसकी कमी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पैंशन की राशि 500 रुपये प्रति मास करने से पूरी हो जायेगी और इससे

[श्री के० एल० शर्मा]

उसका गुजारा चल जायेगा। स्पीकर सर, इतना ही नहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए ऐसी ही राहतों की घोषणा की है। विपक्ष के साथियों को इसी बात की तकलीफ है कि हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिस पर हम मौजूदा सरकार की आलोचना कर सकें। स्पीकर सर, इसके अलावा विधवा पैंशन, विकलांग पैंशन और बारहवीं पास के बेरोजगारों के लिए पैंशन, स्नातक बेरोजगारों के लिए पैंशन इन सब में 250 से 300 रुपये का इज़ाफा किया गया है। स्पीकर सर, कुल मिलाकर यह 8 हज़ार करोड़ रुपये का इज़ाफा है। स्पीकर सर, मैं विपक्ष के साथियों से यह पूछना चाहता हूं कि अपने चार साल के शासनकाल के दौरान इन्होंने 8 हज़ार करोड़ रुपये के टोटल बजट पेश किये थे फिर ये किस आधार पर ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने केवल 3500 करोड़ रुपये का इज़ाफा किया है ? क्या इनमें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है ? ये झूठ बोलते हैं कि 4000, 4500 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 2009-10 के लिए 11000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। ये केवल 3500 करोड़ रुपये का बजट अपने मुंह से मान रहे हैं। स्पीकर सर, मैं विपक्ष के साथियों की हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूं कि अपने समय में ये क्या चीज़ थे। स्पीकर सर, अपनी सरकार के समय में इन्होंने चार बजट पेश किये थे। पहला बजट इन्होंने 2164.17 करोड़ रुपये का पेश किया था और वह खत्म हो गया 1766.87 करोड़ रुपये पर, दूसरा बजट इन्होंने पेश किया 2034 करोड़ रुपये का और वह खत्म हो गया 1776.19 करोड़ रुपये पर, तीसरा बजट इन्होंने पेश किया 2091 करोड़ रुपये का और वह बजट खत्म हुआ जाकर के 1865.79 करोड़ रुपये पर, चौथा और आखिरी बजट जिसे ये चुनावी बजट कहते हैं। स्पीकर सर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इनको चुनावी बजट पेश नहीं करना आता था ? पर पास में कुछ हो और बजट के बारे में कुछ जानकारी हो, बजट की कुछ समझ हो कि कहां से पैसा आयेगा और कहां पर पैसा जायेगा। आज ये यहां पर बात करते हैं कि Rupees come and Rupees go. ये सब भी ये पढ़कर ही बोल लेते हैं इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं पता।

श्री बलवंत सिंह : माननीय स्पीकर सर, मैं माननीय साथी से पूछना चाहता हूं कि जैसा कि ये बता रहे हैं कि वर्ष 2001 में 2000 करोड़ रुपये का और फिर 2100 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। मुझे मेरे काबिल साथी यह भी बतायें कि वर्ष 2001 में और आज के रेट्स में कितना डिफरैंस है। महंगाई कितने गुणा बढ़ी है और उससे लोग कितने बेबस और लाचार हुए हैं ?

श्री के०एल० शर्मा : बलवंत जी, आप मेरी बात धैर्य से सुनिए तो सही, मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, चार साल के अन्दर जो इनका टोटल बजट बना वह था 7517.10 करोड़ रुपये और उसमें इनके आखिरी बजट का घाटा 2933 करोड़ रुपये था। आज ये किस आधार पर हमारी सरकार के बजट के बारे में कह रहे हैं कि इससे घाटा होगा। अध्यक्ष महोदय, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन पता नहीं इनमें कैसी और कितनी चाबी भर दी जाती है कि ये उसी के मुताबिक चलते हैं जैसे कि 'जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना'। जो अच्छी तरह से बजट को समझता है वह भी आज यह बयान दे रहा है कि इस बजट से या तो टैक्स लगेंगे या इसको घाटे में पेश किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं डॉ० इन्दौरा से एक बात पूछना चाहता हूं वे यहां आकर यह बतायें कि जब 948 करोड़ रुपये का घाटा हमारी सरकार के सैकेण्ड बजट में हुआ था तब इन्होंने हमारे बारे में कहा था कि ये पूरे हरियाणा प्रदेश को रसातल में मिलाने जा रहे हैं। इस पर हमने कहा था कि थोड़ा इंतजार

करो और हमें थोड़ा काम करने दो। अध्यक्ष महोदय, हमें अपने काम को करना आता है और हमें यह भी पता है कि राजस्व को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार राजस्व को बढ़ाया जाता है, क्या-क्या एक्शन किये जाते हैं, एफ०आर०बी०एम० क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है इन लोगों को क्या पता ? फिजिकल रिस्पॉसिबिलिटिज बजट मैनेजमैंट आदि के बारे में इनको कोई ज्ञान नहीं है। जब हमने इनको कहा कि हमें काम करने दीजिये और अगले बजट में 948 करोड़ रुपये का इनका घाटा पूरा करने के बाद अगले ही साल 1200 करोड़ रुपये का अधिशेष का बजट पेश किया। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि किस बात की हम कैलकूलेशन इनको करके सुनाते हैं। उसके एक साल बाद हमारे बजट के बारे में सुन लें। वर्ष 2005-06 में इनके 2108 करोड़ के बजट के जस्ट बाद, सढौरा जी कह रहे हैं कि कीमतों में कितना फर्क पड़ गया ? अध्यक्ष महोदय, दो महीने के बाद, दो महीने में कितना फर्क पड़ता है। फरवरी 2005 को इलैक्शन हुआ था। हम फरवरी के लास्ट में आये थे। लेखानुदान के समय इनका 2108 करोड़ रुपये का बजट था और हमारा पहला ही बजट 48 से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ हमारे मुख्य मंत्री जी ने 3 हजार करोड़ रुपये का पेश करवाया था। हमारे वित्त मंत्री महोदय भी उस मीटिंग में गये थे। अध्यक्ष महोदय, काम करवाने का कोई ढंग होता है। बताना पड़ता है कि हम कौन से काम करेंगे, हमारी योजनाएं क्या हैं ? स्पीकर सर, हमें योजनाएं बनानी आती हैं, हमें राजस्व इकट्ठा करना आता है। केवल एक कटाक्ष करने की बात करें तो वह समझ में नहीं आती इसीलिए हम 3 हजार करोड़ रुपये का बजट लेकर आये। स्पीकर सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सारे देश की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई थी। अध्यक्ष महोदय, अमेरिका की जी०डी०पी० 13.5 मिलियन डॉलर है जो पूरे संसार की जी०डी०पी० का 30 प्रतिशत है। आज उनकी भी आँखें हमारी तरफ लगी हुई हैं। आज हमारा जो जी०डी०पी० है उसके साईज को देखा जाये तो अमेरिका भी मंदी की चपेट में है और उनकी ग्रोथ 3.2 प्रतिशत रह गई है लेकिन आज भी हमारी केन्द्र की जी०डी०पी० 9 प्रतिशत बताई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे भारतवर्ष की जी०डी०पी० आज साईज के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। I am not talking about the percentage ? I am talking about the size of growth. हिन्दुस्तान नम्बर 2 पर है। अमेरिका जो सबसे बड़ी इकॉनॉमी कही जाती थी वह आज नम्बर 63 पर पहुंच गई है। आज यह हमारे लिए बड़े फख्र की बात होनी चाहिए थी। आज हरियाणा कहाँ खड़ा है इस पर इनको फख्र होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, आज ये कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी ने घोषणाएं क्यों कर दी। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की गई घोषणा का तो इनको स्वागत करना चाहिए। उन्होंने कुछ दिया ही है कुछ लिया तो नहीं। स्पीकर सर, आप मेरे हल्के में ढोला माजरा में गये थे। आपने देखा वहाँ पर 100-100 गज के प्लाटों का जब आबंटन होना था तो जब हम वहाँ पर गये तो मैंने उन लोगों में इंथूजियाजम देखा। मैंने देखा कि वे बड़े जोश में हैं तो मैंने सोचा कि किसी बड़े लीडर को लाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको लेकर गया और आपने देखा होगा कि पूरे का पूरा गाँव ही नहीं ऐसा लगता था कि पूरा हरियाणा उठ कर आ गया हो। वहाँ पर 4-5 हजार लोग आये थे। आपके लिए वे एक घोड़े वाली बुग्गी सजा कर लेकर आये थे और आपको दूल्हा बना दिया था। अध्यक्ष महोदय, वे लोग समझते थे कि आज तक हमारे साथ छल किया गया है, कपट किया गया है, वे लोग एक ही बात समझते थे कि यह घोषणा केवल घोषणा है, जब उनको पता चला कि अधिकारी उनके लिए 100-100 गज के प्लाटों की रजिस्ट्री लेकर आये हैं तो उनको लगा कि उनका सपना साकार हो गया है और जब गरीब आदमी का सपना साकार हुआ करता है तो वह नाचा करता है। 5 हजार

[श्री के० एल० शर्मा]

आदमियों ने किस प्रकार आपको बिठाकर किस प्रकार से स्वागत किया। उस समय कोई नहीं बचा था। स्पीकर सर, यहाँ तक कि मातृ शक्ति, मालाएं बहनें भी बहुत खुशी से उछल रही थीं। स्पीकर सर, किस-किस की बात करें। स्पीकर सर, अब मैं बजट पर आता हूँ। स्पीकर सर, अभी इन्होंने ऐजुकशन के बारे में एक बात कही थी। मैं बताता हूं कि इनका सोर्स क्या है ? ये पी०ए०सी० के मैम्बर हैं जितने आंकड़े ये बता रहे थे कि यह संख्या घट गई उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया। स्पीकर सर, वह सारा मैटर वर्ष 2006 की रिपोर्ट में था वह इनके टाईम का था। वर्ष 2006 के अन्दर पी०ए०सी० की रिपोर्ट आई थी उसमें ड्रॉप आउट के आंकड़े लिखे हुए थे और सीता राम जी मेरे साथ पी०ए०सी० के मैम्बर रहे हैं। वह केस जिसको ड्रॉप कर दिया और हमने इनकी गलतियों को छोड़ दिया था लेकिन आज वे उन गलतियों को यहां पर गा रहे थे और वे आंकड़े हमें सुना रहे थे। यह ड्रॉप आउट रेट उस वक्त बढ़ा था जिस वक्त इनकी सरकार थी। इन्होंने उस समय तो देखा नहीं लेकिन केवल इतनी बात सुन ली। स्पीकर सर, अभी ये नहर की बात कर रहे थे। नहर के बारे में इन्होंने जिक्र किया था इसके बारे में मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इनकी सरकार ने सिवाय घोषणाओं के कुछ किया है ? मेरा ख्याल है कि जब से हरियाणा राज्य बना है तब से दादू पुर नलवी नहर के लिए शोर मचाया जाता रहा है। हमारे इलाके का हर व्यक्ति अम्बाला से लेकर करनाल तक जितने भी एम०एल०एज० थे सभी ने इस इशु को उठाया लेकिन वे कहते हैं चुनावी घोषणा है। स्पीकर सर, मैं बलवन्त सिंह जी से यह पूछना चाहता हूं कि इनके साथी कहां गये हैं उनको मेरी बात सुननी चाहिए थी लेकिन लगता है कि वे भाग गये हैं। उन्हें जाना था यह मुझे पता था। स्पीकर सर, इन्होंने जो घोषणाएं की थीं, मैं डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था और यह मैं कन्फर्म भी करना चाहता था कि यह जो अभी कह रहे थे कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है यह बात इन्होंने कहां से पढ़ी थी। मैंने वह बात अभी बता दी है कि यह उस वक्त का था जब चौटाला साहब की गवर्नमैंट थी। वर्ष 2006 की पी०ए०सी० की रिपोर्ट पढ़ कर यह कह रहे हैं। (विघ्न) सर, यह रिकार्ड की बात है और मैं रिकार्ड की बात ही बता रहा हूं। डाक्टर साहब इस समय हाउस में नहीं हैं मैं उनके सामने भी कहूंगा। हमने जो नहर की बात कही है इसके बारे में भी सुन लीजिए। करनाल से लेकर अम्बाला तक के सारे एम०एल०एज० ने यहां पर यह बात उठाई है और इसके बारे में शोर मचाते रहे। स्पीकर सर, एक बार ऐसा भी हुआ कि इसका नींव पत्थर रख दिया गया। चौटाला साहब वहां गए नींव पत्थर रख दिया था उसका मुहूर्त कर दिया गया, हवन कर दिया गया लड्डू बंट गए। हल्के के सारे लोग कहने लगे कि दादू पुर नलवी का नींव पत्थर लग गया लेकिन जब हमने बजट उठा कर देखा तो उसमें दादू पुर नलवी के लिए एक रुपये की भी ऐलोकेशन नहीं की गई थी केवल झूठा पत्थर लगा दिया। स्पीकर सर, चुनावी बात तो ये लोग करते हैं। चुनावी बात तो यह होती है कि बजट के अन्दर कोई चीज मौजूद न हो और वहां पर पत्थर लग जाए, वहां पर लड्डू बंट जाएं। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आते ही क्या कहा कि इस नहर के पहले चरण को हम जून तक पूरा कर देंगे यह बात वे स्टेज पर कह कर आए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शाहबाद के अन्दर जा कर सुनो लोग कहते हैं कि हमारा आगे कुछ बने या न बनें हमारे जीवन की रेखा बनी है हमारे बच्चों की यह रोटी बनी है। स्पीकर सर, ऐसे शासक भी आए थे जिन्होंने ऑगुमैंटेशन नहर लगा कर टयूबवैल लगा कर वहां से पानी निकाल लिया था और एक शासक ऐसा भी आया है जिसने हमारी इच्छाओं को पूरा किया है जिसने यहां पर दादू पुर नलवी नहर बनाई है। वह नहर कोई दो चार दस रुपये में नहीं बन गई है, स्पीकर सर, 260 करोड़ रुपये की लागत से बनने

वाली नहर मात्र एक कलम से बन गई। उस दिन दोबारा जब हमने वहां जा कर पत्थर लगाया तो माननीय मुख्य मन्त्री जी कहने लगे कि पत्थर दोबारा लगाने की क्या जरूरत थी। दोबारा लगाने की बात इसलिए है कि इन्होंने तो झूठे पत्थर लगाए हैं हम तो असली पत्थर लगाते हैं। स्पीकर सर, जिसने यह काम किया हो उसी का पत्थर लगना चाहिए। स्पीकर सर, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने हमारे यहां पर इतना अच्छा बजट पेश किया। जब गलोबल रिसैशन आई उसके बावजूद भी हरियाणा के अन्दर यह बताया जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय 58,000 रुपये पर पहुंच गई है (विघ्न) घोषणा करते हुए मंत्री जी ने कहा था कि यह आंकड़े वर्ष 2008-09 के हैं। ये आंकड़े उस वक्त के हैं जिस वक्त लोहे की कीमत 50 रूपए किलो थी। उसके बाद लोहे की कीमत 25-30 रुपए किलो हुई है। सर, वहां की मिट्टी के अन्दर खनिज है, केवल लोहा ही है। इसलिए यहां के लोगों की आय केवल लोहा ही है। अगर उस लोहे की आज की तारीख में कीमत लगाएं तो हरियाणा नम्बर दो पर नहीं नम्बर एक पर होगा। अध्यक्ष महोदय, जहां पर खेती नहीं होती है वहां पर आमदनी इन्डस्ट्रियलाईजेशन से या व्यापार से होती है और वहां पर प्रति व्यक्ति आय हमेशा बढ़ा ही करती है। अध्यक्ष महोदय, आज सारे देश में मंदी छा गई है और यहां पर तो प्रति व्यक्ति आय जो बताई गई है उससे यह एक्सपैक्ट किया जा रहा था कि भारत में जी०डी०पी० रेट कम होगा। सर, भारत सरकार का जी०डी०पी० का रेट अनुमान बजट में 7.1 प्रतिशत बताया गया है। मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि किसी एक इक्नोमिस्ट ने उसका नाम मुझे याद नही आ रहा है, एक बात कही थी कि अगर 6.8 से ऊपर भारत का जी०डी०पी० रेट आ गया तो मैं भारत वर्ष को अपना गुरू मान लूंगा, मैं उनको अपना हीरो मान लूंगा। स्पीकर सर, आज भारत का जी०डी०पी० का रेट 9 आया है, मैं यह केन्द्र सरकार के बजट में सुनकर आ रहा हूँ। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि आज यहां की जी०डी०पी० रेट 9.3 है जिसकी वजह से आज हरियाणा देश में नम्बर एक पर होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां से जाने के बाद उस व्यक्ति को पत्र लिखूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं कि इसको बड़ी-बड़ी इक्नोमीज के सामने लगाया जाए तो यह विकसित देशों के बराबर है। लेकिन आज भी हमारे देश को विकसित देश नहीं माना जाता है, हमारे देश को आज भी विकासशील देश कहा जाता है। हमारी मर्जिंग इकोनौमी है और स्पीड के हिसाब से भी चाईना के बाद भारत का ही नम्बर आता है। स्पीकर सर, बहुत तेजी के साथ एफ०आर०बी०एम० को यहां पर लगाया है। स्पीकर सर, जब हमारी सरकार ने हरियाणा की सत्ता सम्भाली तब हमारे प्रदेश का राजकीय कोष घाटे में था। हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही हरियाणा में एफ०आर०बी०एम० को यहां पर लगाया, भारत के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी की दी हुई पालिसी को लगाया, हमने उसी दिन उस पालिसी के नार्मज पूरे कर लिए थे। उन नार्मज में क्या था यह मैं बताना चाहूंगा। उसमें यह था कि जो हमारा राजस्व घाटा है उसको खत्म करना चाहिए। हमारा जो राज कोषीय घाटा है उसको 3 प्रतिशत जी.डी.पी. के अन्दर लाना चाहिए और हमारे जो जी.डी.पी. के लोन्ज हैं वे 28 प्रतिशत के विद इन रहने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्तमंत्री जी की कोशिशों के साथ हमने पहले ही साल उन तीनों कंडीशंज को पूरा कर लिया था। वित्तीय कोष का घाटा 3 प्रतिशत से नीचे था, हमारा राजस्व घाटा 9 प्रतिशत था, हमारे जो लोन्ज का आंकड़ा 26.3 प्रतिशत था वह 28 प्रतिशत से नीचे था। अध्यक्ष महोदय, सभी नार्मज पूरे करने के बाद हमें बहुत लाभ हुआ। मुख्यमंत्री जी और वित्तमंत्री जी एक मीटिंग में गए हुए थे तो वहां पर वित्तमंत्री जी ने जब यह बात उस मीटिंग में कही तो उस वक्त श्री मोनटेक सिंह आहलूवालिया जो कि प्लानिंग कमिशन के चेयरमैन हैं, ने कहा था कि अगर हिन्दुस्तान

[श्री के० एल० शर्मा]

में वित्तीय प्रबन्धन किसी ने सीखना है तो उसको हरियाणा में जाना चाहिए और वहां से ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि किस तरह से इसको मैनटेन किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो रिजल्ट बताएं हैं कि हमारा बजट किस तरह से बढ़ता चला गया और उसकी वजह से आज हमारे वित्तमंत्री जी ने 11,000 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। आज हमारे पास दूसरा रास्ता मन्दी से बचने का कौन सा बचा है, इस बारे में सभी ने अपने हिसाब से रास्ता बताया। उस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमें लोगों का विश्वास जीतना है, आज हमारा इन्वैस्टर डिमोरेलाईज न हो इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणाएं की हैं और यह उन इन्वैस्टर्ज के लिए मैसिज़ है। स्पीकर सर, हमें विकास करना है, जितना हम विकास करेंगे उतना ही बजट का आकार बढ़ेगा और उसी के साथ हम मंदी के साथ फाईट-आऊट कर सकते हैं। स्पीकर सर, इन सारी बातों को देखते हुए आज यह बजट 11,000 करोड़ रुपए का पेश किया गया है। यहां पर किसी मंत्री ने बोलते हुए कहा है कि हमें टैक्स लगाना होगा नहीं तो घाटा होगा। स्पीकर सर, मैं उनको यह बात ऑन ओथ और शर्त लगाकर कहना चाहता हूं कि वे मेरे पास आकर पांच मिनट बैठें तो मैं उनको बता दूंगा कि कैसे काम करना है। इस सरकार के वक्त में न तो पहले चार साल में कोई टैक्स लगा है और न ही आगे लगेगा। सर, ऐसा कोई मंत्री होगा जिसने चार साल तक पहले टैक्स न लगाएं हों और उसके बाद जब चुनाव का टाईम आ जाएं तो टैक्स लगाए, क्या कोई ऐसी गलती कर सकता है ? स्पीकर साहब, न टैक्स लगेगा न बजट में घाटा होगा और फिर से यह बजट ऐक्सेस का आएगा क्योंकि हमारे आंकड़े बताते हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री जी, मैं इसके लिए एक बात कहना चाहता हूं कि सारा हरियाणा आपकी ओर आँखें लगाए हुए हैं। मैं यह कहता हूं कि जब इसका रिजल्ट आएगा तो आपका नाम हरियाणा के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। यह बात आप नोट कर लो। स्पीकर साहब, मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं कि जो 1500 करोड़ रुपये का एक अलग से प्रावधान बजट में ग्लोबल रिसैशन से फाईट आउट करने के लिए किया गया है यह बहुत अच्छा है इसमें जौब ओरिएंटेशन के लिए बताया गया है ताकि लोगों को नौकरी मिले। सर, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें यह लिखा है कि 1500 करोड़ रुपये का खर्च करने का प्रस्ताव है। यह सभी परियोजनाएं मिशनरी ढंग से शुरू करने का प्रस्ताव है ताकि इन्हें दो वर्षो की अवधि में पूरा किया जा सकें। इसमें पहली बात होस्पीटल का दर्जा बढ़ाने की कही गयी है। यह बहुत ही अच्छी उत्तम स्कीम है क्योंकि इससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को इलाज के लिए सुविधा मिलेगी, लोगों को अच्छी हैल्थ की सुविधाएं मिलेगी। पहले लोगों को बहुत दूर दूर तक इलाज के लिए जाना पड़ता था। ये होस्पीटल 6 जगह पर यानी हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक में खोले जाएंगे। सर, इसमें एक बात और कही गयी है कि 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 500 बिस्तरों के होस्पीटल सहित एक महिला कालेज की स्थापना भी सोनीपत में की जाएगी। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं जहां पर 500 बिस्तरों का होस्पीटल बनता है वहां पर बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ता है। कालेज बन रहा है तो उसमें होस्पीटल भी बनाना पड़ता है। जैसा सरकार ने कहा कि बाकियों का दर्जा अगले साल बढ़ाया जाएगा। सर, करनाल से लेकर चण्डीगढ़ तक सिवाए पी०जी०आई० के कोई ऐसा होस्पीटल नहीं है जिसमें हम यह कह सकें कि हमें इलाज के लिए पूर्णत: सुविधा मिलती है। अगर इसको कुरूक्षेत्र के अंदर पहले साल और दूसरे साल के साथ सोनीपत में अगर जरूरत हो तो बना दिया जाए तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा फिजीबल होगा क्योंकि अगले साल वहां जो होस्पीटल बनेगा

उसकी जरूरत भी शायद न रहे। मैं कहना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र होस्पिटल का भी दर्जा बढ़ाया जाए। सर, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी रोजगार देने की स्कीम सरकार ने सोची है वह यह है कि गांवों के अंदर जो तालाब बंद हो गए हैं उनको खोदेंगे। इसकी जरूरत भी है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि तालाब खोदे जाने चाहिएं क्योंकि जहां भी तालाब थे वे सारे पाट दिए गए हैं। आज हर गांव के अंदर जब बारिश आती है तो वहां पर प्रदूषण सा फैल जाता है क्योंकि वहां पर पानी की निकासी का रास्ता नहीं है। जब इस बारे में हम बात करते हैं तो हमारे इंजीनियर्ज भी एक ही बात कहते हैं कि गांवों में जो पानी की निकासी का रास्ता था वह तो आपने बंद कर दिया है। अब पानी की निकासी कहां ले जाएं इसलिए यह स्कीम बहुत ही उत्तम है। इसमें सरकार ने एक हजार गांव के लिए जो दस दस लाख रुपये देने का प्रावधान किया है, मैं इसको ऐप्रीशिएट करता हूं और कहना चाहता हूं कि ऐसी सुविधाएं उन सारे गांवों में दी जानी चाहिए जहां तालाबों को बंद कर दिया गया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी बात चल रही थी कि शहरों के अंदर नवीनीकरण नहीं होना चाहिए केवल गावों के अंदर नवीनीकरण बढ़ना चाहिए। सर, अगर सारे आंकड़े मिलाकर देखें तो आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि एक साल की तरक्की के आंकड़े गावों के अंदर इनके चार साल के आंकड़ों में जमा कर दिए जाएं तब भी पूरे नहीं हो सकते। अगर शहरों के लोगों का मुख्यमंत्री जी जीवन स्तर ऊँचा उठाना चाहते हैं तो इससे इनको तकलीफ क्यों होती है ? शहरों से आपको क्या ऐलर्जी है ?

श्री बलवंत सिंह : हमें कोई ऐलर्जी नहीं है। हम तो यह कहते हैं कि जो सुविधायें शहरों में हों वह गांवों में भी हो। जो गैप है, जो डिफरैंस है वह नहीं होना चाहिए।

Shri K. L.Sharma : You have not gone through the Budget. आपने उसको पढ़ा नहीं है। यदि पढ़ा होता तो यह बात नहीं आती। नवीनीकरण की बात भी बहुत अच्छी कही गई है। इसके अलावा जो हाउस टैक्स माफ किया गया है। एक एक मकान का दो दो हजार रुपये टैक्स बनता था, उस टैक्स को अदा करने में उन गरीब लोगों को जिनके कि एक -एक और छोटे छोटे मकान थे उनको देने में बहुत दिक्कत होती थी। उस टैक्स को माफ करने से लोग सरकार को बहुत दुआएं देते हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं यदि सरकार उस पर ध्यान दे। हमारे प्रदेश में कुछ विधवाएं ऐसी हैं जिनका कुछ हाउस टैक्स बकाया पड़ा है और वे उसे दे पाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि वे सिर्फ सरकार द्वारा दी जाने वाली पैंशन पर निर्भर करती हैं और इसके अलावा उन्होंने अपने छोटे से मकान में से कुछ पोर्शन किराए पर दे रखा है और उससे उनको 250 रुपये तकरीबन किराया आता है और 750 रुपये के करीब पैंशन सरकार देती है टोटल मिलाकर लगभग एक हजार रुपये की राशि बनती है जिसमें से उनका गुजारा ही मुश्किल से हो पाता है इसलिए वे वह टैक्स दे पाने में समर्थ नहीं हैं और यदि हम कुछ मुकदमेबाजी करते हैं तो भी लगता है कि ले नहीं पाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यह थोड़ी सी राशि है यदि उसे माफ कर दें तो उससे बहुत बड़ी दुआयें मिलेंगी। हाउस टैक्स के अधिनियम में यह जो क्लाज है कि यदि स्वयं रह रहे हैं उसमें यदि विधवाओं के लिए रिलैक्स किया जाए जिससे कि उनको इस बारे में लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। एक मुझे सेला राम नाम का बूढ़ा आदमी मिला, उसे देखकर मेरा मन भर आया। उसकी पगड़ी फटी हुई थी और लाठी टूटी हुई थी। उसने कहा कि मैं तो भगवान के सहारे हूं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जो बूढ़े हैं उनको यदि थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो ये बहुत ज्यादा दुआएं देते हैं। इनको साल में दो सौ रुपये और दे दें तो ये अपने लिए पगड़ी और लाठी ले लें। यह मेरे मन की बात है। यह बात कहने की मैं इसलिए हिम्मत जुटा रहा हूं

कि यहां बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। मैं एक दो बातें और कहकर अपना स्थान लूंगा। यह जो मदों की बात यहां पर कर रहे थे मैं उनको बताना चाहूंगा कि जब कोई काम शुरू होता है उस पर इन्वैस्टमैंट कम होती है, मिडिल में इन्वैस्टमैंट बढ़ जाती है और एंड में फिर कम हो जाती है। यह 3-4 स्टेजिज होती हैं। यह सब देखकर ऐक्सपैंडीचर सैंग्शन किया जाता है। ऐक्सपैंडीचर सैंग्शन काम देखकर के ऑन डिमांड किया जाता है। ये साथी ऐसे मोलड़ हैं कि कहते हैं कि ये परसैंटेज घट गई वह घट गई। पता नहीं कैसे घट गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह : ये मोलड़ शब्द गलत है ये डॉक्टर हैं। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे।

श्री के० एल० शर्मा : आपको दिक्कत है तो मैं यह शब्द वापस ले लेता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप कंक्लूड करें।

श्री बलवंत सिंह : शर्मा जी, आप चाहे कोई भी बात कहें पर ये मोलड़ जैसे शब्द न इस्तेमाल करें। (विघ्न)

1700 बजे **श्री के० एल० शर्मा :** मैं यह कहना चाह रहा था कि इस हाउस में गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए कुछ बात सामने आई हैं। उनमें एक बात माननीय सदस्य श्री विनोद शर्मा, मान साहब और बहुत सारे भाईयों ने कही। हमारे प्रदेश को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान था जिनके सुझाव से भाखड़ा जैसी नहर बनाई गई। मेरा आशय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के लिए है। सभी माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि सरकारी अदारों में उनके नाम की प्रतिमाएं लगाई जायें। मैं तो यह कहता हूं कि सरकारी अदारों से हटकर दूसरे अदारों में भी उनकी प्रतिमाएं लगनी चाहिए। स्पीकर सर, मैं शाहबाद म्यूनिस्पिल कमेटी का धन्यवाद करता हूं। जहां पर म्यूनिस्पिल कमेटी ने सर्वसम्मति से सभी पार्टियों से हटकर शाहबाद में जी०टी० रोड के पास अढ़ाई एकड़ भूमि पड़ी थी उस पर पार्क बनाने का फैसला उसी दिन कर लिया था जिस दिन वहां पर शोक सभा का आयोजन किया था और एक प्रस्ताव पास किया कि इस पार्क का नाम चौधरी रणबीर सिंह मैमोरियल पार्क रखा जाए। उस पार्क के अन्दर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जायेगी। इससे बढ़कर और बात क्या होगी कि म्यूनिस्पिल कमेटी ने यह भी कहा है कि इस पार्क पर जितना भी खर्चा आयेगा चाहे वह एक करोड़ ही क्यों न आये वह पैसा हम सरकार से नहीं लेंगे किसी नेता से नहीं लेंगे बल्कि केवल शाहबाद म्यूनिस्पिल कमेटी ही उस खर्चे को वहन करेगी। यह भी बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी के साथ हमारे एरिया में एक इस्माईलाबाद नाम का कस्बा है वहां पर म्यूनिस्पिल कमेटी तो नहीं है पंचायत ही है। वहां का सरपंच भी पंचायत द्वारा रैजोल्यूशन पास किया हुआ मेरे पास लाया था उसमें एक एकड़ जमीन देने की बात कही है और शाहबाद की तरह उस पंचायत की भी इच्छा है कि उनके दो कम्युनिटी सैंटर बन रहे हैं वहां पर चौधरी रणबीर सिंह की प्रतिमा लगनी चाहिए। मैं अपने सभी भाईयों से गुजारिश करूंगा कि जहां-जहां ऐसी संस्थाएं बन रही हैं या ऐसी जगह हैं वहां पर ऐसा किया जाना चाहिए। यह हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और देश और प्रदेश के लिए सच्ची आत्मा से दुआ होगी। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the Hon'ble Chief Minister will make an announcement.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की जो वचनबद्धता है वह पंचायती राज को मजबूत करने की है। सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करने की है। जो पंचायत का विकास हो उसमें लोगों की इन्वोल्वमैंट हो। इसी बात को मध्यनजर रखते हुए हमने 25 जुलाई, 2007 को ग्राम पंचायत को खर्च करने की पावर 1.25 लाख रुपये से तीन लाख रुपये तक कर दी थी, पंचायत समिति को तीन लाख से 5 लाख तक की पावर दी थी, जिला परिषद को 5 लाख से दस लाख की पावर दी थी और तीन लाख से 5 लाख रुपये की पावर ब्लॉक समितियों को दी थी। आज फिर हमारी सरकार ने इन संस्थाओं की वित्तीय शक्ति को बढ़ाकर ग्राम पंचायत की तीन लाख से पांच लाख रुपये, पंचायत समितियों को पांच लाख से 10 लाख रुपये और जिला परिषदों को दस लाख से 15 लाख रुपये तक किया है। नियमों के अनुसार इनमें संशोधन कर दिया जायेगा। जो भी काम पंचायतों में, पंचायत समितियों में या जिला परिषदों में होंगे वे सभी कार्य पंचायती राज महकमे की तकनीकी आधार पर निविदाएं आमंत्रित करके कराये जायेंगे ताकि गांवों का जल्दी से जल्दी विकास हो और लोगों की ज्यादा से ज्यादा इन संस्थाओं में इन्वोल्वमैंट हो सके।

वर्ष 2009-10 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्रीमती सुमिता सिंह (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं क्योंकि मुझे आज ही बोलने का मौका मिला है। इसलिए सबसे पहले मैं चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी जैसी महान हस्ती जिन्होंने सारे हरियाणा का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है, वह अपने आप में एक इन्स्टीच्यूट थे, उनको श्रद्वांजलि देती हूं। मैं सच्चे मायने में यह मानती हूं कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि हम सभी लोग जो राजनीति में हैं ईमानदारी से अपनी राजनीति करें और प्रदेश की सच्ची सेवा करें। सर्वप्रथम मैं अपने मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को बधाई देती हूं जिन्होंने अभी तक पिछले 4 सालों के अंदर जो भी घोषणाएं की चाहे वे राज्य स्तर पर हों चाहें जिला स्तर पर हों और चाहे ब्लाक स्तर पर हों और किसी भी वर्ग के लिए हों, उन घोषणाओं को पूरा किया। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि जिस घर में बुजुर्गों का आदर सम्मान होता है उस घर के अंदर परमात्मा का वास होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुजुर्गों की पैंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करके यह दिखा दिया है कि हमारे प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार बुजुर्गों का कितना ध्यान रखती है, कितना मान सम्मान करती है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देती हूं। हम सभी जानते हैं कि विश्व भर के अंदर आज अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, शेयर मार्किट गिर रही है, लोगों के बड़े-बड़े व्यापार बन्द हो रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने वर्ष 2009-10 का जो 10 हजार करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है वह एक मिसाल है। इसके लिए मैं अपनी सरकार के मुख्यमंत्री और हमारे वित्त मंत्री बीरेन्द्र सिंह जी को बधाई देती हूं। यह सारा पैसा शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगेगा। **(इस समय सभापतियों की सूची में से माननीय सदस्य आई०जी० शेर सिंह जी पदासीन हुए।)** व्यापार में मंदी की मार को देखते हुए हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपये जो समर्पित आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज रखा है वह इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगाया जाएगा

[श्रीमती सुमिता सिंह]

जिससे होस्पिटल्ज की अपग्रेडेशन, पानी और सीवरेज की व्यवस्था होगी और एजूकेशनल इंस्टीच्यूट खोले जाएंगे, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगी। सभापति महोदय, मैं अपनी सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने अपना ध्यान ग्रामीण विकास में लगाया। इससे पहले कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना में हमारा प्रदेश तीसरे स्थान पर आया है। यह इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारी सरकार ने गांव के विकास के लिए गांव के सैनीटेशन का ध्यान रखा। सैनीटेशन का ध्यान रखते हुए 11 हजार सफाई कर्मचारियों को गांवों में सफाई के लिए लगाया गया है। स्वच्छ नैपकिन को भी बढ़ावा दिया गया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना के तहत जिन गांवों में 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं वहां पर 50-50 लाख रुपये लगाकर उन ग्रामीण इलाकों का विकास किया जा रहा है। सभापति महोदय, इसी प्रकार से शहरी विकास में हमारे प्रदेश ने हर शहर के अंदर विकास के कार्य किए हैं। आज हर शहर के अंदर विकास होता नजर आ रहा है। आज जिस मर्जी शहर पर नजर डाली जाए वहां कंक्रीट की सड़कें हैं। जहां फ्लाई ओवर की जरूरत है वहां फ्लाई ओवर दिए जा रहे हैं। जिस वार्ड में 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं वहां एक-एक करोड़ रुपये मुख्यमंत्री महोदय ने उन स्लम बस्तियों का विकास करने के लिए दिए हैं। शहरों के अंदर हर व्यक्ति को अपने घर में रहने के लिए हाउस टैक्स देना पड़ता था जो कि अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था। वह हाउस टैक्स हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने माफ किया है जोकि एक ऐतिहासिक कार्य है। इससे हमारे अनुसूचित जाति के लोग जिनको म्युनिस्पिल कमेटी में एन०ओ०सी० लेने के लिए जाना पड़ता था। जिन्होंने हाउस टैक्स नहीं दिया होता था उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता था और वे अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सकते थे। उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता था तो वे सरकार द्वारा दी जानी वाली सारी सुविधाओं का फायदा नहीं उठा पाते थे। सभापति महोदय, इसी प्रकार से शिक्षा में भी हमारा प्रदेश बहुत आगे है। समाज की सबसे बड़ी दौलत शिक्षा मानी जाती है। वही प्रदेश तरक्की करता है जहां शिक्षा पर जोर हो। हमें इस बात की खुशी है कि इस बजट का 15.56 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के लिए रखा गया है। बहुत से नए टैक्नीकल इंस्टीच्यूट, नए स्कूल और स्कूलों की अपग्रेडेशन की गई है। हरियाणा में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास की शिक्षा में समैस्टर सिस्टम लागू किया गया है उससे बहुत फायदा होगा। भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना शुरू की गई है जिससे अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं जो दसवीं कक्षा में 60 प्रतिशत से ऊपर नम्बर लेंगे उनको सरकार दस हजार रुपये सालाना वजीफा देगी। हमारी सरकार अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी स्कोलरशिप दे रही है। मैं मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो बच्चे अनाथ हैं और अनाथालयों में पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा की तरफ भी सरकार ध्यान दे। जो बच्चे अनाथालयों में पढ़ रहे हैं और दसवीं या बाहरवीं कक्षा पास करने के बाद जॉब ओरियंटिड शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या टैक्नीकल शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं तो यह कहूंगी कि जो अनाथालय बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों का अच्छी तरह से पालन-पोषण कर रहे हैं उन अनाथालयों को शिक्षा के लिए सरकार एडोप्ट कर ले तो बहुत नेक काम होगा। चेयरमैन सर, मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने सोशयल सर्विसिज को वर्ष 2009-10 के बजट में प्रमुख महत्त्व दिया है ताकि विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा मिल सके। एक महिला होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी

धन्यवाद करूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं को असलियत में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आधार पर स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधवा महिलाओं की पैंशन 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति महीना कर दी है। इसी तरह से बाहरवीं पास बेरोजगार महिलाओं का भत्ता 450 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये प्रति महीना कर दिया है। इसी तरह से ग्रेजूएट महिलाओं का भत्ता 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है। इसी तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्ज और हैल्पर्ज का 1500 रुपये और 750 रुपये प्रति महीना भत्ता कर दिया है। इन बातों से जाहिर होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी सच्चे मन से महिलाओं को समाज में पुरुषों के बराबर लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमारे ही देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनमें ऐसी सरकारें हैं जहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पिछले दिनों बैंगलोर और कर्नाटका में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। बैंगलोर में पब के अंदर लड़कियों के साथ कुछ लोगों ने जो मारपीट की उसके बारे में हम सब जानते हैं। इसी तरह से बस में एक लड़का और लड़की एक साथ जा रहे थे उनके साथ भी बदतमीजी की गई, मारपीट की गई। मैं इन घटनाओं की निन्दा करती हूं। मौरल एथीक्स लड़का और लड़की दोनों के लिए बराबर है। पब भी दोनों के लिए ही बुरा है इसलिए मैं इस घटना की निन्दा करती हूं। बैंगलोर में महिलाओं के साथ बहुत ही शर्मनाक घटना हुई दूसरी तरफ हमारी सरकार महिलाओं को मान सम्मान दे रही है। टीचर्ज की भर्ती में हमारी सरकार ने महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण दिया है। इसी तरह से टैक्नीकल ऐजूकेशन में भी महिलाओं को 25 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में महिला विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गांवों में महिलाओं की चौपालें भी हमारी सरकार बनवा रही है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करवाने पर स्टैम्प डयूटी में भी छूट दी जाती है। इन सब कामों के लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं।

चेयरमैन सर, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहूंगी कि हमारी सरकार प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की तरफ भी विशेष ध्यान दे रही है। इसी के मध्यनजर हमारी सरकार ने 450 स्पैशलिस्ट्स और 800 डाक्टरों की भर्ती की है। इसी तरह से स्टाफ नर्सिज की भी तीन हजार पोस्टें हमारी सरकार ने क्रिएट की हैं। हमारी सरकार द्वारा गरीब लोगों का सरकारी हास्पिटल्ज में मुफ्त इलाज किया जाता है और दवाईयां भी मुफ्त दी जाती हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आज के दिन कैंसर और डायबिटीज की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। कैंसर की जांच के लिए हमारे प्रदेश के लोगों को रोहतक, चण्डीगढ़ और दिल्ली जाना पड़ता है। यह बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। अमीर और गरीब दोनों तरह के लोगों को ये बीमारियां हो जाती हैं इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि जिला लैवल पर हमारे सरकारी हास्पिटल्ज में ही कैंसर के टैस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो गरीब लोग दिल्ली और चण्डीगढ़ नहीं जा सकते वे भी अपना टैस्ट करवा सकें। चेयरमैन सर, डायबिटीज की बीमारी भी बहुत गंभीर बीमारी है। यह बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से सरकार एड्स और पोलियो की जानकारी के लिए अवेयरनैस कैम्पस लगाती है उसी तरह से डायबिटीज की जानकारी भी लोगों को देने के लिए अवेयरनैस कैम्प सरकार की तरफ से शुरु करने चाहिएं। इसके अतिरिक्त मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगी कि जो बहुत से व्यवसायी जिनकी अपनी इण्डस्ट्री, होटल और मकान टूटने का डर था जो नैशनल हाई वे और स्टेट हाई वे पर बने हुए थे। जिन पर टूटने की तलवार पिछले काफी दिनों से लटक रही थी। लेकिन हमारे माननीय

[श्रीमती सुमिता सिंह]

मुख्यमंत्री जी ने पंजाब शिडयूल्ड रोड्ज़, 1963 में संशोधन करके उन लोगों को जिनको सदा बेरोजगार और बेघर होने का डर बना रहता था उससे निजात दिलाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा करके एक बहुत बड़ा कार्य किया है इसके लिए भी मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगी। इसके साथ ही मैं अपनी कांस्टीचुएंसी की कुछेक डिमाण्ड की ओर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आज शिक्षा के ऊपर खास ध्यान दे रहे हैं और खास तौर से टैक्नीकल एजूकेशन को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। सभापति महोदय, इसी संदर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि करनाल के अंदर भी सरकारी इंजीनियरिंग कालेज खोला जाये और एक होटल मैनेजमैंट का इंस्टीच्यूट भी खोला जाये। पिछले कई साल से करनाल शहर का जो बस स्टैण्ड है उसको वर्तमान जगह से सैक्टर-12 के अन्दर शिफ्ट होने की योजना बनाई गई है क्योंकि जो बस स्टैण्ड है वह मेन शहर के अन्दर है जिससे कि वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगा रहता है। मैं इस बारे में भी निवेदन करना चाहूंगी कि जल्द से जल्द हमारे बस स्टैण्ड को सैक्टर 12 में शिफ्ट करने की योजना को अमलीजामा पहनाया जाये। इसी प्रकार से कैथल-करनाल रोड से बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक आता है जिसको शहर के अन्दर से गुजरना पड़ता है। इस ट्रैफिक को डारेक्ट हाईवे पर ले जाने के लिए एक नया बाई-पास बनाने की जरूरत है। इस ट्रैफिक के लिए नया बाई-पास या तो अनाज मण्डी के पास से बनाया जाये या फिर अनाज मण्डी के अन्दर से भी इस ट्रैफिक के लिए रास्ता निकाला जा सकता है। एक और हमारे करनाल में बड़ी चर्चा का विषय है जो कि एक सस्पैंस बना हुआ है कि करनाल के अन्दर कल्पना मैडीकल कालेज की स्थापना होने जा रही है। मैं इस बात की तरफ भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इस ओर भी ध्यान दिया जाये क्योंकि कल्पना चावला ने करनाल का नाम विश्व के मानचित्र पर चमकाया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इस मैडीकल कालेज के बारे में भी शीघ्र निर्णय लेकर उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ करवायें। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि करनाल के अन्दर बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहां पर अनुसूचित जाति के गरीब परिवार रहते हैं। ये बस्तियां सरकारी जमीन के ऊपर है। इन बस्तियों में कुछ लोग तो 50-50 और 60-60 सालों से रह रहे हैं। इसमें कोई शामलात की जगह है तो कोई म्युनिसिपल कमेटी की जगह है। इन बस्तियों में कुछ वर्ष पहले तो पानी, सीवरेज और सड़कें इत्यादि की सुविधायें मुहैया थी परन्तु उनके संदर्भ में आजकल यह कहा जा रहा है कि अनअप्रूव्ड कालोनीज़ में इस प्रकार की मूलभूत नागरिक सुविधायें नहीं दी जा सकती। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि ये कालोनीज़ अप्रूव्ड नहीं हैं। ये परिवार पिछले 50-60 सालों से सरकारी जगह के ऊपर रह रहे हैं जिस प्रकार से आज हम गांवों के अन्दर इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत लोगों को पीने का पानी मुहैया करवा रहे हैं तो कम से कम इन अनुसूचित जाति की बस्तियों में भी पानी, सीवरेज और सड़क की सुविधायें दी जायें। इसके अलावा करनाल में काफी मात्रा में अनअथोराईज्ड कालोनीज भी हैं। यह बात मुझे मालूम है कि इस बारे में हाई कोर्ट का स्टे है, फिर भी हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जहां पर 70 परसैंट से ज्यादा कंस्ट्रक्शन है, चाहे वे अप्रूव्ड न भी हों, कम से कम हम वहां पर मूलभूत सुविधायें तो जरूर दें। इसके अतिरिक्त एक और बात की तरफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगी। करनाल के अन्दर सदर बाजार का एरिया है उस एरिया में हर घर के अन्दर लोगों ने जूते बनाने की फैक्टरी लगाई हुई है किन्तु आज

के दिन जो करनाल में जूता उद्योग है वह बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा है और लगभग पतन के कगार पर खड़ा है। वहां पर सैंकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। मैं यहां पर यह उल्लेख भी करना चाहूंगी कि इस जूता उद्योग को बचाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी रियायतें भी दी हैं। पिछली सरकार ने सिर्फ 100 रुपये तक का जूता टैक्स फ्री किया हुआ था लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद वर्ष 2005 से हमारे मुख्यमंत्री जी ने 200 रुपये तक का जूता टैक्स फ्री किया है और अगले साल वर्ष 2006 में 300 रुपये तक का जूता टैक्स फ्री किया गया। सभापति महोदय, जब से हिमाचल प्रदेश के बद्दी में जूता उद्योग को ज्यादा कर रियायतें दी जा रही हैं तब से करनाल के अन्दर जो हमारा जूता उद्योग है उसकी कमर टूट गई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे करनाल के इस जूता उद्योग को बचाने के लिए एक स्पैशल शू हब या इण्डस्ट्रियल ज़ोन इस उद्योग के लिए जरूर बनायें। सभापति महोदय, अन्त में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूं कि पिछले चार साल के अन्दर जितने काम हमारी सरकार ने किये हैं उतने किसी अन्य सरकार ने आज तक नहीं किये। वह चाहे हरियाणा प्रदेश में चार-चार थर्मल पावर प्लांट लगाने का काम हो, चाहे एजूकेशन इंस्टीच्यूट बनाने का काम हो, चाहे फ्लाई ओवर बनाने का काम हो और चाहे शूगर मिल्ज़ की स्थापना का काम हो। इस सबके साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री के प्रगतिशील नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा काफी ज्यादा मात्रा में सामाजिक कार्य भी किये जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगी कि उन्होंने जो बुजुर्गों की पैंशन 500 रुपये तक बढ़ाकर जो पुण्य का काम किया है इसके लिए प्रदेश के सभी बुजुर्ग उनको सदा ही आशीर्वाद देते रहेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेती हूँ।

श्री अरजन सिंह (छछरौली) : सभापति महोदय, मौजूदा सरकार के बजट सत्र में अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभापति महोदय, मैं मौजूदा बजट के बारे में कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार का यह वर्ष 2009-10 का बजट आम आदमी, कर्मचारी, गरीब मजदूर, महिलाओं आदि के लिए न केवल राहत देने वाला है बल्कि किसानों के लिए तो यह मील का पत्थर साबित होगा। किसानों के लिए बजट में जो विशेष प्रावधान किये हैं इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी तथा सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूँ। सभापति महोदय, सरकार वह अच्छी है, मुख्यमंत्री वही अच्छा है, जिसकी नीयत अच्छी हो। सभापति महोदय, अगर नीयत अच्छी होगी तो नीति भी वह अच्छी ही बनायेगी। अच्छा आदमी अच्छा काम करेगा उससे सबको उसका फायदा होगा। अच्छा आदमी माड़ा काम कर ही नहीं सकता और माड़ा आदमी कभी अच्छा सोच भी नहीं सकता। सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से दो-चार बातों की ओर आपका व सरकार का भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पिछली सरकार में बुढ़ापा पैन्शन बनवाने के लिए कई-कई साल तक इन्तजार करना पड़ता था। हर महीने पटवारी का इन्तजार करना पड़ता था। जब तक उनकी सरकार नहीं बनी थी तब तक डींगें मारा करते थे कि हम बुढ़ापा पैन्शन इतनी देंगे, इतनी देंगे बोलियाँ लगा करती लेकिन जिस दिन सरकार बन गई उसी दिन से सभी अधिकारियों को ऑर्डर कर दिये कि गाँवों में जाओ और जो ज्यादा से ज्यादा पैन्शन बन्द करके आयेगा उसको सबसे बढ़िया स्टेशन दिया जायेगा। सभापति महोदय, पहला सर्वे गाँवों में हुआ 80-80 साल के बुजुर्ग जिनकी पिछले 10-15 सालों से पैन्शन चली आ रही थी, अगर वे हाजिर नहीं हो पाये तो उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हुए उनकी पैन्शन काट दी गई। सभापति महोदय, जो 80 साल का बुजुर्ग है और वह

[श्री अरजन सिंह]

जिन्दा है तो आगे पैन्शन भले ही न दें लेकिन जिसको पहले से ही पैन्शन मिल रही है उसकी तो नहीं काटनी चाहिए। पहला सर्वे गाँव में हुआ और इन्होंने देखा कि सर्वे के बावजूद भी पैन्शनर्ज काफी रह गये तो इन्होंने अगला सर्वे तहसील में किया ताकि कम से कम लोग आयें। कुछ लोग वहाँ पर नहीं जा पाये और उनकी भी पैन्शन काट दी गई। सभापति महोदय, उसके बाद इन्होंने देखा कि अब भी डाटा ज्यादा आ रहा है। सभापति महोदय, 100 रुपये बढाने की बजाय बहुत से बुजुर्गों की पैन्शन की कुर्बानी दी गई।

श्री सभापति : अब तो उनकी पैन्शन बन गई होगी।

श्री अरजन सिंह : सभापति महोदय, अब तो बन गई है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा और न ही किसी की बड़ाई कर रहा हूँ। मैं भी दूसरी पार्टी का सदस्य हूँ और मेरा भी यही फर्ज है कि जो सच्चाई है उसके बारे में बताऊं। उसके बाद एक तरीका ढूंढा गया कि अब की बार सर्वे ऐसी जगह कराओ जहाँ 80 साल का बुजुर्ग चढ़ ही न सके। तीसरा सर्वे डी०सी० ऑफिस में (तीसरी या चौथी) आखिरी मंजिल पर किया गया क्योंकि 80 साल के बुजुर्ग असल में तो चौथी मंजिल तक चढ़ ही नहीं सकते और अगर चढ़ भी गये तो ये मना कर देंगे कि जो चौथी मंजिल पर चढ़ गया तो 80 साल का हो ही नहीं सकता। सभापति महोदय, बेचारे बुजुर्ग मारे गये कि ना चढ़े तो मरे और चढ़े तो मरे। मतलब यह कि बुजुर्गों की जो बेइज्जती हुई वह किसी से छिपी नहीं है। बेचारे बुजुर्ग यह सोच कर घर ही बैठ गये कि 200 रुपये से अच्छा तो अपने घर में ही अपने बच्चों से पिट लेंगे। सभापति महोदय, उसके बाद एक योजना और बनाई गई। जब इन्होंने यह देखा कि अब भी बुजुर्ग ज्यादा रह गये तो इन्होंने घोषणा की कि गाँवों में वृद्ध आश्रम बनाये जायें और वे वृद्ध आश्रम जोहड़ों के नजदीक बनाये जायें। इनकी सोची समझी योजना थी कि लोग समझ लेंगे कि सरकार ने घोषणा कर दी अब ये तो सरकारी हो गये। वृद्ध आश्रम के नाम पर एक कमरा बना दिया गया उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। वहाँ न तो खाट और न बिस्तर का इन्तजाम किया गया न ही चाय-पानी का या खाने का प्रबन्ध किया गया। न हुक्के का प्रबन्ध, न तम्बाकू का इन्तजाम था न कोई टेलीविजन। वहाँ पर कोई रोटी बनाने वाला, कोई सेवा करने वाला हो, कोई बीमार होने पर दवाई दिलवाने वाला हो तब तो इसका फायदा हो। 80 साल के बुजुर्ग को कोई वहाँ मरने के लिए छोड़ कर आयेगा क्या ? सभापति महोदय, हर मां-बाप अपने बच्चे को इस उम्मीद से पालता है कि बुढापे में मेरी सेवा करें, मेरा बुढापे का सहारा बनें। इन्होंने वह संस्कृति भी समाप्त कर दी। वहाँ एक कमरा बना दिया और कहा कि इनको बुग्गी में बैठाकर वहाँ छोड़ आओ। वहाँ कोई रोटी बनाने वाला हो, कोई चाय पिलाने वाला हो, कोई तो कुछ करने वाला हो। ऐसी जगहों पर वृद्ध आश्रम है, जहां जौहड़ हैं क्योंकि इनको पता है कि रात को पेशाब करने उठेंगे और सीधे जौहड़ में जाएंगे और उनका काम निपट जाएगा और पैंशन खत्म। स्पीकर साहब, उसके बाद सबसे ज्यादा जोर श्मशान घाट के रास्तों को बनाने पर दिया। इनको पता था कि बुढ़े को घर के लोगों ने तो फूंकना नहीं है घर वाले वृद्धाश्रमों में आ कर तो फूंकेंगे नहीं इसलिए श्मशान के रास्ते बना कर सरकारी अफसर ही इनको उठा कर फूंक देंगे और पैंशन बच जाएगी। (विघ्न) स्पीकर सर, उस सरकार ने फूलों की खेती पर सबसे ज्यादा जोर दिया क्योंकि इनको पता था कि अनाज तो खाने के लिए होगा ही और श्रद्धांजलि देने के लिए फूल मिल जाएंगे और वहीं खा कर शमशान घाट में श्रद्धांजलि दे आएंगे। चेयरमैन सर, मैं बता रहा था कि इन्होंने किस-किस बात को उठाया था। श्मशान

घाट और वृद्धाश्रमों को बनाने के बाद इन्होंने सबसे ज्यादा जोर तौड़-2 चौधरी देवी लाल जी के बुत बनाने पर दिया। इन लोगों ने जितना पैसा बुत बनाने पर लगाया उतना पैसा अगर विकास के कार्यों पर लगता तो प्रदेश का हर आदमी यह कहता कि सरकार ने अच्छा काम किया है। जिनकी नीयत काम करने की न हो वह विकास के क्या काम करेंगे। चेयरमैन सर, मैं यहां पर यह बात भी कहूंगा कि जो सच है वह बात कहे यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन जो ठीक है उसे ठीक भी कहें और अगर सरकार कहीं गलती करती है तो उसका विरोध करें। यह हमारा फर्ज भी बनता है कि हम गलत और ठीक को ठीक कहें। चेयरमैन सर, मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज जो बुजुर्गों को मान-सम्मान मिल रहा है और घर बैठे उनको पैंशन भी मिल रही है। पैंशन लेने के लिए पहले तो पटवारियों के पीछे फिरना पड़ता था लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। सरपंच के पास जाओ और पैंशन ले आओ। अध्यक्ष महोदय, इस के साथ ही मैं सरकार का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो गरीब बहनों के लिए इस बार रक्षा बन्धन पर फ्री बस की सेवा उपलब्ध करवाई। इस अवसर पर किसी बहन को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी और हर बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए किसी भी बस में बैठ कर भाई के पास जा कर राखी बान्ध कर आई। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार ने किसान को बहुत बड़ी राहत दी है। ट्रैक्टर लेने के लिए किसान को पहले तीन एकड़ जमीन बैंकों के पास गिरवी रखनी पड़ती थी लेकिन अब तीन एकड़ की बजाए एक एकड़ जमीन करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो गिफ्ट दिया उसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, चार साल पहले हमारी युवा पीढ़ी बिल्कुल दिशाहीन थी। दसवीं, बी०ए० और एम०ए० की परीक्षाएं पास करने के बाद भी उनको कहीं कोई रोजगार दिखाई नहीं देता था। लेकिन आज मौजूदा सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में शिक्षा का एक मजबूत ढांचा बनाया है। दसवीं की परीक्षा पास करने के बाद हमारी युवा पीढ़ी पोलिटैक्निक, इन्जीनियरिंग तथा बिजनैस मैनेजमैंट के बड़े-बड़े कोर्सिज करके अपने-अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है। युवा पीढ़ी को इस सरकार ने एक सही दिशा दी है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। चेयरमैन सर, पिछले मुख्यमंत्री जब विदेश में जाते थे तो क्या देखते थे इस बारे में मेरे पास सबूत के लिए यह पूरी किताब पड़ी हुई है इस पर उनके साईन भी किये हुए हैं। जिस देश में वे गये वहां पर हरियाणा के बारे में कुछ देखने के लिए नहीं गये, वे गायों-घोड़ों के फार्म देखने जाते थे। न्यूयार्क में तो वहां पर रहने वाले हरियाणा के 40-50 परिवारों से मिल कर आ जाते थे। थाईलैंड में गन्ने की खेती देखने जाते थे तो वहां घोड़ों और गायों के फार्म देखते थे। जर्मनी जाते हैं वहां जमीन की मलकियत पूछ कर आ जाते थे। आस्ट्रेलिया जाते तो दो सौ, सवा दो सौ एकड़ का फार्म हाउस देख कर वहां से रेट पूछते कि क्या रेट्स हैं, यह क्या विकास के काम करने के लिए विदेशों में जाते थे (विघ्न) अब वाले मुख्यमन्त्री जी जब विदेश में जाते हैं तो प्रदेश के लिए कुछ न कुछ योजना ले कर आते हैं, कुछ उद्योग लेकर आते हैं या कोई न कोई विकास की स्कीम ले कर आते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमन्त्री जी विदेशों में जाते हैं या स्पीकर साहब, या कोई मन्त्री विदेश में जाते हैं तो इस सोच से जाते हैं कि हमें हरियाणा की तरक्की के लिए कोई न कोई योजना मिले। पिछली सरकार के बारे में मैं बात कर रहा था उसकी तो पूरी किताब मेरे पास पड़ी है जिस पर उनके साईन भी हैं। यह सारे का सारा डाटा इसमें दिया हुआ है। (विघ्न) मौजूदा सरकार की पिछले चार सालों में जो भी विदेश यात्राएं हुई हैं उनमें उद्योग के क्षेत्र में प्रदेश में इतना निवेश हुआ है कि कहीं कोई कमी नजर नहीं आती है। चेयरमैन सर, झज्जर जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र में बंजर भूमि का रेट भी एक-एक करोड़ रुपये हो गया

[श्री अरजन सिंह]

है और किसानों के चेहरों पर लौट कर रौनक आई गई है। पिछले मुख्यमन्त्री जी जब नार्वे में जाते थे तो हाईडल प्रोजैक्ट देख कर आते थे और फिर हिमालय में बर्फ ढूंढते थे कि बिजली पैदा करेंगे लेकिन बिजली किसी ने पैदा नहीं करनी थी। चेयरमैन सर, आज की सरकार ने यमुना नदी के दादूपुर हैड पर छः मैगावाट का हाईडल प्रोजैक्ट बना कर यह साबित कर दिया कि यमुना नदी पर भी छोटा हाईडल प्रोजैक्ट बना कर बिजली पैदा की जा सकती है। पिछली सरकार किसानों के प्रति कितनी समर्पित थी यह सबको पता है। आज उस वक्त के मुख्यमंत्री का बेटा भविष्य का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। पिछली सरकार के वक्त में किसानों ने गन्ने के रेट में एक रुपए की बढ़ोतरी की मांग की थी और वे अपनी मांग के लिए धरने पर बैठे थे। जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे 50 पैसे पर आ गये और कहने लगे कि हमें पचास पैसे की ही बढ़ोतरी कर दो तो हम धरने से उठ कर चले जाएंगे। सभापति महोदय, उस वक्त के मुख्यमंत्री कहने लगे कि मुझे यह पहले ही बता देते तो मैं तुम्हें पहले ही उठा देता। सभापति महोदय, वे लोग सर्दी के मौसम में धरने पर बैठे हुए थे तो उन्होंने किसानों पर सर्दी में ठण्डे पानी के फव्वारे चलवाए और उन पर घोड़े दौड़ाए। जिस वजह से वे लोग जख्मी होकर अपने घरों को चले गए। (विघ्न) इस सरकार को मैं क्या सुझाव दूं, यह तो पहले ही अच्छे काम कर रही है। सुझाव तो उनको देने की जरूरत होती है जिसको काम करना ही नहीं आता है। यह सरकार तो लोगों की भलाई का काम कर रही है। (विघ्न) इनके तो चेहरे से झलकता है कि ईमानदारी क्या चीज होती है। (विघ्न) गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं है। गरीब वह होता है जो धन होते हुए भी कुछ नहीं करता है। (विघ्न)

श्री सभापति : आप इस तरह से बार बार बीच में मत बोलें। अगर आपका कोई प्वायंट आफ आर्डर है तो आप अपनी सीट पर जा कर बोलें। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी का चेहरा न देखें, उनके दिल से पूछें।

श्री सभापति : इन्दौरा जी, आप बैठें। अरजन सिंह जी बजट पर बोल रहे हैं। आप उनको सुनें। (विघ्न)

श्री अरजन सिंह : चेयरमैन सर, जब ये बोल रहे थे तो मैंने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की थी। अब ये बार-बार मुझे बीच में टोक रहे हैं। (विघ्न)

श्री सभापति : आपका कोई प्वायंट आफ आर्डर है तो आप बोलें। (विघ्न) आप बीच बीच में मत टोकें। ये बजट पर ही बोल रहे हैं। आपकी सरकार की कारगुजारियां बता रहे हैं। (विघ्न) ये अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं आपको बैठकर इनकी बात सुननी चाहिए।

डॉ० सीता राम : चेयरमैन सर, इनको कारगुजारियाँ बताने के लिए समय दिया गया है या बजट पर बोलने के लिए समय दिया गया है। इनको बजट पर बोलना चाहिए।

श्री सभापति : आप बैठें। अरजन सिंह जी, आप बोलें।

श्री अरजन सिंह : चेयरमैन सर, जब इनकी सरकार आई थी तो क्या इनको उस वक्त अच्छे सुझाव नहीं आए थे। उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं अच्छे काम किए, लोगों की भलाई क्यों नहीं की ? जो आज ये भलाई की बात करते हैं। (विघ्न) आज की सरकार की अच्छी नीतियां हैं और लोगों की भलाई

के काम कर रही है। जब इनकी सरकार साढ़े पांच साल रही, क्या तब इनके दिमाग में काम नहीं किया कि लोगों की भलाई का काम करना चाहिए। (विघ्न) क्या इनको इससे पहले काम करने का टाईम नहीं मिला जो आज बार बार टोका-टाकी कर रहे हैं। (विघ्न) मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार आज अच्छा काम कर रही है। जब हमारी सरकार आएगी तो हम इनसे भी अच्छे काम करेंगे। लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला है। लेकिन जिनको मौका मिला है मैं उनके बारे में ही कह रहा हूं। पिछली सरकार के वक्त में इन्होंने चार साल तो गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया लेकिन जब इलैक्शन आया तो उस वक्त इन्होंने आखिरी साल में गन्ने का रेट एक ही बार बढ़ाया था। (विघ्न) मौजूदा सरकार ने अपने पहले ही साल में गन्ने के भाव में 19 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की थी और उसी बढ़ोत्तरी को आगे बढ़ाकर 53 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। चेयरमैन सर, सरकार ने इस साल गन्ने की अगली पिराई सत्र से पहले ही गन्ने का समर्थन मूल्य 15 रुपए बढ़ा दिया है। ऐसा करके मौजूदा सरकार द्वारा जो किसान और मजदूर वर्ष 2009-10 मनाया जा रहा है, उसको सार्थक कर दिया है। चेयरमैन सर, अब मैं पापुलर की बात करना चाहता हूं इनेलो की सरकार आने से पहले पापुलर का रेट 550 रुपए प्रति क्विंटल था लेकिन इनकी किसान और मजदूर हितैषी सरकार के आने के बाद पापुलर का रेट 150 रुपए प्रति क्विंटल हो गया था। जबकि आज इसका रेट 800 रुपये क्विंटल है। उस वक्त पापुलर की एक ट्राली 12500 रुपये की थी जबकि आज वही ट्राली 85 हजार रुपये की है। इस तरह से एक पापुलर की ट्राली में 55-60 हजार रुपये का नुकसान होता था। (विघ्न) चेयरमैन सर, गेंहू के, धान के मूल्य में 72 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके सरकार ने किसान हितैषी सोच को सार्थक किया है। वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2004 तक गेंहू के मूल्य में केवल 40 रुपये की वृद्धि की गयी थी तथा वर्ष 2004 से लेकर आज तक गेंहू का भाव 640 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1080 रुपये प्रति क्विंटल करवाने के लिए मैं मौजूदा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और सारे मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं। पिछली सरकार के दौरान एक जन-प्रतिनिधि माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी जहां-जहां पर प्रदेश में अपना दरबार लगाते थे वहां-वहां पर सरपंचों को ग्रांट दी जाती थी लेकिन मौजूदा सरकार में दस जन प्रतिनिधि हैं और लोकतांत्रिक तरीके से गांवों में विकास कार्य हो रहे हैं। अब एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं चल रही है। आज हर आदमी अपने आप में स्वतंत्र है। पंच, सरपंच, नम्बरदार को पहले सरकार की ओर से कोई मानदेय नहीं मिलता था जिसकी वजह से वे गांव के विकास में कोई रुचि नहीं लेते थे। लेकिन मौजूदा सरकार ने नम्बरदार, पंचों तथा सरपंचों को मानदेय 1500 रुपये प्रति माह देकर उनको समाज सेवा के लिए प्रेरित किया है और चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर उनकी मौजूदा स्थिति में सुधार करने की कोशिश की है। मौजूदा सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्ज, हैल्पर्ज और बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्तों में बढ़ोत्तरी करके एवं बेसहारा बच्चों को वित्तीय अधिकार देकर हर वर्ग को सुविधा देने के लिए जो घोषणा की है उसके लिए मैं मौजूदा सरकार का धन्यवाद करता हूं। वर्ष 2005 में निवेश के मामले में पहले हरियाणा 13वें नम्बर पर था। पिछले चालीस वर्षों में राज्य में लगभग चालीस हजार करोड़ रुपयें का ही निवेश हुआ था। लेकिन मौजूदा सरकार की नयी औद्योगिक नीति तथा साफ नीयत के कारण चार साल में ही 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। यह सब मौजूदा सरकार की प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा प्रदेश की आमदनी को बढ़ाने की सोच के कारण हुआ है। पिछली सरकार के समय में बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों को सरप्लस करके घर भेज दिया जाता था लेकिन मौजूदा सरकार ने उनको दोबारा से रोजगार देकर एक अच्छी सोच का परिचय दिया है। इसी तरह से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को भी सबसे पहले मौजूदा सरकार ने लागू करके कर्मचारी हितैषी

[श्री अरजन सिंह]

सोच होने का परिचय दिया है। पिछली सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की फीस फार्म की ली जाती थी लेकिन करोड़ों रुपये इकट्ठे करने के बाद वे भर्तियां रद्द कर दी जाती थी। हर बेरोजगार आदमी से 500 रुपये की फार्म की फीस लेना और उसके बाद भर्ती रद्द कर देना क्या ठीक था। उस समय उनका पैसा भी वापस नहीं किया जाता था।

श्री रामफल चिढ़ाना : चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। सर, मैं जानना चाहता हूं कि अब फार्म की क्या कीमत है ?

श्री सभापति : यह बात आप क्वैश्चन ऑवर में पूछ लेना। आपको फैक्टस पता नहीं है लेकिन ये फैक्टस दे रहे हैं इसलिए आप बैठें। यह कोई प्वायंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। (विघ्न)

श्री अरजन सिंह : आज 150 रुपये गूंठा टेक मजदूर को पैसा मिलता है हालांकि मजदूर ढूंढने से नहीं मिलता। आज उनके घर में घी के दिए जलने शुरू हो गये हैं क्योंकि अब मौजूदा सरकार की तरफ से उनके बच्चों को हर महीने वित्तीय सहायता देकर पढ़ाई का सारा खर्चा उठाकर, वर्दी तथा फ्री किताबें देकर और साथ में उनकी माँ का बैंकों में खाता खोलकर गरीब की माँ की इज्जत को बढ़ाया है और उसको जीने का अधिकार दिया है। इस सरकार ने जितनी घोषणायें की हैं उससे ये विपक्ष के साथी सोच रहे हैं कि इतना पैसा कहां से आ रहा है जो इतनी रियायतें सरकार दे रही है। ये पैसे हरियाणा के लोगों के खून पसीने की कमाई थी। पिछली सरकार यह पैसा कहां लेकर जाती थी। विदेशों में फार्म हाउस देखने जाते थे। उन्होंने तो हरियाणा की चिंता एक दिन भी नहीं की थी। इनका तो वह हिसाब है कि सुहागण राण्ड के पास खड़ी थी। राण्ड कहती है कि मेरे जैसी हो जाओ। ये तो यही चाहते हैं कि हम भी इनके जैसे हो जाएं। इस सरकार ने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं और सराहना करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। इसके साथ ही साथ मेरी 2-4 डिमांडज़ भी हैं इनको जरूर पूरा किया जाए। एक तो यह है कि प्रदेश में गन्ने की पैदावार बहुत घट गई है मेरा अनुरोध है कि कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों से इस किस्म में सुधार करवाने के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया जाए। दूसरा मेरा अनुरोध यह है कि डीज़ल का रेट चार रुपये प्रति लीटर तक घट गया है इसलिए रोडवेज की बसों का किराया भी उसके मुताबिक थोड़ा घटा दिया जाए क्योंकि रोडवेज की बसों में गरीब लोग सफर करते हैं। उनको थोड़ी बहुत राहत मिलनी चाहिए। मेरे इलाके में धाड़ क्षेत्र में मेवात की तर्ज पर सुविधायें दी जाएं और लड़कियों के लिए कालेज का निर्माण किया जाए। यमुना नदी के साथ-साथ यू०पी० की तर्ज पर पटड़ी बनाई जाए और सड़क बना दी जाए, इससे इन गांवों को बाढ़ से बचाया जा सकेगा। इससे ट्रैफिक की समस्या भी सड़कों पर कम हो जाएगी। इसके अलावा जिस प्रकार से यू०पी० के हर गांव से हरियाणा के गांव तक सड़क बनी हुई है उसी तर्ज पर हरियाणा के गांवों से भी यू०पी० के साथ लगते गांवों तक सड़क बनाई जाएं। भारतीय संविधान सभा के एकमात्र सदस्य चौधरी रणबीर सिंह जी जैसे आदर्शवादी महापुरुष की प्रतिमा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर लगाई जाए। इससे भावी पीढ़ियों को शिक्षा व सही मार्गदर्शन मिलेगा। पिछली सरकार के समय में तो पिता, पुत्र, नाती, गोती, चेले-चपटे सभी लूटने का काम करते थे। अब ऐसा कुछ कहीं देखने को नजर भी नहीं आता है। कहीं किसी चाचा का भी पता नहीं है। कोई इनकी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता। इसके लिए मैं इस परिवार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके अलावा मेरे धाड़ क्षेत्र में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां खोली जाएं। बहुत गरीब लोग वहां बसते हैं।

मुस्लिम जाति से संबंध रखते हैं। एक लाकड़, कलेसर, तहारपुर के स्कूलों को हाईस्कूल का दर्जा दिया जाए ताकि लड़कियों को और लड़कों को पढ़ने में असुविधा न हो। जैसे मेवात विकास बोर्ड बना हुआ है वैसे घाड़ विकास बोर्ड बनाया जाए। यह मेरी मांग है।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : यह घाड़ क्षेत्र क्या है ? इस एरिया में शिवालिक विकास बोर्ड अलग बना हुआ तो है।

श्री अरजन सिंह : सर, घाड़ क्षेत्र का मतलब है कि जंगल में रह रहे लोगों को थोड़ी बहुत सुविधा वहां दे दी जाए। सर, हिमाचल की पहाड़ियों से सटे हुए जो गांव हैं उनके लिए मैं अलग से लिखकर भी दे दूंगा। मैं आदरणीय पी०डब्लू०डी० मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे यहां क्रशर जोन है इस वजह से वहां हैवी ट्रैफिक के व्हीकल्ज़ निकलते हैं जिनकी वजह से सड़कें बनने में तो बहुत टाइम लगता है लेकिन टूटने में टाइम नहीं लगता। मेरे हल्के में बेगमपुर की सड़क बनाने में तो डेढ़ साल का समय लगा लेकिन टूटने में मात्र डेढ़ महीने का समय लगा!

कैप्टन अजय सिंह यादव : चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनका जो बी०के०डी० की रोड है उसके लिए हुडको में हमने केस बनाकर भेज दिया है और उस रोड़ पर जल्दी से काम करवायेंगे।

श्री अरजन सिंह : चेयरमैन साहब, इस सड़क को जल्दी से बना दिया जाये क्योंकि पशुओं के लिए जो घास है वह सारी खराब हो जाती है और बरसीम और गन्नों के गोले हैं वे भी धूल मिट्टी से खराब हो जाते हैं। इसलिए उन सड़कों को जल्दी से बनाया जाए। मैं दोबारा से सरकार का धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई) : चेयरमैन साहब, आपका धन्यवाद। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो बजट पेश किया है वह बहुत ही सराहनीय बजट है और सब लोग उस बजट को सराह रहे हैं। जाहिर है कि बढ़िया बजट देना अपने आप में यह दर्शाता है कि सरकार किस प्रकार से चल रही है। हर साल इसमें बढ़ोत्तरी करके लगभग 2000 करोड़ रुपये से 11000 करोड़ रुपये पर बजट अनुमान पहुंचाया है। इतना खर्चा स्टेट में अगर होगा तो जाहिर है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर में और सारी चीजों में बहुत वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो टैक्स कलैक्शन एफिशिएंसी कम्प्यूट्रीकृत करके बताया है जो बहुत ही ड्रामैटिक इन्क्रीज है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश होने से पहले जो घोषणाएं की हैं और बहुत से कन्सेशन सभी उन वर्गों को दिए हैं जिनको बहुत आवश्यकता थी। कुछ लोग उन चीजों के लिए राजनीति भी कर रहे थे लेकिन अब उनकी सारी हवा निकल गई है और लोगों को ये सब चीजें भी मिली हैं इसके लिए मैं सरकार को बहुत मुबारिकबाद देता हूं। इतना बैलैंस करके चाहे बेरोजगार नौजवान थे या चाहे विकलांग थे चाहे बूढ़े बुजुर्ग जिनको वाकई आज के युग में बहुत आवश्यकता है। जो गरीब आदमी हैं या छोटे लेवल के सरकारी कर्मचारी हैं उन सब को इन घोषणाओं में कुछ न कुछ दिया गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार बधाई के पात्र हैं। यह स्पेशल इकोनोमिक इम्पूटिस पैकेज और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल होस्पीटल के लिए 100 करोड़ रुपये रखे हैं और सोनीपत में मैडीकल कालेज विशेषकर लड़कियों के लिए बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये दिए गये हैं

[श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई)]

जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। क्योंकि सरकार की यह सोशल रिसपौंस्बिलीटी है, स्पेशली गरीब परिवारों के लिए इस बजट में बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ और करने की आशा भी है। जिसमें ये नये हास्पिटल्ज आयेंगे तो मेरे ख्याल से यह जो सुविधाएं हैं ये बहुत नजदीक गरीब आदमी को यह सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा में सिर्फ रोहतक में ही एक स्पेशियलिटी मैडीकल कॉलेज है जहां पर हम अच्छी मैडीकल हैल्प ले सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा फायदा गरीब आदमी का होगा। हमारे शहरों में जो पब्लिक हैल्थ के काम हो रहे हैं। कैथल में मैं देखता हूं कि हर जगह 6-7 जिलों में ये काम हो रहे हैं। इसके अलावा 18 या 16 कस्बों में ये काम और होंगे जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान इस साल किया है। क्योंकि डवैलिंग एरिया है जब तक इनके अन्दर सफाई नहीं रखी जायेगी तब तक सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। यह बात बहुत सराहनीय है कि इस हैड में इन्होंने इतना पैसा रखा है लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेटस के कहने पर और उनकी योजनाएं बनाने पर जो पोलीटिकल लीडरशिप हैं वे पैसे का आबंटन करते हैं। क्योंकि वे इंटैलीजैंट हैं और वे अपने अपने विभाग के बारे में पूरी तरह से जानते हैं लेकिन उसके रख रखाव के लिए मैन पावर डिवैल्प करना बहुत जरूरी है। मैं रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर को देखता हूं। जैसे पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है या चिकित्सा की व्यवस्था है उसमें लोअर कैडर की मैन पावर जो हमारे पास है वह डिवैल्पड नहीं है। जहां हम इतना खर्चा प्रोजैक्टस पर, बिल्डिंग्स पर और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर करें वहां यह भी बहुत जरूरी है कि उसके लिए उपयुक्त मैन पावर हम साथ साथ डिवैल्प करें। उसके लिए हमें चाहे कोई इंस्टीच्यूट्स बनाने पड़े, चाहे एट वेरियस लैवलस कोई स्कूल खोलने पड़े या कोई रिफ्रैश कोर्सिज चलाने पड़े। आज हम समझते हैं कि हमारी मैन पावर जो आलरेडी नौकरी में है, सरकारी कर्मचारी हैं और नीचे के लैवल के हैं, वे उतना बहुत कम काम करते हैं जितना कि उन्हें करना चाहिए। अगर वे टैक्नीकल आदमी हैं तो उनको टैक्नीकैलीटीज समझाने की आवश्यकता है। आज हमारे नौजवान इल-इजूकेट हैं। हमारे नौजवान समझते हैं कि सरकार की नौकरी होने के बाद हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को इस मोड आफ थोट को बदलना चाहिए। अगर इतने इतने पैसे लगाकर हमने सुविधाएं क्रिएट करनी हैं तो उसके लिए मैन पावर को डिवैल्प करना बहुत जरूरी है।

Mr. Chairperson : Do you suggest the courses in service ?

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : सभापति महोदय, मान लो जैसे बिजली विभाग के जो आदमी हैं उनका मोटीवेशन कैम्प तो होना ही चाहिए कि what they have to do ? Nobody tells them their duties. Nobody tells them anything. They are just wandering here and there. पानी वाले महकमे में जो नौकरी करते हैं, उनको अपनी ड्यूटीज का पता ही नहीं। बिजली किस समय आती है और उसका क्या शिडयूल है और ड्यूटी पर लगा कर्मचारी कहां से और कब ड्यूटी पर आता है उसकी ठीक से प्लेसमैंट होनी चाहिए। सरकार के कर्मचारियों में यह भावना भी होनी चाहिए कि सरकार आपको जहां नौकरी देती है वहीं आपकी सोशल रिस्पौंसीबिलिटी होनी चाहिए कि जिस गांव में आप लगे हैं वहां बिजली का प्रावधान करें, पानी का प्रावधान करें। सफाई कर्मचारी जहां लगें वहां पूरी सफाई करें। सारे काम सोशल रिस्पौंसीबिलिटी के साथ आर्गेनाइजिंग कैम्पस के माध्यम से हमें बार बार इम्बाइब करने चाहिएं। इसमें एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वैसे है तो नरेगा स्कीम के नीचे। गांव में जो पुरानी वाटर बोडीज हैं और बहुत सारे जोहड़ हैं वे ओवर ए पीरियड इररैलेवैंट हो गए हैं। जो पीने का पानी गांव में देते हैं वह सारी नालियों में से जाता है। पुराने जमाने में वाटर बोडीज में सिर्फ बरसात

का पानी होता था, जानवरों को उसमें नहलाया करते थे, आदमी भी उसमें नहाया करते थे तो उसमें से नहाकर निकलते थे तो साफ सुथरे होकर निकलते थे। अब सारे जोहड़ बुरी तरह से स्मैल करते हैं। मैंने देखा है कि कहीं कहीं काडा के माध्यम से मेरे हल्के में भी कई जोहड़ ऐसे बनाए गए हैं जो गंदे पानी के जोहड़ हैं उनको सीमित करके एक तरफ कर दिया है और अच्छे पानी की वाटर बोडीज बनाकर उसकी चार दीवारी करके, खुदाई करके और नीचे करके बनाया गया है। वाटर टेबल को ऊंचा करने के लिए और जानवरों के रख-रखाव के लिए यह बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि नहरों का बहुत सा पानी आजकल जब गर्मी आती है तो जोहड़ों के अंदर देना पड़ता है। एक तरफ फसलों को पानी की जरूरत है और दूसरी तरफ जोहड़ों को पानी की जरूरत है। इस प्रकार हम जितना भी पानी कंजर्व कर सकेंगें वह इरीगेशन में यूज होगा। नरेगा स्कीम सौभाग्य से एक ऐसी स्कीम है जो दिल्ली की सरकार ने बनाई है जिसमें गरीब आदमी को बगैर मौसम के जब उसे कहीं रोजगार नहीं मिलता है उसे 100 दिन का रोजगार देने की योजना है। उसका ठीक मोनीटर करना डिप्टी कमीशनर से लेकर चुने हुए नुमांइदे तक हम सब लोगों के लिए जरूरी है। मैंने कैथल में कई मीटिंग्ज की हैं, मैंने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर दिया है कि नरेगा स्कीम एक नई स्कीम है इसको गलने मत दो। इसका प्रयोग ठीक करो। गांव में कहीं कहीं समस्या भी है इनका पर पर्सन क्वानटम आफ वर्क जो इसमें दर्शाया गया है उसमें जैसे कई बार रजबाहों की सफाई करने का, नहरों की खुदाई करने का काम है उसमें जितनी मिट्टी हम चाहते हैं उतनी मिट्टी शायद खोद नहीं पाते। विशेषकर जो बुजुर्ग लोग हैं वे यह मिट्टी खोदने का काम नहीं कर पाते। उसमें समस्या है उसकी अभी से मोनीटरिंग करनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा आदमियों को रोजगार मिले, काम भी हो सके क्योंकि इसका पैसा तो भारत सरकार से मिलता है ताकि हमारे गांवों में जो व्यवस्था है चाहे, सफाई की है, चाहे जोहड़ की खुदाई की है, चाहे गलियों और रास्तों में मिट्टी डालने की है उसमें भी इजाफा हो सके। गांवों के अंदर से जो रजबाहे निकलते हैं उनकी भी सफाई होनी चाहिए। मैंने देखा है जब यह सरकार बनी थी उस समय सारे रजबाहे अटे पड़े थे। मैं ओन ओथ कह सकता हूं कि पिछली सरकार के समय में मेरे हल्के की किसी टेल पर भी पानी नहीं पहुंचता था। लेकिन इस सरकार के बनते ही रजबाहों की सफाई करवाई गई। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं स्वयं रात को रजबाहों पर जाकर देखता था कि टेल बराबर है कि नहीं है और अधिकारियों को भी लेकर जाता था। मुझे खुशी है कि आज हमारी सारी टेल्ज पूरी हैं और उन तक पानी जाता है। सभापति महोदय, सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय सिंह जी बैठे हुए हैं। मैंने इनको कहा था कि देखिये आप पानी की चोरी रोकने के लिए बराबर इंतजाम कीजिए। अपना स्टाफ रखिये क्योंकि जब भी पुलिस मांगते हैं तो पुलिस मिलती नहीं है और पानी की चोरी होती रहती है। आपके अधिकारियों के पास जीपों की भी कमी है और जो हैं वे भी दूसरे कामों में लगी रहती है। कभी मैडीकल के काम में लगा दी जाती है, कभी तहसीलदार ले जाते हैं। आपके विभाग के पास आलरैडी व्हीकल्ज की शोर्टेज है। जब तक पानी की चोरी की जगह आपके आदमी पहुंचते हैं उससे पहले ही मोबाईल द्वारा चोरी करने वालों को मैसेज मिल जाता है और वे चले जाते हैं। इसलिए इस तरफ सरकार विशेष ध्यान दे और पानी की चोरी को रोके।

श्री सभापति : मान साहब, अब आप वाईंड अप करें।

श्री तेजेन्द्रपाल सिंह मान : सभापति महोदय, अभी मैं वाईंड अप करता हूं। सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों इस समय सदन में बैठे हुए हैं। सरकार ने एक बड़ी अम्बीसीयस योजना नहर के खालों को पक्का करने की शुरू की है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि

[श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई)]

चार इंच की खाल नहीं चलेंगी उन पर सरकार बेकार में पैसा खर्च न करे। मेरा सुझाव है कि जितनी भी खाल पक्की की जायें वे 9 इंच की बनाई जायें। इस प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा जो किसानों के काम भी आयेगा और सालों साल चलेगा भी। चार इंच की खालों को तो तोड़ने वाले लोग भी बहुत हैं और डंगर ढोर वहां से गुजरते हैं उनसे भी टूट जायेंगी कभी कामयाब नहीं होंगी। बहुत सी जगह पर तो किसान ही चार इंच की खाल बनवाने से मना कर गये। जहां-जहां हमने सोसायटीज बना रखी हैं उन्होंने कहा कि चौधरी साहब यदि चार इंच की दीवार से खाल पक्की करनी है तो हमारी खाल पक्की मत करवायें। हम तो ऐसे ही काम चला लेंगे। इसलिए मैं मंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा कि चाहे 100 प्रतिशत खालों को पक्का करने के बजाय आप 50 प्रतिशत खालों को ही पक्का करवा दें लेकिन करवायें 9 इंच की दीवार बनाकर ताकि वे टूटें ना और किसानों को भी पूरा फायदा मिले।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : सभापति महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि अब हम 9 इंच की दीवार ही बनवाते हैं।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : कैप्टन साहब, आप काडा में तो 9 इंच की दीवार बना रहे हैं लेकिन जो पुराने खाल हैं उनको तो चार इंच की दीवार से ही पक्का किया जा रहा है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : जो पुराने खाल 80 प्रतिशत तक टूट गये हैं उनको अब 9 इंच का ही बना रहे हैं।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : कैप्टन साहब, मेरे हल्के में तो पुराने खाल पूरे के पूरे ही टूटे पड़े हैं। मेरी हजूर आपसे प्रार्थना है कि आप इनके डिजाईन चेंज कीजिएगा और 9 इंच की दीवार बनवायें तभी काम चलेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : मान साहब, इसको हम एग्जामिन करवा लेंगे।

श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान : सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है कि सरकार गांवों को डिवैल्प कर रही है। बहुत ज्यादा पैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी गांवों के विकास के लिए दे रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा पैसा गांवों में कभी आते नहीं देखा। इस समय गांव के हर कोने और हर जगह पर पैसा ही पैसा लग रहा है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शहरों में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि सचिवालय बना दिए और एक छत के नीचे बहुत से दफ्तर आ गये जिससे आम जनता को बहुत सहूलियतें मिली हैं। गांवों में जो भी इन्फ्रास्ट्रैक्चर सरकार बनाये। चाहें आंगनवाड़ी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाये, चाहे पंचायत घर बनाये और चाहे पटवार घर बनवाये वे सभी एक ही कम्पाउंड में बनने चाहिएं। गांवों में जो पंचायत की जमीन है उसमें दो एकड़ की एक बाउंड्री बना देनी चाहिए जिसमें ये सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि आसानी से मोनीटरिंग भी हो सके। अब तो पता ही नहीं चलता की पटवारी जी कहां बैठते हैं। बहुत से गांवों में तो पटवारी बैठते ही नहीं हैं, वे तहसील आफिस में बैठते हैं। सरपंच जो हैं उनके पास इतनी बेगार हैं, इतना काम है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं इनके नोटिस में मैं यह बात लाना चाहूंगा कि पंचायतों पर एक 10 प्रतिशत का टैक्स बी०डी०ओज० ऐसा लगाते हैं कि यह पैसा तो रैडक्रास के लिए चाहिए और कभी कहते हैं कि ब्लॉक के खर्चे के लिए चाहिए। ये लोग पंचायत के पैसे को हराम का समझते हैं कि भई पंचायत का पैसा तो सारों का जीमणा करने के लिए है। कुछ तो सरपंच महोदय ऐसा करते हैं, कुछ ये स्टाफ वाले करते हैं। मैं कहता हूं कि यदि उनका कोई खर्चा है तो वह खर्चा सरकार अपने

बजट में से दे। बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास खर्चा नहीं होता उनको भी सरकार देती है। रैडक्रास के नाम से जो पैसा लिया जाता है उसका कोई हिसाब नहीं ले सकता। जो डी०सीज० हैं हमने कई बार अखबारों में पढ़ा है कि कोई कार खरीद रहा है, कोई मोबाईल खरीद रहा है और कोई कुछ 1700 बजे और खरीद रहा है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं उस पैसे की मॉनीटरिंग होनी चाहिए। यह ठीक है कि गरीबों की आड़ में बहुत ज्यादा धन इकट्ठा किया जाता है लेकिन उसका दुरूपयोग भी होता है। सरकार के लैवल पर इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सभापति महोदय, सरकार की एक स्कीम है जिसमें जिन गांवों में हरिजनों की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा हो उन्हें 50-50 लाख रुपये सरकार की तरफ से दिये जाते हैं। मेरे हल्के के दो गांव रावणहेड़ा और मंडवाल हैं इन दोनों गांवों में हरिजनों की आबादी 70, 80 और 90 फीसदी तक है। इन दोनों गांवों में यह पैसा अभी तक भी प्राप्त नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस पैसे को सरकार की घोषणा के अनुसार जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के आदेश सम्बंधित अधिकारियों को देने का कष्ट करें। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में गांवों की सफाई के लिए 11 हज़ार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करके एक बहुत ही बड़ा सराहनीय काम किया है इससे गांवों की सफाई में एक बड़ा भारी रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। सभापति महोदय, जब मैं गांवों में जाता हूं तो मुझे यह महसूस होता है कि हमें उनकी नफरी को 50 प्रतिशत या कम से कम 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ाना पड़ेगा ताकि गांवों की सफाई भी शहरों की तर्ज़ पर हो सके। सभापति महोदय, जब मैं पहली बार विधायक बना था तो मैंने अपने हल्के में कुल 5 पी०एच०सीज़० में से दो की बिल्डिंग बनवाई थी और तीन पी०एच०सीज़० को पंचायत घरों में शुरू करवाया था। इस बात का मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैं 10 साल के बाद पुन: जनता का नुमाइंदा बनकर आया तो मैंने देखा कि वे पंचायत घर गिर चुके हैं और उनमें पी०एच०सीज़० वैसे की वैसे ही चल रही हैं। सभापति महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरे हल्के के करोड़ा गांव में आये थे तब इन्होंने आदेश दिए थे कि ये पी०एच०सीज़० जो पंचायत घरों में चल रही हैं इनकी बिल्डिंग बनेगी। सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि इनके आदेशानुसार ये तीनों बिल्डिंग बननी शुरू हो चुकी हैं और निकट भविष्य में जल्दी ही बनकर तैयार हो जायेंगी। सभापति महोदय, इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हल्के में 6 नये पावर सब-स्टेशंज बनवा दिये हैं और इसके अलावा चार अन्य सब-स्टेशंज जिन्हें मैंने 10 साल पहले बनवाया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन सभी की कैपेसिटी बढ़ाकर डबल और ट्रिपल कर दी है। इसके साथ-साथ बिजली की लाईनें भी बदली जा रही हैं और सेग्रीगेशन हो रही है। बिजली से सम्बंधित सारे काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं और मैं एज़ ए नुमाइंदा टोटली सटीसफाईड हूं कि मेरे हल्के में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैवेल्पमैंट बिजली का है, नहरों का है, सड़कों का है उसमें हमने बहुत ज्यादा तरमीम की है और उसकी बेहतरी के लिए सरकार के लैवल पर बहुत अच्छा प्रयास किया गया है और किया जा रहा है। मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहूंगा कि इसमें हमें कहीं न कहीं क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं स्वयं भी सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी गतिविधियों में हिस्सा लेता हूं। सभापति महोदय, आप मुझे बार-बार वाईंड अप करने के लिए कह रहे हैं और मैं अपने पड़ोसियों की तरह भी नहीं हूं कि मना करने के बावजूद भी खड़ा रहूं। सभापति महोदय, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि जो कुछ भी मैंने कहा है मुझे उम्मीद है कि आप उस पर अवश्य ध्यान देंगे। सभापति महोदय, सरकार द्वारा पेश किया गया मौजूदा बजट बहुत बढ़िया है। सभापति महोदय,

[श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान (पाई)]

आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं एक छोटी बात मैं और कहना चाहूंगा सोशल वैलफेयर और चाईल्ड डैवेल्पमैंट डिपार्टमैंट बहुत गरीबों के कल्याण के लिए है। हम जब भी यह सुनते हैं कि यह शादी का पैसा, यह शगुन योजना या किसी अन्य योजना का पैसा, ये एक लाख रुपया उनके इंश्योरैंस का है। इसके लिए जिन स्थानीय कर्मचारियों की ड्यूटी होती है वे लोगों को यह कहते रहते हैं कि फण्ड अभी आये नहीं हैं और गरीब आदमियों को वे बार-बार घुमाते रहते हैं। Obviously for their own things. इसका कोई रिवॉलविंग फण्ड करके इन सारे महकमों को जिला हैडक्वाटर पर एक छत के नीचे कर दिया जाना चाहिए ताकि गरीब आदमी को यह पता हो कि अमुक महकमा यहां पर है। इस बात की हमें ही जानकारी नहीं हो पाती कि कौन सा पैसा किस डिपार्टमैंट के ऑफिस से मिलेगा। अगर ये सभी विभाग एक ही जगह होंगे तो जरूरतमंद गरीब आदमी को अगर एक जगह से उसका पैसा नहीं मिलेगा तो वह दूसरी जगह चला जायेगा। सभापति महोदय, यह सुझाव मैंने पहले भी दिया था आज के समय में यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस पर जरूर ध्यान दें और जो गरीब आदमी के पास पैसा पहुंचने वाला है उसकी ज्यादा से ज्यादा एक महीने के अन्दर-अन्दर डिस्बर्समैंट सुनिश्चित करवाने के आदेश देने की कृपा करें तभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप गरीब लोगों को वांछित लाभ मिल सकेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय प्रदान किया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय सचिव (डॉ० कृष्णा पण्डित) : आदरणीय चेयरमैन सर, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय प्रदान किया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। सबसे पहले मैं आपसे और इस सदन से एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे इस महान सदन में एक मोटो लिखा हुआ है इसमें यह लिखा है कि "One must not enter an Assembly Hall or he must speak here with all the righteousness, for one who does not speak or one who speaks falsely does involve himself in the equal sin." सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभापति महोदय, सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता जी के निधन पर मैं उनको श्रद्धांजली देती हूँ क्योंकि उन्होंने जो उसूल हमारे सामने छोड़े और जो कुछ उन्होंने हमें सिखाया वह एक बहुत बड़ी बात है। आज हम जिन चीजों पर चलते हैं और ये सिखाना चाहते हैं कि हम किस तरीके से काम करते है और किस तरीके से हमें सदन में एक दूसरे की भागीदारी लेनी चाहिए वह एक अपने आप में बहुत बड़ा आदर्श है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी ने हमें जो बजट दिया है वह एक बहुत ही अच्छा बजट है जिसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ और मैं इस बजट का अनुमोदन करती हूँ। यह बजट एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा बजट है। जो कि हमें यह सिखाता है कि किस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी गरीबों के दिल में रहते हैं। जब हम मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं सुनकर बाहर गये तो सबने एक ही आवाज में कहा कि हमेशा ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए क्योंकि जो मुख्यमंत्री गरीबों के दिल में झांकता है गरीबों से जो दुआएं लेता है उसके लिए हर एक के दिल में बहुत इज्जत है। यहाँ खड़े होकर मेरा ये पंक्तियाँ पढ़ने का मतलब यह था कि जो इन्सान अच्छा काम करता है और यह देखता है कि हमें उसूलों पर चल कर लोगों की भलाई करनी है। जिस पद पर वे बैठे हैं तो हम चाहे किसी भी पार्टी के हों तो हमें पब्लिक को बताना चाहिए कि ये-ये अच्छे काम हुए हैं क्योंकि

यहाँ पर जितने भी नुमाइंदे हैं वे सब पब्लिक के नुमाइंदे हैं और उनकी जो नुमाइंदगी करते हैं वह इसलिए करते हैं कि हम उनके लिए अच्छे काम करें। जो उनकी समस्याएं हैं उनको सदन में लाएं और उनको ठीक करें। जैसे कि पहले कहा गया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने हमेशा भलाई के कार्य किये हैं। मैं तो सदन की नई सदस्या होने के नाते एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पर सच्चाई बोल रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वे हमारे मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनकी तारीफ की जाये। तारीफ सिर्फ उस आदमी की होती है जो दिल जान से देश की सेवा करता है और लोगों की सेवा करता है। यह काम वही आदमी कर सकता है जिसने लोगों के बीच में बैठ कर यह सब कुछ सीखा हो। आज किसी ने अगर किसी से मातृभक्ति सीखनी है या पितृभक्ति सीखनी है और आज किसी को अपने उसूल देखने हैं तो मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से सीखें। एक डॉक्टर होने के नाते जब उनके पिता जी बीमार थे तो मैं भी उनसे मिलने गई थी। वहाँ पर एक डॉक्टरों की टीम थी तो मेरे सामने ही मुख्य मंत्री जी ने डॉक्टरों से पूछा कि यहाँ हम इनका क्या कर सकते है तो डॉक्टरों का जवाब था कि यहाँ आप इनका कुछ नहीं कर सकते सिर्फ यही रह गया है कि इनको देखो कि ये कब तक पुल ऑन कर सकते हैं तो ऐसे मुख्यमंत्री जिनका एक ही जवाब था कि अगर हम हॉस्पीटल में उनका कुछ नहीं कर सकते तो हम उनको घर ले जाते हैं ताकि वहाँ पर उनकी सेवा कर सकें। यह भाव हमें सिखाता है कि किस तरीके से हमें बुजुर्गों की बड़ों की और किस तरीके से हमें देश की सेवा करनी है। सभापति महोदय, आज मुझे जो यहाँ पर बोलने के लिए समय दिया उसी से जुड़ते हुए मैं यह कहना चाहूँगी कि श्री रणबीर सिंह हुड्डा जो एक आदर्श पेश करके गये जैसा अन्य साथियों ने भी कहा, उसके लिए हमें एक प्रतिमा या यादगार स्थापित करनी चाहिए और उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए, मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ती हूँ। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, आज हमारे हरियाणा में जितनी प्रगति हुई है और जितना कुछ हमने किया और जितना हमारे मुख्यमंत्री ने किया अगर हम यह समझें कि अकेले मुख्यमंत्री ही सब कुछ करेंगे यह गलत हैं जितने हम सदस्य इस सदन में बैठे हुए हैं, उन सबका यह फर्ज बनता है कि हम एक-एक करके उनका जो आदेश होता है, उसकी पालना करें। जिस तरीके से हरियाणा का आज विस्तार हुआ है और एक नम्बर पर आया है उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का अहम रोल है और उस बात के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज अगर हम सड़कों का हाल देखें तो बहुत अच्छा है और यदि पब्लिक हैल्थ की हालत देखें तो हर जगह पर सीवरेज बिछा हुआ है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर आज गौर से गरीबों को देखें तो 100-100 गज के प्लाटों के आबंटन की जो बात है यह अपने आप में एक मिसाल है। गरीब आदमी आज माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को दुआएं देता है कि ऐसी सरकार बार-बार आए ताकि हमें 100-100 गज के प्लॉट मिलें। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से यह पहली दफा हुआ है कि मिनिमम वेजिज 135 रुपये के रेट पर मिलती है जो कि अपने आप में एक मिसाल है। आज गरीब आदमी किसी जगह पर भूखा नहीं रहता और उनके घर पर रोजाना चूल्हा जलता है। जहां तक नौकरियों का सवाल है, जैसे कि कहा गया है कि सरकारी नौकरियां सभी को नहीं मिल सकती हैं लेकिन जो नरेगा के अन्दर रोजगार मिला है और नरेगा के अन्दर गरीब आदमियों को जो काम मिला है, तालाब खोदने का काम मिला है या औरतों को रोजगार मिला है यह भी एक ऐसा काम है जिसमें सब लोग आराम से अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं और 148 रुपये प्रति दिन की दर से उनको तकरीबन तीन महीने रोजगार मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। इसके लिए हम सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। आज न केवल हरियाणा बल्कि

[संसदीय सचिव (डा० कृष्णा पण्डित)]

पूरे देश में उनका नाम हुआ है और लोग चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री का काम है किस तरह से उसको बढ़ावा दिया जाए। स्पीकर सर, आज आप खेलों में देखें, एजूकेशन में देखें आज जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वे सड़कों और हैल्थ के बारे में आते हैं, मैं यह कहना चाहूंगी कि हैल्थ के मामले में जिस तरीके से विस्तार हुआ है और जिस तरीके से हमने इतने डॉक्टरों की भर्ती की है कि साढ़े पांच सौ से लेकर साढ़े सात सौ डॉक्टर्ज की भर्ती कर रहे हैं और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्पैशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं। जैसे आज सुबह भी यह सवाल आया था कि करनाल में हमारी मशीन पड़ी हुई थी जैसे मेरी बहिन सुमिता सिंह जी ने बताया था कि यह मशीन पड़ी हुई है यह चालू क्यों नहीं हो पाई उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत यह थी कि उसके लिए हमारे पास स्पैशलिस्ट्स नहीं थे। ब्लड ऐनालाईजर ऐसे स्पैशलिस्ट्स हैं जो केवल ब्लड बैंकों में काम करते हैं और वह जानते हैं कि हम ऐनालाईजर को कैसे यूज कर सकते हैं। उनके न होने की वजह से भी उस मशीन के चलने में डिले हुई। जैसे ही मशीन का स्पैशलिस्ट मिलेगा उसका काम शुरू हो जाएगा। स्पीकर सर, इस तरीके से हमारा एम०आर०आई० है वह सबसे पहले गुड़गांव में लगा। बड़े सस्ते रेट में 750 रुपये से लेकर 1200 रुपये में हर गरीब आदमी को उसकी सुविधा मिल सकती है। इसी तरह से जो कैंसर की दवाइयां हैं उनमें से कुछ दवाइयां तो ऐसी है जो कि मिलती हैं जैसे कि मेरे भाईयों ने क्वैश्चन उठाया लेकिन कुछ दवाइयां जैसे कि कीमोथैरैपी की मैडिसन्ज़ हैं जो कि बहुत महंगी हैं इस बारे में गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया की भी ऑलरैडी एक मीटिंग हुई है उस मीटिंग में हमने मिस्टर पासवान जी को भी कहा था कि ये दवाइयां उसमें एण्टर होनी चाहिएं और कुछ दवाइयां बहुत महंगी हैं। स्टैपटोगायने, 60 एन०टी०डी० हैं ये सारे इंजैक्शन्ज़ 3200 रुपये और 3500 रुपये के बीच में आते हैं उनको भी बीच में ऐड करवा दिया गया है। सबसे बड़ी चीज जो हरियाणा में मुख्यमन्त्री जी के आदेश से हुई है कि पहली तारीख से हमने सारी दवाइयां फ्री देनी शुरू कर दी हैं और एम०आई०आर० और एम०एम०आर० का रेट घटाने के लिए सबसे बड़ा योगदान मिला है। इंस्टीच्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए 500 रुपये पहले तीन महीने में, 500 रुपये बीच वाले में और 500 रुपये लास्ट वाले तीन महीनों में तथा 700 रुपये बच्चे और मां की देखभाल के लिए यानी 2200 रुपये दिये जाते हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। 2200 रुपये जो दिये गये हैं वह इसलिए दिये गये हैं ताकि हरेक गरीब आदमी अच्छी तरह से डिलीवरी करवा सके और बच्चा और मां दोनों बिल्कुल स्वस्थ हों। सभी जगहों पर जहां भी हमारे सीएचसीज़ हैं उनमें हमने पांच डॉक्टरों की नियुक्ति की है इसमें गायनोकोलोजिस्ट पिडीट्रिशियन, फिजीशियन, आर्थोपिडिक्स सर्जन और ऐनेस्थीसिस्ट इसलिए नियुक्त किये हैं ताकि सारी सुविधाएं वहीं पर मिलें। पांच ट्रॉमा सैंटर्ज में भी न्यूरोसर्जन के इन्तजाम भी किये जाएंगे और ट्रॉमा सैंटर्ज की वर्किंग शुरू हो जाएगी ताकि हम सरकार के आदेशों का पालन करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन करते हुए गरीब आदमियों को सारी सुविधाएं पहुंचा सकें। स्पीकर सर, आज गरीब आदमी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी है कि 30 रुपये के स्मार्ट कार्ड में 30,000 रुपये का ट्रीटमैंट लोगों को मिल सकता है। वह किसी भी रिकेग्नाईजड गवर्नमैंट अस्पताल में जा कर 30 हजार रुपये का फायदा ले सकते हैं। यह काम वही इन्सान कर सकता है जो गरीबों के बीच में रह कर गरीबों के दिलों में झांकता है और यह जानता है कि मुझे गरीबी को दूर करना है। इसी तरह से सारे डॉक्टरों को भी आदेश किये गये हैं और पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है यह मैं अपने भाईयों को कहना चाहूंगी। इंदौरा साहब हमारे भाई भी हैं और वे इस बात की तारीफ भी करते हैं। वे बहुत अच्छे इन्सान हैं और कहते हैं कि जो अच्छे काम किये हैं कि जिस तरीके से सारी दवाइयां और सारी चीजें

मिल रही हैं यह अपने आप में एक महान उपलब्धि है। गरीब आदमी के दिल में सुख शांति हो और हम उनको सारी मूलभूत सुविधाएं दे सकें। हमारे सरकारी अस्पतालों में हरेक ऑपरेशन और सभी चीजें बिल्कुल फ्री हैं और उनको हरेक तरह का पैकेज दिया जाता है। उससे ज्यादा पारदर्शिता यह है कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि जो हमारी फाईलें बनीं हैं उसके एक पैकेज में लास्ट पेज पर लिख गया है कि पेशैंट यह लिख कर जाएगा कि डॉक्टर ने कैसा ट्रीटमैंट किया। उसका ट्रीटमैंट ठीक था कि नहीं था, नर्सिज़ ने ठीक से काम किया कि नहीं किया, दवाई मिली की नहीं मिली। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरे बिजली की सुविधा मिलना, बाल विकास का काम, नारी उत्थान का काम है, आज हर चीज सबको मिल रही है। हरेक एम०एल०ए० अपने एरिया का मुख्यमंत्री है। वह जिस किसी मंत्री को अपने हल्के का काम करने के लिए कहता है तो उसका हर काम पूरा होता है। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी और चौधरी बीरेन्द्र सिंह फाईनांस मिनिस्टर जी बहुत दरियादिल और अच्छे इन्सान हैं और उनके पास जब भी किसी काम से जाएं तो वे कभी भी न नहीं करते हैं, खास करके फाईनांस से रिलेटिड हो, उसको ये बहुत जल्दी मानते हैं। स्पीकर सर, आज डॉक्टरों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उनको हमेशा डर लगा रहता है कि वे कोई भी काम करें, उसमें कोई गड़बड़ी न खड़ी हो जाए। यह जो एट्रोसिटी ऑफ डॉक्टर्ज थी जिसके बारे में मैंने सी०एम० साहब से भी बात की थी और फाईनांस मिनिस्टर साहब से भी बात की थी। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से इस बारे में फिर से गुजारिश है कि अगर सरकार डाक्टर्ज की सुविधाओं का ध्यान रखेगी, तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्ज हमारे यहां पर आकर नौकरी करेंगे और इससे गरीब आदमियों को फायदा होगा तथा उनको अच्छी सुविधा मिलेगी। स्पीकर सर, मैं इन सारी बातों के साथ मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और साथ ही आपका भी धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री ईश्वर सिंह पलाका (रादौर एस०सी०) : स्पीकर सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय वित्त मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने पेश किया है। मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। (विघ्न) स्पीकर सर, इस बजट में कहीं पर भी यह नहीं दर्शाया गया है कि हम कितने लोगों को रोजगार देंगे। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार युवा साथी बहुत ही ध्यान से सरकार की नीतियों को पढ़ते हैं कि सरकार ने बजट में रोजगार के कोई नए अवसर जुटाए हैं या नहीं। स्पीकर सर, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो औद्योगिक सुरक्षा बल में और अन्य विभागों में युवक लगाए थे उनको हटाने का काम किया और बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया। स्पीकर सर, इस सरकार के आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी यह कहते थे कि हमारी सरकार सत्ता में जब आएगी तो हम बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। स्पीकर सर, बेराजेगारी खत्म होने की बजाय बढ़ी है। स्पीकर सर, इम्पलायमैंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवाने के लिए बहुत लम्बी लम्बी लाईनें लगी रहती हैं। बल्कि कई बच्चों को तो यह कह दिया जाता है कि कल आना या दो दिन बाद आना, आपका नाम तब दर्ज किया जाएगा। आज बेरोजगार बच्चे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए भटकते रहते हैं। लेकिन कई कई दिन बाद उनका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज किया जाता है। स्पीकर साहब, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि आठ लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को पानी के कनैक्शंज दे दिए और कभी कुछ और कह देते हैं। स्पीकर साहब, 200 लीटर की टंकी पानी के लिए उनको दी जाती है लेकिन जिसका भी थोड़ा बड़ा परिवार होता है उसका 200 लीटर की टंकी में काम नहीं चलता है। 200 लीटर की यह टंकी भी कई बार खाली ही रह जाती है क्योंकि बिजली ही नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष : आप यह बताएं कि 200 लीटर में कितनी बाल्टी पानी होता है ?

श्री ईश्वर सिंह पलाका : सर, इस तरह से दलित लोगों को इस तरह की पानी की टंकी देकर बिलोया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उनको तो अच्छे रोजगार की जरूरत है लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : पलाका जी, लेकिन भारद्वाज जी का तो कहना है कि पीने का पानी देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

डा० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर साहब, अगर हरियाणा के किसी भी कस्बे में मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी तो विकास नहीं होगा इसलिए हमारी सरकार की प्रथम प्राथमिकता शुद्ध जल देने की होनी चाहिए, दूसरी प्राथमिकता हर घर में स्वच्छ शौचालय प्रदान करने की होनी चाहिए और तीसरी प्राथमिकता हर बच्चे को शिक्षा देने की होनी चाहिए। जैसी नयी घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गयी हैं जिस तरह से बेरोजगारों को भत्ते की सुविधा दी गयी है वह अच्छी बात है।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर साहब, बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की बात कही गयी है। 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता तो कुछ भी नहीं है। 500 रुपये में हमारे बेरोजगार साथी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अगर उनको कुछ देना ही है तो कम से कम उनको 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दो।(विघ्न)

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर साहब, जब इनकी सरकार थी तो उस वक्त तो केवल 100 रुपये ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था इसलिए अब तो इनको इसकी सराहना करनी चाहिए।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर साहब, उस वक्त दो रुपये में कॉपी आ जाती थी जबकि आज बीस रुपये में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कॉपी आती है। स्पीकर साहब, इसी तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को प्लॉट्स देने की बात कही गयी है। प्लॉट्स देने के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि पंचायतों की जमीन में से कभी भी सरपंच प्लॉट काट सकते हैं इसलिए इस बारे में वाहवाही लूटने की बात नहीं है। इन प्लॉट्स पर उनसे दो सालों में मकान बनाने के लिए कहा जा रहा है लेकिन वे गरीब आदमी दो सालों में मकान कैसे बना लेंगे। अच्छा तो यह होता कि इन प्लॉट्स पर मकान बनाकर इन गरीब लोगों को दिए जाते।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, इंदिरा आवास योजना में 50 हजार रुपये उनको मकान बनाने के लिए दिए जा रहे हैं।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर साहब, जैसे डॉक्टर सीता राम जी ने कहा कि जोहड़ की जरूरत नहीं हैं जहां पर आलरेडी दो-दो जोहड़ हैं वहां पर भी इन पर पैसा खर्च किया जा रहा है। सारे परिवार के लोग इस काम में लगे रहते हैं इसलिए मुश्किल से उनके हिस्से में 13-13 रुपये आते हैं। जहां तक इनको काम देने की बात है काम तो इनको पूज्यनीय चौधरी देवीलाल जी ने 1977 में दिया था जब उन्होंने काम के बदले अनाज योजना की शुरूआत की थी। उस समय इस योजना के तहत गरीब आदमी को खाने के लिए अनाज भी मिलता था। (विघ्न) उस वक्त घटिया नहीं बल्कि बढ़िया गेंहू दिया जाता था। इस तरह से अब इन गरीब लोगों के नाम पर बड़ा भारी बजट का गोलमाल किया जा रहा है। स्पीकर साहब, इसी तरह से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की जहां तक

बात है, सरकार को यह करना चाहिए था कि केन्द्र सरकार की तर्ज पर इसको प्राथमिकता के आधार पर लागू करती और कर्मचारियों को राहत प्रदान करती लेकिन सरकार ने यह सारा मामला ही गोलमाल कर दिया है क्योंकि सरकार ने इस बारे में एक कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी कब निर्णय लेगी, क्या करेगी कुछ पता नहीं है। यह तो वह बात कर दी (विघ्न) स्पीकर सर, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके सरकार ने कर्मचारियों को आपस में लड़ा दिया है। किसी को जूनियर कर दिया, किसी को सीनियर कर दिया। आज कर्मचारी कहते हैं कि ये मेरे से जूनियर है ये मेरे से सीनियर है। मेरे को इससे कम वेतन मिल रहा है। स्पीकर सर, पी०टी०आई० और कला अध्यापक जो बच्चों के लिए बेचारे बहुत मेहनत करते हैं उनको भी इसमें न के बराबर राहत दी गई है। मेरा यह निवेदन है कि सरकार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय उनको भी पूरा मान सम्मान दे। स्पीकर सर, जहां पैंशन के बारे में मेरे साथियों ने बड़े लम्बे चौड़े दावे किए कि हमने पैंशन बढ़ाई। अच्छी बात है, पैंशन बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : पलाका जी, आप पैंशन कितनी बढ़वाना चाहते हो।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : सर, खजाने में पैसे की कमी नहीं है आप एक हजार रुपये पैंशन कर दें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : एक हजार रुपये से ऊपर कर देंगे तो पार्टी छोड़ दोगे। आप सौ रुपये, दो सौ रुपये और तीन सौ रुपये पैंशन देते हो और हमें कहते हो कि एक हजार रुपये कर दो।.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये 300 रुपये पैंशन देने की घोषणा करके चले गए। पैसे इन्होंने नहीं दिये। हमने दिये और वह भी विद एरियर दिए। इन्होंने यह भी कह दिया कि सौ रुपये सालाना बढ़ाएंगे।

श्री अरजन सिंह : स्पीकर सर, ये तो पैंशन के पैसे को इकट्ठा करके तारबड़ी में धरते थे। (विघ्न)

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर, एक आदमी 10 लाख की कार लेने जाता है तो बैंक द्वारा उसको लोन देने पर उसकी तो कार ही प्लैज की जाती है उसकी जमीन प्लैज नहीं की जाती है लेकिन जब किसान बैंक के पास ट्रैक्टर के लिए लोन लेने के लिए जाता है तो उसकी जमीन प्लैज की जाती है। जमीन प्लैज करने का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये मेरा सुझाव है ताकि किसान को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : जब तुम्हारा राज था तब क्या चक्की चलाया करते थे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पहले छह एकड़ जमीन प्लैज करते थे अब तो हमने एक एकड़ का प्रावधान कर दिया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : पलाका जी, आप कंक्लूड करें।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। हाउस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2009-2010 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा कि आज के दिन स्कूलों में टीचर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में पहले ही डिटेल में बात आ चुकी है।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी शिक्षा बहुत ही जरूरी है। उससे ही बच्चों का भविष्य बनता है। (विघ्न) ऐजूसेट लगा दिया उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। उसमें बहुत बड़ा गोलमाल किया गया है। मंत्री जी, इस मामले की जांच कराएं। सर्वशिक्षा अभियान में बहुत गोलमाल किया गया है।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि कौन सा गोलमाल हुआ है और कब हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : पलाका जी अब आप, कंक्लूड करें।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के बारे में भी हर बार कहा जाता है कि एक हजार नयी बसें खरीदी गई हैं। गाँवों में जहां दो-दो बसें जाती थी आज वहां पर एक भी बस नहीं जाती। गाँवों से जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं वे या तो किसी के मोटरसाईकल को हाथ देकर उस पर बैठ कर जाते हैं या फिर पैदल चलकर जाते हैं। वहां पर नई बसें लगाकर उन बच्चों को राहत प्रदान की जाए। आज के जमाने में लोगों के पास एक-एक बच्चा है और वह भी बस की छत पर चढ़कर पढ़ने जाये तो वह कितना रिस्की काम है। इसलिए सरकार को स्टुडैंट्स के लिए स्पेशल बसें चलानी चाहिएं ताकि वे अपनी शिक्षा अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें और उन परिवारों को राहत मिल सके। लड़कियों के लिए जो बेचारी गाँवों से पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज में जाती हैं उनके लिए भी बसों का प्रावधान किया जाए। मंत्री जी से मेरी यह प्रार्थना है। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

Mr. Speaker: Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 17th February, 2009.

*18.31 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 17th February, 2009.)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh